

• 60 फीसदी थानों में महिला शौचालय नहीं • मप्र के 20 जिलों में लगाई कटाई पर रोक

In Pursuit of Truth

प्राक्षिक
अक्ष

www.akshnews.com



आत्मनिर्भर मप्र पर आधारित बजट

वर्ष 19, अंक-10

16 से 28 फरवरी 2021

पृष्ठ-48

मूल्य 25 रुपये

प्राकृतिक आपदाएं खलनायक कौन?





Anu Sales Corporation

*We Deal in
Pathology & Medical
Equipments*

**Add: Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023**

M. : 9329556524, 9329556530

E-mail : ascbhopal@gmail.com

मनरेगा

9

मनरेगा मजबूरी नहीं जरूरी

दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार की गारंटी देने वाली योजना मनरेगा में अब तक का रिकॉर्ड बजट मुहैया कराया गया है। इससे शहरों से पलायन करके गांवों में पहुंचे लोगों को रोजगार मिल रहा है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी...

राजपथ

10-11

जीत का मंत्र

बीते विधानसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए मप्र भाजपा अभी से अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। इसके लिए भाजपा ऐसी रणनीति बना रही है, जिससे कि 2023 तक प्रदेश से कांग्रेस का पूरी तरह...

योजना

12

विवादों में अटल प्रोग्रेस-वे

केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अटल प्रोग्रेस-वे विवादों में पड़ता जा रहा है। सबसे बड़ा विवाद जमीनों के अधिग्रहण को लेकर है। विवाद की वजह है अधिकारियों द्वारा मनमानी घोषणाएं। दरअसल, योजना को जैसे ही सरकार...

मप्र भाजपा

14

अपनी डफली अपना राग

राजनीति के वियाबान में अपनी-अपनी मंजिल की तलाश कर रहे भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा अब अपनी डफली और अपना राग छोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि प्रदेश में डेढ़ दशक से अधिक समय से सरकार रहने के बाद अब इन नेताओं को राजधानी भोपाल और उसके आसपास के इलाकों...



हिमालय में हुई त्रासदी के लिए अकेले प्रकृति ही जिम्मेदार नहीं है। इसे प्राकृतिक आपदा कहना सच्चाई से मुंह मोड़ना है। वास्तव में निरंकुश और लापरवाह तरीके से किए गए विकास के चलते हमने हिमालय क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। इससे भी बड़ा खतरा यह उत्पन्न हो गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के चलते यह अधिक खतरे वाला क्षेत्र बन गया है। वैज्ञानिकों ने भी इस तरह की वर्षा की घटनाओं में बढ़ोतरी की आशंका जाहिर की है।

13



राजनीति

30-31

जनता के भरोसे जोखिम

किसी भी नेता की राजनीतिक पूंजी उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। नेता इसका इस्तेमाल बड़ी किफायत से करते हैं और इसके प्रति सजग रहते हैं कि इसमें कमी न होने पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास राजनीतिक पूंजी बहुत ज्यादा है, पर वह इसका इस्तेमाल बड़ी दरियादिली से करते...

राजस्थान

35

वसुंधरा की बाजीगरी

राजस्थान में करीब तीन साल बाद यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन, इसके सियासी बुलबुले निकलने शुरू हो गए हैं। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के समर्थकों ने हाल में नया मंच बना डाला जिससे संकेत मिलता है कि...

उप्र

37

आंसू बने संजीवनी

उप्र के पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपना अस्तित्व खो चुकी राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) को किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आंसू संजीवनी बन गए हैं। उन्हें उम्मीद जगी है कि वे...

6-7 अंदर की बात

41 महिला जगत

42 अध्यात्म

43 कहानी

44 खेल

45 फिल्म

46 व्यंग्य



खंडहर होकर अपने भाग्य पर रो रहे शहर

शा यर और गीतकार साहिर लुधियानवी ने ताजमहल के लिए लिखा था...

**इक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर
हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक।**

वर्तमान समय में देश में बन रही 100 स्मार्ट सिटी के बारे में भी उपरोक्त पंक्तियां कुछ हद तक सही हैं। क्योंकि मद्रास की राजधानी भोपाल, व्यावसायिक राजधानी इंदौर सहित देशभर में बन रही स्मार्ट सिटी की कहानी भी कुछ वैसी ही है। सरकारी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अफसरों ने बसे-बसाए क्षेत्र को उजाड़कर स्मार्ट सिटी बनाने का जो अड़ियल रुख अपनाया है, उससे लगभग सभी शहर के वे भू-भाग खंडहर होकर अपने भाग्य पर रो रहे हैं। अगर भोपाल की बात करें तो यहां स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर के सबसे अच्छी बसाहट और हरियाली वाले क्षेत्र को उजाड़कर सरकारी महत्वाकांक्षा पूरी करने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश के कारण आज पूरा क्षेत्र खंडहर, मलबा में तब्दील हो गया है। दरअसल, स्मार्ट सिटी निर्माण का कार्य योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया गया है। अफसरों ने 300 एकड़ में व्यवस्थित बसाहट को तोड़कर योजना को साकार करने का असफल प्रयास किया है। गौरतलब है कि देश और प्रदेश में आजादी के बाद कई बड़ी परियोजनाओं को साकार किया गया है, वह भी बिना तोड़फोड़ के। भोपाल में बीएचईएल इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने इस महत्वाकांक्षी योजना को इतने व्यवस्थित तरीके से साकार करवाया कि आज भी यह सुव्यवस्थित है। ऐसी न जाने कितनी योजनाएं-परियोजनाएं योजनाबद्ध तरीके से स्थापित की गई हैं, जिनके कारण किसी भी तरह की न तो तोड़फोड़ की गई, न ही बसाहट को उजाड़ा गया। वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी के नाम पर अरबों रुपए स्वाहा किए जा रहे हैं, जबकि इसका कोई औचित्य ही नहीं था। यह सही है कि हमारी कुल आबादी का महज 31 फीसदी हिस्सा शहरों में निवास करता है, लेकिन भारत की कुल जीडीपी का तकरीबन 65 फीसदी हिस्सा इन्हीं से आता है। माना जा रहा है कि अगले 15 वर्षों में शहरों से हमारी कुल जीडीपी की तकरीबन 75 फीसदी आय अर्जित होगी। इससे पता चलता है कि भविष्य के हमारे आर्थिक विकास के लिए शहरों का कितना अधिक महत्व है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य बनाया है। लेकिन इसके लिए जिस तरह बसे-बसाए क्षेत्र को उजाड़ा जा रहा है, वह चिंतनीय है। यहां पर विचार करना आवश्यक है कि आखिर स्मार्ट सिटी का वास्तविक आशय क्या है? इस पर तमाम तरह के विचार हैं। जहां कुछ लोग सूचना और संचार तकनीक की मजबूत भूमिका की वकालत कर रहे हैं तो अन्य लोग इसके टिकाऊ होने के पहलू की चर्चा कर रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से कुशलता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं तो कुछ अन्य समावेशी विकास की बात कह रहे हैं ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। इसी तरह कुछ लोग हर समय सेवाओं की उपलब्धता पर जोर दे रहे हैं तो कुछ लोग सेवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देने को कह रहे हैं। एक स्मार्ट सिटी में तमाम विशेषताएं होनी भी चाहिए। लेकिन जिस देश में बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचारी जैसी समस्याएं हैं, वहां स्मार्ट सिटी से पहले इन समस्याओं को खत्म करने की प्राथमिकता होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी बनाकर बेरोजगार, गरीब और भ्रष्ट लोगों के साथ क्या मजाक नहीं किया जा रहा है।

- राजेन्द्र आगाल

आक्षर

वर्ष 19, अंक 10, पृष्ठ-48, 16 से 28 फरवरी, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :

प्लॉट नम्बर 150, जेन-1 मनोरमा कॉम्प्लेक्स,

एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर

भोपाल- 462011 (म.प्र.),

फोन नं. 0755-2557777, टेलीफैक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com

Website : www.akshnews.com

RNI NO. HIN/2002/8718

MPHPL/642/2021-23

ब्यूरो

मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, कोलकाता:- इंद्रकुमार,

जयपुर:- आर.के. बिनानी, छत्तीसगढ़:- संजय शुक्ला,

मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, लखनऊ :- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता

094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे

098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया

094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार

098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली :- ईसी 294 माया इन्क्लेव

मायापुरी-फोन : 9811017939

जयपुर :- सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर

(राजस्थान) मोबाइल-09829 010331

रायपुर :- एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,

फोन : 0771 2282517

भिलाई :- नेहरू भवन के सामने, सुपेला,

रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015

इंदौर :- 39 श्रुति सिल्टर निर्माणिया, इंदौर

मोबाइल - 7000123977

स्वाधिकाारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 150, जेन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।



कुपोषण एक बड़ी समस्या

प्रदेश में कुपोषण एक बड़ी समस्या के रूप में है। कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार हर साल बजट बढ़ा रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1495 करोड़ रुपए बजट बढ़ाया गया है। अब सरकार कुपोषण से लड़ने के लिए नई नीति पर काम करेगी। मप्र में करीब 70 हजार बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं।

● दिनेश प्रजापति, भोपाल (म.प्र.)

कैसे भेंगे बिजली बिल

कांग्रेस सरकार की नीति में परिवर्तन कर आमजन की जेब ढीली करने की तैयारी पूरी हो गई है। नियामक आयोग की मंजूरी मिलते ही आम उपभोक्ताओं पर तीन गुना ज्यादा बिजली बिल का भुगतान करना होगा। मप्र में उपचुनाव जीतने के बाद से ही बिजली आम उपभोक्ताओं को झटके पर झटके दे रही है।

● लवकुश द्विवेदी, सीधी (म.प्र.)

नक्सलियों पर नजर

मप्र में बालाघाट और मंडला नक्सल प्रभावित जिले हैं, जहां पर नक्सली गतिविधियों की सूचना मिलती रहती है। नक्सलियों की हरकतों पर नजर रखने और सूचना जुटाने के लिए एक विशेष शाखा भी बनाई गई है। सरकार को नक्सलियों की हर एक मूवमेंट पर नजर रखना चाहिए।

● रोशनी सोनी, इंदौर (म.प्र.)



परेशान है किसान

ग्रामीण आय में खेती का हिस्सा करीब 40 फीसदी से भी कम है। खवाल यह है कि अगर खेती-किसानों की स्थिति इतनी बुरी है, तो देश के पूंजीपति (रईस) और उद्योगपति इसकी ओर आकर्षित क्यों हो रहे हैं? भारत कृषि प्रधान देश है। यहां खेती-किसानों में आधी से अधिक आबादी लगी हुई है, लेकिन भारत की कुल जीडीपी में इसका योगदान केवल 16 से 17 फीसदी के आसपास ही रहता है। देश में एक किसान की औसत मासिक आय भी 6,000 रुपए से अधिक नहीं हो पा रही है। यह 200 रुपए रोज की औसत दिहाड़ी है, जो कि न्यूनतम मजदूरी दर से भी बहुत कम है। हजारों किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। करीब 70 फीसदी किसान खेती के अतिरिक्त दैनिक कमाई पर निर्भर हैं।

● संतोष श्रीवास्तव, जबलपुर (म.प्र.)

ब्लिंडर का उपयोग कैसे?

जब नाए-नाए उज्वला गैस कनेक्शन हुए थे, तब अधिकतर घरों में गैस चूल्हे पर खाना बनने लगा था, लेकिन अब अधिकतर घरों में फिर से कच्चे ईंधन (लकड़ी, कंडे आदि) से चूल्हे पर ही खाना बनता दिखने लगा है। हाल यह है कि गांवों के अधिकतर घरों से सुबह-शाम फिर वही धुआं उठता है। खर्दियों में अगर देखें, तो और अधिक धुआं उठता दिखाई देता है। क्योंकि अनेक लोग खर्दी से बचाव के लिए अलाव भी तापते हैं।

● लक्ष्य शर्मा, ग्वालियर (म.प्र.)

न्यायिक प्रणाली तेजी से काम करेगी

अगर देश में पुलिस, स्कूल, अस्पतालों में लाखों बिक्रियां हैं तो इसका मतलब है कि भारतीय राज्य का अस्तित्व सिर्फ कागजों में है। आखिर ऐसे में सरकार का आकार कम करने की बात ही कहां आती है? जब सरकार सिर्फ नाममात्र के लिए हो तो उसका आकार कम करना न्यायसंगत कैसे हो सकता है? किसी के लिए भी यह बुनियादी बात समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि अगर अधिक न्यायाधीश होंगे तो हमारी न्यायिक प्रणाली तेजी से न्याय देना सुनिश्चित करेगी।

● रंजन सिंह, राजगढ़ (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल



सुशासन बाबू की उस्तादी

आखिर नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। सरकार गठन को हालांकि करीब दो महीने हो चुके हैं। इस बार के विस्तार में नीतीश भाजपा पर हिस्सेदारी के मामले में इक्कीस साबित होते दिखे हैं। कुल 17 नए मंत्रियों को शामिल करने के बाद अब मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आंकड़ा 31 हो गया है। 17 में 9 भाजपा के हैं तो सात जद(एकी) के। एक निर्दलीय को भी जद(एकी) के कोटे में ही माना जाएगा। इस विस्तार ने भाजपा के भीतर असंतोष को बढ़ाया है। इस विस्तार के साथ ही नीतीश ने भाजपा को यह जताने की कोशिश की है कि विधायक भले उनकी पार्टी के कम जीतकर आए हों पर बिहार में गठबंधन के असली बास तो वही हैं। गृह, कार्मिक, शिक्षा, ग्रामीण विकास और जल संसाधन जैसे ज्यादातर अहम मंत्रालय नीतीश ने जद(एकी) के अधीन ही रखे हैं। भाजपा के 16 मंत्रियों के पास कुल 22 विभाग हैं तो जद(एकी) के 13 मंत्रियों के पास 21। जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी को भी मंत्रिपद मिले हैं। भाजपा की रेणु देवी बेशक उपमुख्यमंत्री हैं पर विभाग तो उन्हें आपदा प्रबंधन का मिला है। विधानसभा चुनाव में जद(एकी) को 43 और भाजपा को 74 सीटें मिली थीं। एक तरफ जद(एकी) ने बिहार में अपना कद छोटा नहीं होने का संदेश दिया है।

कश्मकश में योगी

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल का विस्तार अब ज्यादा नहीं लटका पाएंगे। वहां अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव हो जाएगा। इस नाते सरकार को चुनावी नजरिए से चाक चौबंद करना चाहेंगे। वाराणसी के सांसद होने के नाते अब प्रधानमंत्री भी सियासी नजरिए से तो उप्र के ही हो गए हैं। दूसरे सूबों से कहीं ज्यादा प्रतिष्ठा उनकी उप्र से जुड़ चुकी है। अपने पूर्व सचिव एके शर्मा को उन्होंने आईएएस से इस्तीफा दिलाकर उप्र विधानपरिषद में निर्वाचित किसी रणनीति के तहत ही कराया है। चर्चा गरम है कि योगी अपने मंत्रिमंडल में आधा दर्जन नए मंत्री शामिल कर सकते हैं। पर लगता है कि उन्हें अभी तक आलाकमान से हरी झंडी नहीं मिल पाई है। विस्तार के दौरान योगी खराब कामकाज वाले अपने कुछ मंत्रियों को हटा भी सकते हैं। मिशन 2022 के मद्देनजर योगी को जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों की चिंता भी करनी होगी और अब तो किसान आंदोलन की भी चुनौती है। मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की अटकलों के बीच मंत्री पद के दावेदार भाजपा विधायकों ने भी अपनी लॉबींग तेज कर दी है।



कांग्रेस डाल-डाल, सरकार पात-पात!

कांग्रेस पार्टी को सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा हो गया है और इसके फायदे का भी अंदाजा हो गया है। पहली बार कांग्रेस ने सफलता का स्वाद भी चखा है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने, किसानों के आईटी सेल ने और बाकी स्वतंत्र नागरिकों ने कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। सो, अब कांग्रेस पार्टी ने 5 लाख साइबर वारियर्स बहाल करने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली से लेकर सभी प्रदेशों तक में सोशल मीडिया की टीम बढ़ी करेगी और साइबर वारियर्स बहाल करेगी, जो कांग्रेस की नीतियों के प्रचार के साथ साथ केंद्र और राज्य की सरकारों और भाजपा की कमियों को लोगों के सामने ले आएगी। यह संयोग है कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने साइबर वारियर्स बहाल करने का ऐलान किया, उसी दिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नए प्रोग्राम की घोषणा की, जिसमें सामान्य नागरिकों को वालंटियर के तौर पर बहाल किया जाए। ये वालंटियर सोशल मीडिया से लेकर आम जीवन में होने वाली आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगे। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये वालंटियर सरकार को देशविरोधी गतिविधियों के बारे में भी बताएंगे।

चर्चा में चिनम्मा

लंबे दौर तक जयललिता की सबसे निकट सहयोगी रही शशिकला आय से ज्यादा संपत्ति जुटाने के आरोप में चार साल कैद की सजा काटने के बाद बैंगलूरु की जेल से रिहा हुई तो कोरोना की चपेट में आ गई। आखिर बैंगलूरु से जानबूझकर चेन्नई तक का लंबा सफर उन्होंने सड़क मार्ग से तय किया। 23 घंटे के सफर के बाद चेन्नई पहुंची। रास्ते में जिस अंदाज में उनका स्वागत हुआ उससे सियासत में फिर कदम बढ़ाने का उनका अरमान हिलोरे जरूर ले रहा होगा। जयललिता के जीवित रहते जो पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी उनकी आरती उतारते थे, उन्होंने तय किया कि चिनम्मा यानी शशिकला अम्मा से जुड़े किसी भी स्थल तक न जा पाएं। पलानीस्वामी ही समझौते के तहत सूबे की अन्नाद्रमुक सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। पनीरसेल्वम ने चिनम्मा को रोकने के लिए पलानीस्वामी से हाथ मिला लिया था। लेकिन अब जिस तरह चिनम्मा का स्वागत-सत्कार हुआ है, उससे राज्य की राजनीति गरमा गई है। अब देखना यह है चिनम्मा क्या गुल खिलाती हैं।

दूसरा पहलू

उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के कारण बिजली परियोजनाओं में काम कर रहे लोग तो जरूर हताहत हुए पर आम लोग सोशल मीडिया पर हादसे की सूचना वक्त रहते प्रसारित हो जाने से संभल गए। सरकारी एजेंसियां भी समय पर सूचना मिल जाने के कारण बेहतर भूमिका अदा कर पाईं। उसी का नतीजा रहा कि मलबे में दबे और सुरंग में फंसे कुछ लोगों को तो बचाया जा सका। अन्यथा 2013 की उत्तराखंड की आपदा ने तो समूचे तंत्र को ही पंगु बना दिया था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भाग्यशाली रहे। हादसे से उनकी छवि पर बहुगुणा की तरह बट्टा नहीं लगा। सरकार और उसकी एजेंसियां सभी मुस्तैद थे तो आपदा के कारण न ज्यादा नुकसान हुआ और न ही अफरातफरी या अनिश्चितता का माहौल बना। रावत के हादसे वाली जगह पर पहुंचने का भी अच्छा संदेश गया। मुख्य भूमिका बेशक आईटीबीपी और आपदा मोचन बल के जांबाज जवानों की ही थी।

चटनी-चूरण ने बढ़ाई कड़वाहट

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक प्रमुख सचिव की हैरानी-परेशानी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल, 1996 बैच की उक्त महिला आईएएस जबसे नए विभाग में प्रमुख सचिव बनकर आई हैं, उनकी कड़वाहट विभागीय अधिकारियों पर भारी पड़ रही है। आलम यह है कि मैडम के पास कोई फाइल पहुंचने में एक-दो दिन की देरी होती है तो वे अफसरों को चक्करधिन्नी बना देती हैं। फाइल का निपटारा करने की बजाय वे अफसरों से स्पष्टीकरण मांग लेती हैं कि मेरे पास फाइल पहुंचने में इतनी देरी क्यों हुई? सूत्रों का कहना है कि इन दिनों पूरा विभाग मैडम को स्पष्टीकरण देने में ही लगा हुआ है। दरअसल, मैडम की इस कड़वाहट के पीछे की कहानी कुछ अलग है। सूत्रों का कहना है कि मैडम पहले निर्माण एजेंसी में थीं। वहां रोजाना मैडम से मिलने तरह-तरह के लोग आते थे। इससे मैडम का मन लगा रहता था। अब जबसे वे नए विभाग में आई हैं, यहां कोई आता-जाता नहीं है। दरअसल, मैडम को जो विभाग मिला है वह चटनी-चूरण वाला है। इस विभाग की पूछ-परख न के बराबर है। ऐसे में यहां मैडम से मिलने कोई आता-जाता भी नहीं है। जहां पूर्व विभाग में मैडम के यहां मिलने वालों की कतार लगी रहती थी, वहीं अब इस चटनी-चूरण वाले विभाग में इस तरह का कोई काम ही नहीं होता है। ऐसे में मैडम की कड़वाहट बढ़ती जा रही है और वे अपनी खीझ फाइलों पर निकाल रही हैं।

मैडम की मटरगश्ती

माना जाता है कि नौकरशाह हमेशा मर्यादा में रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर भी वे यह प्रदर्शित करते हैं कि उनके लिए मर्यादा ही सबकुछ है। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि नौकरशाह व्यवस्थित प्रक्रिया में रहते हैं। लेकिन मालवा के एक जिले में पदस्थ एक आईपीएस अधिकारी की मटरगश्ती प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में चटखारे लेकर सुनी और सुनाई जा रही है। दरअसल, उक्त महिला आईपीएस प्रोविजनल डीएसपी पद पर पदस्थ हैं और उनकी प्रतिभा का हर कोई लोहा मानता है। वह इसलिए कि वे एक आरक्षक की बेटी हैं और उन्होंने आईपीएस बनने से पहले कई अन्य नौकरियां भी की हैं। लेकिन फोटो खिंचवाने की लालसा उनकी प्रतिभा पर भारी पड़ रही है। दरअसल, जब भी किसी आयोजन में वरिष्ठ या सहयोगी अधिकारियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने का अवसर आता है, मैडम इस तरह बन-ठनकर आती हैं कि हर कोई उन्हें देखकर अचंभित हो जाता है। कई बार तो उनके कपड़े ऐसे मॉडर्न लुक में होते हैं जो एक आईपीएस अफसर की मर्यादा के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैडम को यह ज्ञात नहीं है, लेकिन वे अतिउत्साह में ऐसा कर जाती हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है।



काम करें या समन्वय बनाएं

प्रदेश के नौकरशाह इस समय दोहरी चुनौती से जूझ रहे हैं। एक तो उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ उन पर विधायकों से समन्वय बनाने का दबाव डाला जा रहा है। इसका असर यह हो रहा है कि मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ अफसर दुविधा में पड़े हुए हैं। इसी तरह दुविधा में फंसे एक कलेक्टर ने तो गत दिनों सरकार के मुखिया से कह दिया कि आप तो हमें कलेक्टरी से हटा दो। दरअसल, हो यह रहा है कि एक तो कलेक्टरों पर जिले की विकास योजनाओं को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने को कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि विकास योजनाओं का काम विधायकों के साथ समन्वय बनाकर करें। ऐसे में कई कलेक्टर इसलिए परेशान हैं कि जब भी किसी विकास योजना पर चर्चा के लिए वे विधायक से मिलना चाहते हैं तो पता चलता है कि माननीय राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। इस कारण विधायक के इंतजार में कलेक्टर योजना को क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। योजना के क्रियान्वयन में देर होने के कारण सरकार के मुखिया कलेक्टरों को फटकार लगाते हैं। कभी-कभी तो सरकार के मुखिया कलेक्टरों को खरी-खोटी सुना देते हैं। ऐसे में कलेक्टरों की समझ में नहीं आ रहा है कि वे करें तो क्या करें। इसी दुविधा में फंसे एक कलेक्टर ने विगत दिनों सरकार के मुखिया से साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि इससे तो अच्छा है आप मुझे कलेक्टरी से हटा दो।

9 दिन चले अढाई कोस

यह एक मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसे इंदौर स्मार्ट सिटी में चरितार्थ किया जा रहा है। दरअसल, प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी में जिस तरह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लटके हुए हैं, उससे योजना भी अधर में है। ऐसे में योजना को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। जब योजना की धीमी रफ्तार की पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि सबसे इस योजना का प्रभार 2015 बैच की एक महिला आईएएस के हाथ में आई है, तबसे इसका काम लगभग ठप सा पड़ गया है। सूत्रों का कहना है कि विभाग में अपनी पदस्थापना के बाद से ही मैडम हर मामले में पेंच फंसाती रहती हैं। विभाग के अधिकारी जो भी प्रोजेक्ट बनाकर लाते हैं, मैडम उसमें कोई न कोई नुक्स निकाल देती हैं। इस कारण प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैडम की पेंच फंसाने की आदत से अधिकारियों के साथ ही ठेकेदार भी परेशान हैं। आलम यह है कि इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इन दिनों काम की बजाय फाइल-फाइल खेला जा रहा है। मैडम की कृपा से स्मार्ट सिटी का काम लगभग ठप पड़ा हुआ है।

तू डाल-डाल, मैं पात-पात

मग्न में इन दिनों राजनीति चमकाने का दौर चल रहा है। इस कड़ी में प्रदेश के दो कद्दावर नेताओं के बेटों के बीच राजनीति चमकाने की होड़ मची हुई है। तू डाल-डाल, मैं पात-पात की तर्ज पर ये युवा नेता अपने-अपने क्षेत्र में कार्यक्रमों का आयोजन कर जनता के बीच पैठ बना रहे हैं। विगत दिनों एक नेता के सांसद पुत्र ने अपने क्षेत्र में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया और उसका उद्घाटन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरेश रैना के हाथों करवाया। उनके इस आयोजन का तगड़ा जवाब देते हुए दूसरे नेता के पुत्र ने अपने पिता के विधानसभा क्षेत्र में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया और उसका उद्घाटन कांग्रेस से भाजपा में आए कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद से करवाया। यही नहीं इस युवा नेता ने अपने क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का मेला भी लगवाया। जिसमें आसपास के क्षेत्रों के लोग पहुंचे और सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। इन दोनों युवा नेताओं के बढ़ते रुतबे को देखते हुए अन्य वरिष्ठ नेताओं के पुत्र भी ऐसे आयोजन करने की रणनीति बना रहे हैं।



मैं जनता के आग्रह पर चुनाव तो लड़ूंगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री अब कोई नया चेहरा होना चाहिए। पार्टी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाएगी और आगामी चुनाव में युवा चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ेगी।

● वीरभद्र सिंह



राज्यपाल ही क्या, मुख्यमंत्री को भी निजी इस्तेमाल के लिए सरकारी विमान के अनुमति की इजाजत नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने नियम का पालन ही किया, इसमें राज्यपाल से विवाद का सवाल ही कहां उठता है, परंतु महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता देवेन्द्र फडणवीस इस विमान विवाद को अलग ही हवा में उड़ाने लगे हैं। इससे राज्यपाल की ही गरिमा को ठेस पहुंची है।

● संजय राउत



भले ही मैं 100 मीटर का धावक हूँ, लेकिन मुझे भी क्रिकेट पसंद है। अक्सर मैं अपने घर में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। मुझे क्रिकेट खेलता देख दोस्त उसमें भी भाग्य आजमाने की सलाह देते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि घर और ग्राउंड में क्रिकेट खेलने में बड़ा अंतर है। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे प्रशंसक मेरे हर कदम को सराहते हैं।

● उसेन बोल्ट



हमारी कोशिश रहेगी कि पूरा विश्व समुदाय मिल-जुलकर रहे। एक देश को दूसरे देश के हितों का ध्यान रखना होगा। हम अच्छे दोस्त तभी हो सकते हैं, जब एक-दूसरे के हितों पर ध्यान रखेंगे। इसलिए हमारी अपील है कि सभी एक-दूसरे के हितों का ध्यान रखें।

● जो बाइडेन



मैंने अपनी लगभग हर फिल्म में एक अलग तरह का किरदार निभाया है। इन दिनों मैं पठान फिल्म में काम कर रही हूँ। यह फिल्म भी अलग कहानी और किरदार वाली है। हाल ही में मुझे धूम-4 में विलेन के लिए ऑफर मिला है। मैं भी कुछ अलग तरह का रोल करना चाहती हूँ। अभी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद निर्णय लूंगी कि विलेन का रोल करूँ कि नहीं। अगर यह रोल मेरे फैंस को खुश रखेगा तो निश्चित रूप से मैं इसे करूँगी। वैसे आज तक मैंने जितने भी रोल अदा किए हैं, फैंस ने उसकी सराहना की है।

● दीपिका पादुकोण

वाक्युद्ध



देश में कुछ लोगों को राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बातों से एलर्जी हो रही है। हैरानी तो यह है कि जब भी राष्ट्रवाद की बात होती है, लोग केंद्र सरकार और मुझे घेरने में जुट जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि लोगों को देशभक्ति की बातें चुभती हैं। ऐसे लोगों को भारत में रहने की जरूरत नहीं है।

● कंगना रनौत

भारत किसी धर्म या जाति का देश नहीं है। यहां धर्म, जाति और विचारधारा के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति राष्ट्रभक्त है। अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राष्ट्रवाद के नाम पर देश में एक विचारधारा को बढ़ाया जा रहा है।

● स्वरा भास्कर



दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार की गारंटी देने वाली योजना मनरेगा में अब तक का रिकॉर्ड बजट मुहैया कराया गया है। इससे शहरों से पलायन करके गांवों में पहुंचे लोगों को रोजगार मिल रहा है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने मप्र को 28.50 करोड़ काम तैयार करने का लक्ष्य दिया था, जिसमें अभी तक 24.50 करोड़ से अधिक मानव दिवस के लिए काम तैयार किया जा चुका है। मनरेगा में मिल रहे रोजगार से प्रवासी मजदूरों को काफी लाभ मिला है। औसतन 20 लाख मजदूरों को रोज मनरेगा में काम मिल रहा है, जो पिछले सालों की तुलना में सर्वाधिक रिकॉर्ड है।

मनरेगा के तहत मप्र के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों को जहां बड़ी संख्या में रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, वहीं देशभर में काम की मांग के बावजूद 97 लाख परिवारों को रोजगार नहीं मिल सका। कोरोना महामारी से उपजे बेरोजगारी के संकट के दौर में इन सभी परिवारों ने मनरेगा में रोजगार के लिए काम की मांग की थी। इतना ही नहीं, इस साल मनरेगा में रोजगार पाने को लेकर जॉब कार्ड के लिए आवेदन करने के बावजूद 45.6 लाख परिवारों के जॉब कार्ड नहीं बन सके, जबकि कुल 9.02 करोड़ जॉब कार्ड सक्रिय रहे। इसके बावजूद देशभर में नवंबर तक 19 लाख परिवार ही मनरेगा में मिलने वाले 100 दिनों का रोजगार पूरा कर सके हैं। यह आंकड़े वर्ष 2004 में मनरेगा योजना की सरकारी वेबसाइट की एमआईएस रिपोर्ट को ट्रैक करने के लिए बनाए गए कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और जन संगठनों के सदस्यों का एक समूह पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी (पीईजी) की हालिया रिपोर्ट में सामने आए हैं। यह रिपोर्ट अब तक ग्रामीणों को मनरेगा में रोजगार मिलने को लेकर तस्वीर पेश करती है।

मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को साल में 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। प्रत्येक लाभार्थी ग्रामीण परिवार को एक जॉब कार्ड दिया जाता है, जिसमें घर के सभी वयस्क सदस्यों के नाम होते हैं जो मनरेगा में काम कर सकते हैं। मप्र में इस वर्ष 46.65 लाख परिवारों के 86 लाख से अधिक मजदूरों को मनरेगा में काम मिला है। 1.47 लाख परिवारों ने अपने हिस्से का 100 दिवस काम पूरा भी कर लिया है। 24.51 करोड़ मानव दिवस में से 13.46 प्रतिशत काम अनुसूचित जाति, 33.51 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों ने किए हैं। वहीं मप्र में अभी 8.92 लाख लोग ऐसे हैं जो मनरेगा के तहत काम की आस लगाए बैठे हैं। कोरोना संक्रमणकाल के दौरान शहरी श्रमिकों का बड़ी संख्या में गांवों की ओर पलायन हुआ है। गांवों में बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए

मनरेगा मजबूरी नहीं जरूरी



19 लाख परिवारों को 100 दिन का रोजगार

कोरोना के कारण शहरों से हुए पलायन के कारण देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। ऐसी स्थिति में मनरेगा श्रमिकों के लिए वरदान साबित हुई है। पीईजी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि नवंबर तक देशभर में 19 लाख परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिल सका है, जबकि पिछले वर्ष से तुलना करें तो 40.61 लाख परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिल सका था। पीईजी की इस रिपोर्ट से जुड़े और मनरेगा मजदूरों के लिए लंबे समय से काम करते आ रहे देबमाल्या नंदी बताते हैं कि इन आंकड़ों के अनुसार वास्तव में मनरेगा में रोजगार को लेकर देशभर में कितनी भारी मांग रही है। रोजगार की इतनी मांग के बावजूद 100 दिन का रोजगार पूरे करने वाले सिर्फ 19 लाख परिवार रहे, जबकि काम की मांग को देखते हुए यह आंकड़ा अब तक पिछले वर्ष के मुकाबले 40 लाख परिवारों से कहीं ज्यादा होना चाहिए था। ऐसा इसलिए सामने आया क्योंकि मांग के बावजूद राज्य सरकारें मनरेगा की क्षमता को पूरी तरह से पकड़ नहीं कर पाईं। वह कहते हैं कि मनरेगा कभी भी ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने के करीब नहीं पहुंच पाया।

मप्र सरकार ने मनरेगा के तहत हर श्रमिक को काम देने की घोषणा कर दी। इसका प्रतिफल यह हुआ कि सबसे ज्यादा मजदूरों को काम देने के मामले में मप्र शीर्ष पर पहुंच गया है। अकेले 22 दिसंबर को ही एक लाख से अधिक काम के लिए 19 लाख 43 हजार से अधिक मनरेगा मजदूरों की तैनाती रही।

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने मप्र को 28.50 करोड़ काम तैयार करने का लक्ष्य दिया था, जिसमें अभी तक 24.50 करोड़ से अधिक मानव दिवस के लिए काम तैयार किया जा चुका है। मनरेगा में मिल रहे रोजगार से प्रवासी मजदूरों को काफी लाभ मिला है। औसतन 20 लाख मजदूर को रोज मनरेगा में काम मिल रहा है, जो पिछले सालों की तुलना में सर्वाधिक रिकॉर्ड है। इस वर्ष 46.65 लाख परिवारों के 86 लाख से अधिक मजदूरों को मनरेगा में काम मिला है। 1.47 लाख परिवारों ने अपने हिस्से का 100 दिवस काम पूरा भी कर लिया है। 24.51 करोड़ मानव दिवस में से 13.46 प्रतिशत काम अनुसूचित जाति, 33.51 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों ने किए हैं। लेकिन पीईजी की रिपोर्ट में सामने आया कि सरकारों की कोशिश के बाद भी 30 नवंबर तक 97.32 लाख परिवारों को काम

मांगने के बावजूद रोजगार नहीं मिल सका। देश के सबसे बड़े राज्य उप्र में करीब 25 लाख से ज्यादा ग्रामीणों ने मनरेगा में रोजगार के लिए आवेदन किया, मगर उन्हें एक भी दिन का रोजगार नहीं मिल सका। यह आंकड़ा ओडिशा में 6.85 लाख, बिहार में 8.32 लाख और मप्र में 8.92 लाख रहा। नवंबर तक देशभर में 97 लाख से ज्यादा ऐसे ग्रामीण परिवार रहे, जिन्हें मनरेगा में रोजगार की मांग करने के बावजूद काम नहीं मिल सका।

कोरोना वायरस से देश में लगे पूर्ण लॉकडाउन के खत्म होने के बाद 20 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों के 179 जिलों में 25 हजार से ज्यादा ग्रामीणों के बीच सर्वे के बाद तैयार एक रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं वह चौंकाने वाले हैं। सर्वे के अनुसार देश के 68 प्रतिशत ग्रामीणों ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें या उनके परिवार के किसी न किसी सदस्य को मनरेगा में काम मिला। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने 21 अप्रैल से मनरेगा में लोगों को रोजगार दिए जाने की छूट दी थी। इसके बावजूद कई इलाकों में लॉकडाउन के चार महीने बीतने के बाद भी मनरेगा का काम शुरू नहीं हो सका।

● प्रवीण कुमार

हार से जो सबक लेकर आगे की तैयारी में निरंतर लगा रहता है, उसकी जीत निश्चित होती है। इसी तर्ज पर मप्र भाजपा काम कर रही है। 2018 में मिली हार के बाद फिर से सत्ता में वापसी के साथ ही पार्टी अपने मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों को लगातार प्रशिक्षण दे रही है, ताकि जीत की सारी बाधाएं फटह कर ली जाएं। इसी कड़ी में महाकाल की नगरी में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया।

बीते विधानसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए मप्र भाजपा अभी से अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। इसके लिए भाजपा ऐसी रणनीति बना रही है, जिससे कि 2023 तक प्रदेश से कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया किया जा सके। यही वजह है कि ऐसी रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए विधायकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर उज्जैन में 12 व 13 फरवरी को आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण वर्ग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित सभी वरिष्ठ नेताओं ने मंत्रियों और विधायकों को जीत का मंत्र दिया।

संगठन की दृष्टि से स्वाभाविक यह कार्यक्रम अतीत, वर्तमान और भविष्य के सामंजस्य का केंद्र है। पिछले कुछ वर्षों से पार्टी में गैर भाजपाई नेताओं का आगमन तेज हुआ है। वर्तमान में सत्ता और संगठन में इनकी संख्या बढ़ी है। आने वाले दिनों में ऐसे नेताओं को पार्टी की रीति-नीति के अनुसार अनुशासित और प्रतिबद्ध कर आगे बढ़ना है। गैर भाजपाइयों के पार्टी में आने से विपक्ष बेशक कमजोर हुआ है। वर्तमान में भाजपा सत्ता में है। भविष्य में नगरीय निकाय, 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी पार्टी को तैयारी करनी है। यानी सत्ता और संगठन को अतीत से निकलकर, वर्तमान संभालकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है। जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा कहते रहे हैं कि भाजपा में शीर्ष नेतृत्व से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो प्रशिक्षण वर्ग भी उनके बयानों की पुष्टि करता है।

दरअसल, 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की पराजय और उससे कुछ वर्ष पहले तक पार्टी में गैर भाजपाइयों के आगमन का सिलसिला याद करें, तो पार्टी ने कई तरह की उथल-पुथल देखी है। हालांकि प्रदेश की सत्ता उसे डेढ़ साल बाद फिर से मिल गई, लेकिन अब संगठन का स्वरूप बनाए रख पाना ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया। आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि



जीत का मंत्र

दो साल बाद होने वाले चुनावों पर नजर

भाजपा और कांग्रेस की नजर विधायकों के इस प्रशिक्षण वर्ग में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की जीत पर है। दोनों ही दलों को बीते आम चुनाव में स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिल सका था। यह बात अलग है कि दूसरे दलों और निर्दलियों के भरोसे पहले कांग्रेस ने और फिर निर्दलियों व दलबदलुओं की मदद से भाजपा ने सरकार बनाई, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। यही वजह है कि अब दोनों दलों का फोकस अभी से विधानसभा चुनाव की रणनीति पर बना हुआ है। मप्र के जिन अंचलों में पिछले विधानसभा चुनाव में उसकी हार हुई उसके कारणों की तह तक जाते हुए पार्टी ने अब अनुसूचित जाति, जनजाति का भरोसा जीतना अपनी पहली प्राथमिकता बना लिया है। इसके लिए पार्टी के पदाधिकारी मंत्री विधायक सांसद और दूसरे जिम्मेदार नेता वर्ग विशेष पर केंद्रित चिंतन-मंथन करने जा रहे हैं। भाजपा ने इस वर्ग की छोटी जाति और अलग-थलग पड़े समुदाय को एकजुट कर पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। एक ओर शिवराज सरकार गलती सुधारने के साथ सवर्ण आयोग के गठन के साथ आरक्षण से प्रभावित मतदाताओं का भरोसा नए सिरे से जीतना चाहती है, तो दूसरी ओर धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए उसने आदिवासी जाति और आरक्षित विधानसभा सीटों पर भरोसा जीतने की अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं।

पार्टी के कुल विधायकों में से 20 प्रतिशत से ज्यादा मूल रूप से भाजपा से जुड़े नहीं रहे हैं, वहीं कैबिनेट में ऐसे 40 प्रतिशत से ज्यादा मंत्री हैं। अब नगरीय निकाय चुनाव सामने हैं। इसके बाद विधानसभा और लोकसभा के चुनाव। संगठन में नए चेहरों के आने से उनसे पुरानी सियासी अदावतें नहीं भुला पाना कार्यकर्ताओं के लिए आसान नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस या निर्दलीय विधायक रहे नेताओं का भाजपा में आना उनकी कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं ला सका है।

भाजपा के कई वरिष्ठ नेता कहते रहे हैं कि कांग्रेस में नेताओं का आभामंडल काम करता है, जबकि भाजपा में उनकी कार्यशैली। पार्टी मानती है कि भाजपा में विधायक बनने तक कोई भी नेता इसके कई अनुष्ठांगिक संगठनों के साथ काम कर चुका होता है। वह कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल का महत्व समझता है और जनता के बीच मौजूदगी को महत्व देता है।

इधर मुश्किल यह है कि कांग्रेस से जो विधायक भाजपा में आए हैं, उनकी उम्र 45 से लेकर 65-70 साल तक है। यानी उन्होंने सियासत की शुरुआत कांग्रेस की रीति-नीति, कार्यप्रणाली के साथ की है और अब इस मुकाम तक पहुंचने के बाद उसमें बदलाव कर पाना उनके व्यक्तित्व के सवाल से जुड़ जाता है। पार्टी मुख्यालय में भी इन विधायकों एवं मंत्रियों के आने पर कार्यकर्ताओं में कोई अपनापन नहीं दिखाई देता। कई बार इनके स्वभाव को पार्टी के ही भीतर अनमना कहा जा चुका है। अब बजट सत्र सामने है और नगरीय निकाय चुनाव में

कांग्रेस से कड़ा मुकाबला होना है, तो भाजपा में बाहर से आए विधायकों और मंत्रियों को पार्टी की रीति नीति से जोड़कर उन्हें अनुशासित और प्रतिबद्ध बनाना भी जरूरी हो गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का महत्व इस लिहाज से भी बढ़ जाता है कि कांग्रेस की सियासत व्यक्तित्व केंद्रित रही है, लेकिन भाजपा में पार्टी के लिए प्रतिबद्धता रही है। चाहे मुख्यमंत्री बदल जाए या पार्टी अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के बीच खेमेबंदी जैसी कोई भावना नहीं रहती। बाहर से आए विधायकों और मंत्रियों को इसी खेमेबंदी से बाहर निकालकर पार्टी में समरस करना ही इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य बताया गया है। हालांकि दो दिन की चर्चा और विभिन्न विषयों पर जानकारी किसी विधायक या मंत्री के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हुए बदल सके, सियासत में ऐसा कम ही देखने में आता है। जिनकी निष्ठा बदलनी होती है, उनकी रातोंरात बदल जाती है और जिनका व्यक्तित्व बदलना मुश्किल है, उन्हें कई प्रशिक्षण भी बदलाव के सूत्र नहीं दे पाते हैं। आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव साबित कर सकेंगे कि कितने विधायकों और मंत्रियों के व्यक्तित्व और विचार में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बदलाव ला सका है।

प्रशिक्षण वर्ग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों को अच्छे नेता बनने के टिप्स दिए। उन्होंने कहा उस जनता और कार्यकर्ता के सम्मान में कहीं कमी न आने दें जिसने आपको नेता चुना है। पार्टी के तीन मंत्र राष्ट्रवाद, अंत्योदय और सुशासन को कभी न भूलें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों से कहा कि आप गहराई के साथ प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन कीजिए। अपने विचार-परिवार को समझिए और इस बात पर चिंतन कीजिए कि समाज ने आपको जनप्रतिनिधि चुना है, तो आपके सामाजिक दायित्व क्या हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि हम उस दल के विधायक हैं, जिसकी प्रेरणा राष्ट्रवाद है, लक्ष्य अंत्योदय है और मंत्र सुशासन है। हम सभी को मिलकर एक गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्धशाली और शक्तिशाली भारत का निर्माण करना है।



मुख्यमंत्री चौहान ने कहा भाजपा का कार्यकर्ता बड़े लक्ष्य के लिए बना है। इसलिए विधायकों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्यकर्ता विचार के लिए लड़ता है और आपको विधायक बनाने के लिए संघर्ष करता है, उसके प्रति स्नेह और सम्मान में कोई कमी न आए। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा करवाए गए परमाणु परीक्षण और चीन सीमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहस और सूझबूझ का उल्लेख करते हुए कहा आज दुनिया भाजपा के सुशासन के कारण भारत के पराक्रम का लोहा मान रही है। धारा-370, राम मंदिर, सीएए और तीन तलाक जैसे अविश्वसनीय लगने वाले काम पूरे हो चुके हैं। कोरोनाकाल में हमारे नेतृत्व की क्षमताओं का लोहा दुनिया मान रही है।

गौरतलब है कि पचमढ़ी में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते पूर्व में अपने मंत्रियों का आईक्यू टेस्ट लेने का भी प्रयोग किया जा चुका है। उसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति और मप्र से जुड़े बैंकेया नायडू जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए थे। इसके साथ ही अब भाजपा बीते आम चुनाव में मिली हार के कारणों में सामने आए अनुसूचित जाति, जनजाति वोट बैंक पर अपनी कमजोर होती पकड़ को और मजबूती देने पर भी काम करने का फैसला कर चुकी है। भाजपा

को बीते चुनाव में जयस की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी योजना तैयार की जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव फिलहाल भाजपा के लिए एक पड़ाव रहेगा लेकिन उसका बड़ा लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनाव ही माना जा रहा है। इसके साथ ही हाल ही में इंदौर पदाधिकारियों की बैठक में शीर्ष नेतृत्व ने यह बता दिया कि यहां बैठे लोग ही भविष्य की भाजपा का चेहरा होंगे यानी जवाबदेही और जिम्मेदारी का अहसास गाइडलाइन से अवगत कराते हुए करा दिया गया इसलिए सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए मानस बना लेना होगा। इस प्रदेश पर पार्टी आलाकमान की भी खास नजर है, जिसकी वजह से ही केंद्र द्वारा अपने आधा दर्जन पदाधिकारियों को भी अब तक तैनात किया जा चुका है। दरअसल इस पूरी कवायद के पीछे एक बड़ी वजह विपक्ष की भूमिका निभाने वाले भाजपा के टिकट पर श्रीमंत समर्थकों के निर्वाचित विधायक भले ही अब भाजपाई हो चुके हैं, लेकिन उनके मूल भाजपाई नेताओं के साथ समन्वय की मजबूती जरूरी है। भाजपा संगठन इस बार किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहती है। इसलिए विधायकों का यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

● कुमार राजेन्द्र

पीए से सावधान और बिचौलियों से दूर रहें

प्रशिक्षण वर्ग के पहले दिन के आखिरी सत्र में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने विधायकों को सीख दी कि वे अपने दामन में लगने वाले दामों से किस तरह बचें। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक जरूरत अपने निज सहायक (पीए) से सतर्क रहने की है। ये चाय से गर्म केतली वाली कहावत की तर्ज पर आम जनता और कार्यकर्ताओं के बीच आपकी छवि बिगाड़ते हैं। इनके लिए भी एक प्रशिक्षण वर्ग चलाया जाएगा। सभी विधायक पीए की नियुक्ति करते समय भी ध्यान दें कि वे ईमानदार छवि के हों। चौहान ने कहा कि आपके इर्द-गिर्द जो बिचौलिए घूमते हैं, इनके आभा मंडल में फंसने की जरूरत नहीं है। ये आपकी पद-प्रतिष्ठा के कारण आते हैं और जो इनके चंगुल में फंस जाता है, वो चुनाव हार जाता है। अंतिम सत्र में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि हमारी सरकार ने 8-10 महीने में जो हमने काम किए हैं, इन्हें आम जनता के पास ले जाएं। हमने लव जिहाद रोकने के लिए ठोस कानून बनाए हैं। अब हम ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं, जिससे लोगों के घर से पत्थर निकाले जाएंगे। पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाएंगे। हमारी सरकार अब तक चार हजार गुमशुदा बच्चियों की घर वापसी करा चुकी है।

केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अटल प्रोग्रेस-वे विवादों में पड़ता जा रहा है। सबसे बड़ा विवाद जमीनों के अधिग्रहण को लेकर है। विवाद की वजह है अधिकारियों द्वारा मनमानी घोषणाएं। दरअसल, योजना को जैसे ही सरकार ने हरी झंडी दी, अफसरों ने अपने-अपने जिले में अपने-अपने मन से जमीन अधिग्रहण को लेकर घोषणाएं कर दीं। अब जब जमीन अधिग्रहण करने का समय आया है तो उक्त घोषणाएं बाधा बन रही हैं। गौरतलब है कि चंबल नदी के किनारे अटल प्रोग्रेस-वे बनाने के लिए किसानों की जमीन लेने के बदले उन्हें दोगुनी जमीन देने की घोषणा सरकार ने की थी। अफसरों ने भी किसानों को यही भरोसा दिया। अब सरकार दोगुनी जमीन देने से पीछे हट रही है। किसान को उतनी ही जमीन देने की बात कही जा रही है जितनी जमीन उससे ली जाएगी। राजस्व अधिकारी भी कह रहे हैं कि जमीन के बदले दोगुनी जमीन देने का कोई नियम ही नहीं है। ऐसे में किसान अपनी एक इंच जमीन देने को भी राजी नहीं हैं।

6 हजार करोड़ की लागत से कोटा से श्योपुर होते हुए मुँरैना-भिंड तक अटल प्रोग्रेस-वे स्वीकृत किया गया है। इसमें मुँरैना के 70 गांवों के 1358 किसानों की 489 हैक्टेयर निजी जमीन अधिग्रहित होनी है लेकिन अब तक एक भी किसान ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन देने की सहमति नहीं दी है। घड़ियाल अभयारण्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अटल एक्सप्रेस-वे को चंबल नदी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में करीब 1467 हैक्टेयर जमीन सरकारी है। वहीं 489 हैक्टेयर किसानों की जमीन आएगी। अटल प्रोग्रेस-वे के लिए मुँरैना अनुभाग के गड़ौरा, गौसपुर, जखौना, नायकपुरा, गोरखा, पिपरई, विंडवा चंबल, मसूदपुर, जारह व कैथरी गांव की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है लेकिन दो शिविर लगाने के बाद भी किसानों ने अपनी जमीन देने की सहमति नहीं दी। वहीं अंबाह के ऐसाह, जौहा, डंडौली, खिरेटा, गूज व रिठौना गांव की 73.685 हैक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है लेकिन किसान दोगुनी जमीन मिलने का लिखित अनुबंध होने के बाद ही अपनी जमीन देने की बात कह रहे हैं। उक्त गांवों से होकर ही अटल प्रोग्रेस-वे निकलेगा। इसमें पोरसा के 15, जौरा के 18, सबलगढ़ के 21 व पोरसा के 150 गांव शामिल रहेंगे।

अटल प्रोग्रेस-वे की डिजिटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भोपाल की एलएन मालवीय कंपनी को दिया है। यह कंपनी एक साल में डीपीआर बनाकर एनएचएआई को सौंपेगी। इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके अगले चरण में प्रोग्रेस-वे बनाने का काम। आंकलन के मुताबिक,



अगस्त-2020 में की थी दोगुनी जमीन की घोषणा

पहले सरकार ने जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा न देकर जमीन देने की बात कही थी। इस पर ज्यादातर किसान तैयार नहीं थे। ऐसे में अगस्त-2020 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर प्रवास के दौरान किसानों को जमीन के बदले दोगुनी जमीन देने की घोषणा की थी लेकिन अब अफसरों का कहना है कि ऐसा कोई आदेश नहीं आया। सड़क विकास निगम के मैनेजर अर्पित कुशवाहा का कहना है कि हम तो केवल राजस्व विभाग के सहयोग से आवश्यक जमीन के अलाइनमेंट का प्रस्ताव एसडीएम व तहसीलदारों को नए सिरे से भेज रहे हैं। प्रोग्रेस-वे पहले श्योपुर के खातौली से शुरू होकर वीरपुर, मुँरैना के गढ़ौरा, अंबाह होते हुए भिंड के शिहदा होकर उग्र के नेशनल हाईवे 719 से जुड़ना था। बाद में इसे दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर से उग्र के दिल्ली इलाहाबाद कॉरिडोर से जोड़ने का फैसला लेते हुए खातौली की बजाय इसकी शुरुआत राजस्थान के दीगोद से करने का फैसला लिया। राजस्थान में प्रोग्रेस-वे की लंबाई 78 किमी बढ़ गई है, लेकिन राजस्थान में इसके निर्माण की कोई सुगबुगाहट नहीं है।

प्रोग्रेस-वे का काम 2022 के अंत तक शुरू होने की स्थिति बन पाएगी।

भू-राजस्व संहिता में जमीन के बदले जमीन या मुआवजा देने का ही प्रावधान है। ऐसा नियम नहीं है कि जमीन के बदले ज्यादा जमीन दी जा सके। राजस्व विभाग के अफसरों के अनुसार भू-राजस्व संहिता में नियम चाहे तो राज्य सरकार बदल सकती है, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि आगे यह नियम सरकार के लिए ही सिरदर्द बन सकता है। ऐसे में किसानों को दोगुनी जमीन मिलना मुश्किल है। सड़क विकास निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर पीएस राजपूत कहते हैं

कि अटल प्रोग्रेस-वे के लिए 70 गांव के किसानों की 489 हैक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। पटवारी अभी नक्शों से जमीन का मिलान व सत्यापन कर रहे हैं। अभी तक एक भी किसान ने सहमति जमीन अधिग्रहण के लिए नहीं दी है। जमीन के बदले दोगुनी जमीन देने संबंधी कोई आदेश शासन से नहीं आया है।

गौरतलब है कि राजस्थान के दीगोद से लेकर श्योपुर, मुँरैना और भिंड होते हुए उग्र तक को जोड़ने के लिए 404 किमी लंबा अटल प्रोग्रेस-वे बनाया जा रहा है। भारत माला परियोजना के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) द्वारा बनाए जाने वाले इस प्रोग्रेस-वे की लंबाई मप्र के श्योपुर, मुँरैना व भिंड जिले में 309.08 किमी होगी और इसके निर्माण पर 6 हजार 58 करोड़ 26 लाख रुपए का खर्च आंका जा रहा है। मप्र सरकार को जमीन का अधिग्रहण कर केंद्र सरकार को देना है। प्रोजेक्ट में 52 फीसदी जमीन सरकारी तो 48 फीसदी जमीन किसानों की आ रही है। किसानों की जमीन को अधिग्रहित करने का जिम्मा मुँरैना, श्योपुर और भिंड जिला प्रशासन को दिया है, लेकिन अधिग्रहण 20 फीसदी भी नहीं हो पाया है। मुँरैना में 55 गांव के 1700 से ज्यादा किसानों की 4200 बीघा से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण होना है, पर अभी 100 किसानों से भी जमीन अधिग्रहित नहीं हुई। श्योपुर में करीब 1100 किसानों से 3000 बीघा जमीन का अधिग्रहण होना है। इनमें से जिला प्रशासन 408 किसानों की सहमति ले चुका है, 700 किसान जमीन देने अब तक तैयार नहीं। श्योपुर में 408 किसानों से यह कहकर जमीन अधिग्रहण की सहमति ले ली है कि उनकी अगर एक बीघा जमीन जाएगी तो उन्हें 2 बीघा जमीन सरकार देगी। मुँरैना में किसानों को जमीन के बदले उतनी ही जमीन देने का वादा किया जा रहा है।

● नवीन रघुवंशी

कांग्रेस कैडर बेस पार्टी नहीं है। इस कारण पार्टी के विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के सुर बिखरे रहते हैं। 15 साल बाद सत्ता में आई पार्टी 15 माह बाद ही सत्ता से बाहर हो गई, इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि पार्टी विधायक किसी एक विचारधारा से बंधे नहीं थे। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बचे 96 विधायकों को एकजुट रखने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसके लिए जल्द ही विधायकों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, जहां उपदेशों और नसीहतों के माध्यम से कांग्रेस की विचारधारा से सबको बांधा जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को मात देकर फिर से सत्ता में आना चाहती है।

गौरतलब है कि विगत दिनों महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन में भाजपा विधायकों के दो दिनी प्रशिक्षण वर्ग में नसीहतों और उपदेशों की घुट्टी पिलाई गई है। उसका मकसद विधायकों के हाव-भाव, कार्यशैली में बदलाव कर समन्वय और समरसता बैठाकर छवि सुधारना है। इस कवायद का आखिर विधायकों पर कितना असर पड़ा उस दृष्टि से देखने वाली बात यही होगी कि उनके आचार, व्यवहार और कार्यशैली में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए उपदेश रूपी क्रीम का प्रयोग करने से आखिरकार चेहरे में कितना निखार आएगा? लेकिन भाजपा के इस वर्ग का असर कांग्रेस पर जरूर पड़ा है। अब कांग्रेस इस कोशिश में लगी है कि जल्द से जल्द वह भी अपने विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करे।

33 साल बाद अब कांग्रेस विधायकों को सिखाने जा रही है कि उन्हें विधायकी कैसे करनी है। इसके लिए पार्टी जल्दी ही 96 विधायकों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रही है। पार्टी के सभी विधायक दो से तीन दिन तक एक जगह रुक सकें, इस लिहाज से प्रारंभिक तौर पर यह शिविर खजुराहो में आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। आयोजन के लिए मांडू भी एक विकल्प रखा गया है। विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है जो 26 मार्च तक चलेगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का विचार है कि शिविर का आयोजन सत्र के बाद ही किया जाए, जिससे सभी विधायक मौजूद रह सकें। प्रदेश कांग्रेस संगठन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा के बाद इस आयोजन के बारे में अंतिम फैसला लेगा।

कांग्रेस सांसदों और विधायकों को सेवादल के प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए प्रशिक्षित करती रही है। मप्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान सेवादल के प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए मप्र के विधायकों को

भाजपा के बाद अब कांग्रेस भी अपने विधायकों को उपदेशों और नसीहतों की घुट्टी पिलाकर उन्हें चमकाने की कोशिश करेगी। इसके लिए पार्टी जल्द ही प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेगी। हालांकि अभी प्रशिक्षण की तिथि तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि खजुराहो या मांडू में प्रशिक्षण शिविर लगाया जा सकता है।

उपदेशों और नसीहतों की घुट्टी



80 प्रतिशत टिकट युवाओं को देगी कांग्रेस

नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस-भाजपा दोनों खेमों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर जोड़-तोड़ का खेल शुरू हो गया है। दोनों पार्टियों में महापौर के साथ पार्षद की दावेदारी करने वाले सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि वह निकाय चुनाव में 80 प्रतिशत युवाओं को टिकट देगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने प्रदेशभर में सर्वे करा लिया है। पार्टी जल्द ही महापौर समेत सभी पार्षद प्रत्याशियों के नाम तय कर लेगी। इतना ही नहीं इस बार पार्षदों की 80 प्रतिशत टिकट अंडर 40 यानी युवाओं को देने का भी निर्णय लिया गया है। जिसमें युवक कांग्रेस और एनएएसयूआई द्वारा दिए जाने वाले नामों को प्राथमिकता दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार इस बार केवल सक्रिय स्थानीय नेताओं को ही टिकट दिया जाएगा। किसी भी वार्ड में पैराशूट प्रत्याशियों को नहीं थोपा जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने अपने सभी स्थानीय नेताओं को आश्वस्त कर दिया है कि जो क्षेत्र में सक्रिय रहा है, उसे ही टिकट दिया जाएगा। उधर, युवा कांग्रेस चाहती है कि नगरीय निकाय चुनाव में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाए। इसके लिए युवा कांग्रेस ने अपने संगठन के पदाधिकारियों से जिलों से सीधे नाम भोपाल बुलाए हैं।

प्रशिक्षित किया गया था, उस दौरान दिग्विजय सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। यह संयोग की बात है कि सेवादल का प्रशिक्षण शिविर खजुराहो में आयोजित किया गया था। वरिष्ठ विधायक पीसी शर्मा का कहना है कि इस तरह के आयोजन से संगठन शक्ति बढ़ती है। पार्टी शिविर के लिए एजेंडा तैयार कर रही है। इसमें प्रमुख तौर पर भाजपा को मौजूदा स्थिति में कैसे घेरा जाए, भाजपा की घेराबंदी के लिए कौन से मुद्दे हों, इस बारे में रूपरेखा तय की जा रही है। फिलहाल कांग्रेस विधानसभा में मजबूत विपक्ष की भूमिका में है और उसके 96 विधायक हैं।

इधर, इंदौर शहर में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद कांग्रेस अब संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। 21 फरवरी को आयोजित होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शामिल होंगे। 8 जिलों के कार्यकर्ता और निकाय चुनावों में टिकट के दावेदारों से नाथ बात करेंगे। कांग्रेस ने संभागीय सम्मेलन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी तरह के आयोजन प्रदेशभर में किए जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में 20 फरवरी को प्रदेश बंद का आह्वान किया है। इसके पीछे कांग्रेस की कोशिश यह है कि वह जनता के बीच में भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल बनाए। अब देखना यह है कि कांग्रेस की कोशिश कितनी कारगर सिद्ध होती है।

● अरविंद नारद



राजनीति के वियाबान में अपनी-अपनी मंजिल की तलाश कर रहे भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा अब अपनी डफली और अपना राग छोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि प्रदेश में डेढ़ दशक से अधिक समय से सरकार रहने के बाद अब इन नेताओं को राजधानी भोपाल और उसके आसपास के इलाकों के नए सिरे से नामकरण की याद आने लगी है। यह वे नेता हैं जो लंबे समय से सत्ता में भागीदार रहे हैं। अचानक इस तरह की मांगों में आई तेजी की वजह से अब राजनीतिक निहितार्थ भी तलाशे जाने शुरू हो गए हैं। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा तक शामिल हैं।

अगर इस मामले की सूची देखें तो धीरे-धीरे वह लंबी होती जा रही है। यह बात अलग है कि इन नेताओं के द्वारा विभिन्न स्थानों के नाम परिवर्तन को लेकर उठाई जा रही मांगों पर सूबे के मुखिया की चुप्पी के अपने ही अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इस तरह की मांग की शुरूआत शर्मा द्वारा की गई थी। उनके द्वारा भोपाल के ईदगाह हिल्स इलाके का नाम बदलकर नानक टेकरी करने की मांग की जा चुकी है। शर्मा का कहना है कि मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि 500 साल पहले ईदगाह टेकरी पर सिखों के पहले गुरु गुरुनानक देव जी आए थे।

इसलिए इसका नाम गुरुनानक टेकरी ही किया जाना चाहिए। शर्मा का कहना है कि अगर 500 साल पहले गुरुनानक देव वहां आए थे, तब वहां ईदगाह नहीं थी। उन्होंने कहा कि पिता का नाम है तो पिता का नाम ही बताएंगे ना, वल्दियत थोड़ी बदल दी जाती है। 500 साल पहले गुरुनानक के आने के पहले टेकरी पर क्या था, कोई बता सकता है क्या? जंगल में नानक जी आए इसीलिए उसे ईदगाह ना कहके गुरुनानक टेकरी कहा जाए। गुरुनानक पहले भोपाल आए थे तो भोपाल की धरती पवित्र हुई। उनका कहना है कि जिस जगह का जो प्राचीन नाम है, उसे उसी नाम से ही पुकारा जाएगा। उनका तो यहां तक कहना है कि जो इस पर राजनीति कर रहा है, वह मूर्ख है, उसको अकल नहीं है। होशंगाबाद को भी नर्मदापुरम कहते हैं। जिसके नाम पर इस

**वाल, चरित्र और चेहरा वाली पार्टी
भाजपा में नेता अपनी डफली-
अपना राग अलाप रहे हैं। मप्र की
राजनीति में अपना सिक्का जमाने
के लिए नेता कई तरह के गड़े मुर्दे
उखाड़ रहे हैं। राजधानी भोपाल में
तो नाम परिवर्तन की राजनीति
इन दिनों जोरों पर है।**

अपनी डफली अपना राग

जिले का नाम रखा गया है, वह होशंग शाह लुटेरा था, लुटेरे के नाम से तो नगर नहीं बसेगा ना। उन्होंने कहा कि लुटेरे की इज्जत करनी है या शहीदों का सम्मान करना है? हलाली डेम का नाम बदलने की उमा भारती की मांग को भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का समर्थन मिल गया है। सांसद का भी इस मामले में कहना है कि हलाली डेम हिंदुओं के हलाल होने की याद दिलाता है। उन्होंने इसके साथ ही लालघाटी और इस्लाम नगर आदि के नाम बदलने की भी मांग की है। उधर इस मामले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी लालघाटी का नाम बदलने की मांग कर चुके हैं।

सूबे की पूर्व मुखिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती भोपाल के समीप स्थित हलाली डेम के नाम में बदलाव चाहती हैं। उन्होंने इसके लिए स्थानीय भाजपा विधायक विष्णु खत्री को एक चिट्ठी भी लिखी है। उमा भारती ने इस चिट्ठी में हलाली शब्द को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए कई अहम बातें लिखी हैं। चिट्ठी में लिखा है कि आपके

विधानसभा क्षेत्र बैरसिया में एक चर्चित स्थल हलाली डेम का नाम बार-बार आता है। जबकि मेरी जानकारी के अनुसार उसका नाम बदल चुका है। भोपाल शहर के बाहर प्रचलित हलाली नाम का स्थान एवं नदी विश्वासघात की उस कहानी की याद दिलाती है जिसमें दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल के आसपास के अपने मित्र राजाओं को बुलाकर उन्हें धोखा देकर उनका सामूहिक कत्ल किया था। उनके कत्ल से नदी लाल हो गई थी। हलाली शब्द और हलाली स्थान उसी प्रसंग का स्मरण कराता है। भोपाल में ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरुनानक टेकरी करने की मांग पर मुस्लिम समाज के साथ-साथ कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। उनका आरोप है कि भाजपा के नेता एक धर्म विशेष को टारगेट कर अपनी राजनीति चमकाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की मांग भाजपा के नेता जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उठा रहे हैं।

उमा ने चिट्ठी में लिखा कि विश्वासघात, धोखाधड़ी, अमानवीयता यह सब एक साथ हलाली शब्द के साथ आते हैं, तो हलाली का इतिहास जानने वालों के अंदर घृणा का संचार होता है। मैंने सुना है कि उसको एक पर्यटन केंद्र बनाया जा रहा है क्योंकि वहां डेम है, नदी है। यह एक बहुत अच्छी बात है। किंतु आप तुरंत संस्कृति एवं पर्यटन विभाग से संपर्क करके घृणा पैदा करने वाले इस नाम का उल्लेख बंद करवा दीजिए। आप इस संबंध में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर से मिलकर भी बात कर सकते हैं। मैं भी इस पत्र की एक कॉपी उनको भेज दूंगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर अटल जंक्शन करने की मांग कर चुके हैं। इसके लिए उनके द्वारा रेल मंत्री को भी एक आग्रह पत्र दिया जा चुका है। प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने प्रमाण और तथ्यों के आधार पर ही ऐतिहासिक धरोहरों के नाम बदलने की बात कही है। उनका पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के हलाली डेम का नाम बदले जाने के पत्र पर कहना है कि उमा भारती के पत्र पर विभाग फैसला लेगा।

● राकेश ग़ोवर

एकमुश्त समझौता योजना

प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार किसानों के हित में योजनाएं बनाने और उन पर बेहतर क्रियान्वयन के लिए काम कर रही है। यही वजह रही कि पिछली भाजपा सरकार में प्रदेश को लगातार पांच बार कृषि कर्मण अवॉर्ड भी मिला। प्रदेश सरकार ने अब राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कर्जदार किसानों को अपनी हजारों हैक्टेयर भूमि छुड़ाने के लिए एकमुश्त समझौता योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बैंक परिसमापन की प्रक्रिया में है और 80 हजार से ज्यादा किसानों से तकरीबन 2600 करोड़ रुपए की वसूली की जानी है। हालांकि इस राशि को प्राप्त करने के लिए और किसानों को बंधक भूमि वापस लौटाने के लिए वर्ष 2017 में समझौता योजना लाई गई थी। जिसमें 20 हजार किसानों ने 83 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाकर करीब 49,500 हैक्टेयर भूमि को मुक्त करा लिया था। दूसरी ओर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अपने खराब प्रबंधन के कारण खुद कर्ज की गिरफ्त में फंस गया और अंत तक वह इससे बाहर नहीं निकल पाया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से शासन की गारंटी पर कर्ज लेकर उसने किसानों को दे दिया था लेकिन वह किसानों से इस कर्ज की वसूली नहीं कर सका। बाद में शासन ने नाबार्ड का तो कर्ज चुका दिया लेकिन सहकारी बैंक का कर्ज अब तक फंसा हुआ है।

किसानों से सहकारी बैंक का कर्ज वसूलने के लिए शिवराज सरकार ने पिछले कार्यकाल में एक योजना लागू की थी। जिसमें तीन किशतों में मूलधन लौटाने पर ब्याज पूरी तरह माफ करने का प्रावधान था। उस दौरान करीब एक लाख किसानों ने लिखित सहमति जरूर जताई थी लेकिन सिर्फ 20 हजार किसानों ने ही कर्ज चुकाया। बहरहाल सरकार की इस योजना से जो उम्मीद थी वह पूरी नहीं हो सकी लेकिन किसानों को इससे 213 करोड़ रुपए की ब्याज माफी जरूर मिली। जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों का कहना है कि भले ही बैंक परिसमापन की प्रक्रिया में है पर किसानों के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है और यह बरकरार रहेगा। बैंक के पास बंधक भूमि को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही उस पर कर्ज लिया जा सकता है। वसूली के लिए सहकारिता विभाग ने प्रस्ताव दिया है कि 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को यह जिम्मा सौंप दिया जाए। वे सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से वसूली करें और उस राशि को सरकार को सौंप दें। इस काम के लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

वर्तमान में जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को किसानों से 2600 करोड़ रुपए लेने हैं। इसमें मूलधन लगभग 700 करोड़ रुपए



कई किशतों में 7669 करोड़ का भुगतान

बीते साल सितंबर में प्रदेश के 37 लाख से अधिक किसानों के खाते में 4688 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि का फसल बीमा के रूप में भुगतान किया गया। प्रदेश में 61.09 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की फसलों का बीमा कराया गया था। इसके लिए बीमा कंपनियों को 2488 करोड़ 69 लाख रुपए के प्रीमियम का भुगतान किया गया था, उसके बाद भी राज्य सरकार को मुश्किल का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई किसानों के खाते में दस-बीस रुपए ही पहुंचे थे। प्रदेश में इस वर्ष किसानों को फसल बीमा के रूप में अब तक कई किशतों में 7669 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, लेकिन अब नियमों में बदलाव के बाद किसानों को कम क्षेत्र में भी फसलों के नुकसान पर कम से कम 5 हजार रुपए तो मिलेंगे ही। यदि अधिक क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ तो फिर उससे अधिक सहायता राशि भी मिलेगी। बदले गए नियम अगले सीजन से लागू करने की तैयारी है।

हैं। वहीं 50 हजार हैक्टेयर से ज्यादा भूमि बैंकों के पास किसानों की बंधक है। इसे छुड़ाने के लिए किसानों को कर्ज चुकाना होगा। जो बिना समायोजन के संभव नहीं है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने एक बार फिर एकमुश्त समझौता योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। जिस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा।

मप्र सरकार शायद देश की ऐसी पहली सरकार है, जिसकी प्राथमिकता में हमेशा से ही किसान कल्याण रहा है। यही वजह है कि सरकार उनके हित में लगातार न केवल योजनाएं बनाती

रहती है बल्कि उनके क्रियान्वयन पर भी पूरा फोकस करती है। इसी तरह का अब एक और कदम प्रदेश सरकार द्वारा फसल क्षति की सहायता के लिए उठाया गया है। इसके तहत अब फसल क्षति के मुआवजे के रूप में न्यूनतम 5 हजार रुपए की राशि देने का प्रावधान कर दिया गया है, जबकि अब तक कई बार तो किसानों को यह राशि 10 से लेकर 20 रुपए तक मिलती रही है।

दरअसल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान होना सामान्य है। इसके लिए अब सरकार द्वारा आरबीसी के प्रावधानों के नियमों में संशोधन कर दिया है। दरअसल यह मामला बीते लंबे समय से लंबित था, लेकिन इस मामले में लगातार हो रही सरकार की फजीहत के बाद आखिरकार सरकार की नौद खुली और उसने उसमें संशोधन कर दिया। इस साल सरकार द्वारा किसानों को फसल बीमा के रूप में अब तक 7669 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है, इसके बाद भी उसे विपक्ष की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा था। इसकी वजह है किसानों को 100 रुपए से भी कम की बीमा राशि का भुगतान होना। इस मामले में अब राज्य सरकार अपनी खुद की फसल बीमा कंपनी का गठन करने पर काम कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया जा चुका है। कंपनी के गठन के लिए शुरू में कम से कम 100 करोड़ रुपए की अंश पूंजी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान किया जा चुका है, लेकिन इसे पर्याप्त न मानते हुए इसकी अंश पूंजी में बढ़ोतरी की जरूरत बताई जाने पर अब उसके गठन के बाद अंश पूंजी में वृद्धि करने पर सहमति बनी है।

● लोकेंद्र शर्मा

6

आगामी बजट शिवराज सरकार के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। चुनौती इस मायने में कि राज्य में खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके मुकाबले आय में वृद्धि नहीं हो पाई है। जनता को राहत पहुंचाने वाली योजनाओं को गति देने के लिए वित्तीय स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संकट के दौरान दिन-रात जुटे हैं। उन्होंने अपनी पूरी टीम को भी मोर्चे पर लगा दिया है। मुख्यमंत्री की सक्रियता और दूरदर्शी सोच के कारण ही राज्य को संकट से उबारने में मदद मिली है।

9



आत्मनिर्भर मप्र पर आधारित बजट

मप्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह उत्साहित दिख रहे हैं, उससे तो यह साफ हो गया है कि प्रदेश का बजट आत्मनिर्भर मप्र पर आधारित होगा। शिवराज सरकार का आगामी बजट निश्चित रूप से प्रदेश की दिशा तय करने वाला होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट शिवराज सरकार के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। चुनौती इस मायने में कि राज्य में खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके मुकाबले आय में वृद्धि नहीं हो पाई है। जनता को राहत पहुंचाने वाली योजनाओं को गति देने के लिए वित्तीय स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संकट के दौरान दिन-रात जुटे हैं। उन्होंने अपनी पूरी टीम को भी मोर्चे पर लगा दिया है। मुख्यमंत्री की सक्रियता और दूरदर्शी सोच के कारण ही राज्य को संकट से उबारने में मदद मिली है। हालांकि वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए बड़े फैसले लेने की जरूरत अभी भी है।

अब तक की तैयारियों से माना जा रहा है कि विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले बजट के जरिए सरकार बड़ा संकल्प जाहिर कर सकती है। सरकार के लिए यह बजट चुनौती के साथ एक बड़ा अवसर भी है। माना जा रहा है कि राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर मप्र का खाका खींचने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस बार का बजट अवसर

सरकार के लिए भी होगा, क्योंकि जोखिम लेकर अभी तक जितने भी प्रयोग किए गए हैं, वे सभी प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए कारगर साबित हुए हैं।

कोरोना संकट से प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है। लगभग सभी क्षेत्रों में राजस्व संग्रहण में वृद्धि हो रही है। यह शुभ संकेत हैं, क्योंकि सरकार ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए जो रोडमैप तैयार किया है, उसके लिए वित्तीय संसाधनों की अधिक जरूरत होगी। इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागों को अतिरिक्त आय सृजित करने के लक्ष्य भी दिए हैं। जीएसटी के बाद राज्य के पास टैक्स लगाने का दायरा सीमित हो गया है। ऐसे में उन विकल्पों पर विचार करना होगा, जिनके माध्यम से सरकार जनता पर कर का बोझ बढ़ाए बगैर आय बढ़ा सकती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने देशभर के नामचीन विषय विशेषज्ञों के साथ मंथन के बाद आत्मनिर्भर मप्र का रोडमैप तैयार किया है। इसमें सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विषम परिस्थितियों में बेहतर प्रबंधन करते आए हैं, वैसा ही इस दौर में भी वे बजट के माध्यम से करेंगे। सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करने के साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए कदम उठाने से वह नहीं झिझकेंगे।

विधानसभा को मिलेंगे नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

22 फरवरी को सत्र के पहले दिन दिवंगतों को निधन के उल्लेख और श्रद्धांजलि के साथ सदन की कार्यवाही स्थगित की जा सकती है। बजट सत्र में विभागवार चर्चा के बाद इसे पारित कराया जाएगा। एक दर्जन विधेयक और अध्यादेशों को विधेयक का रूप देने के लिए प्रस्ताव भी इस सत्र में आएगा। इसके अलावा प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव और शासकीय कार्य भी इस सत्र के दौरान निपटाए जाएंगे। सत्र के पहले ही सप्ताह में नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चयन की कवायद भी की जा सकती है। भाजपा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद अपने पास रखने के मूड में है। उधर, कांग्रेस का कहना है कि अगर भाजपा ने उपाध्यक्ष का पद उसे नहीं दिया तो वह दोनों पदों के लिए चुनाव लड़ सकती है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती वित्त का प्रबंधन करने की है। आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य को मिलने वाले केंद्रीय कर के हिस्से में लगातार कमी हो रही है। वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार से लगभग 63 हजार करोड़ रुपए मिलने का अनुमान था, लेकिन यह घटकर पहले 49,517 करोड़ रुपए हुआ और अब बजट अनुमान 2020-21 में 46,025 रह गया है। यह पूरी राशि भी मिलने की संभावना कम ही है। हालांकि पूर्व में दो प्रतिशत अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति देकर मौजूदा वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने एक तरह से बड़ी राहत दी है। इसकी वजह से कोरोनाकाल में प्रदेश सरकार को आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने में काफी मदद मिली। जाहिर है कि वर्ष 2021-22 में भी इसी तरह अतिरिक्त राशि की दरकार होगी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक प्रतिशत अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति देने की मांग की थी, जिसे मान लिया गया है। आम बजट में राज्यों को एक फीसदी अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी गई है। इससे सरकार लगभग 13 हजार करोड़ रुपए अधिक ऋण ले सकेगी, जो काफी मददगार साबित होगी। सरकार के ऊपर कर्मचारियों की देनदारी साढ़े चार हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनके देयकों के भुगतान के लिए प्रबंध भी करना है।

राज्य की वित्तीय स्थितियों के जानकार मानते हैं कि आगामी बजट का फायदा मुख्यमंत्री एक अवसर की तरह उठाने की कोशिश करेंगे। इसे ध्यान में रखकर ही बजट की तैयारी भी हो रही है। आत्मनिर्भर मद्र के तहत तय किए लक्ष्यों को वर्ष 2023 तक पूरा करने के लिए विभागवार राशि का प्रबंध किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त आय के विकल्प तलाश जा रहे हैं। इसी कड़ी में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन भी किया गया है, जो अनुपयोगी सरकारी संपत्तियों के सदुपयोग की कार्ययोजना पर काम कर रहा है। इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं।

विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली लोक लेखा समिति सदन में आने वाले मामलों पर सिफारिशें कर विभागीय मंत्री और अफसरों को उन्हें पूरा करने की अनुशंसा करती है। लेकिन ऐसी 145 अनुशंसाओं पर भी अब तक विभागों ने कोई काम नहीं किया है, जिसकी वजह से वे अधूरी पड़ी हुई हैं। इनमें वाणिज्यिक कर विभाग की सर्वाधिक 36 सिफारिशों को अब भी पूरा होने का इंतजार बना हुआ है। इसी तरह से लोक निर्माण विभाग से जुड़ी 21, पशुपालन विभाग की 19 और राजस्व विभाग की 14 सिफारिशों के अब भी पूरा होने का



मंत्रियों के 5 सैकड़ा आश्वासनों पर अफसर पड़ रहे हैं भारी

विधानसभा में सरकार की ओर से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर भले ही माननीय खुश हो जाते हैं, लेकिन यह खुशी उनकी अधूरी ही रहती है, इसकी वजह है उनका पूरा न होना। दरअसल संबंधित अफसरों द्वारा ऐसे मामलों में सरकार के आश्वासनों को पूरा करने में रुचि ही नहीं ली जाती है। हालत यह है कि अब सदन के अंदर दिए गए करीब 500 से अधिक आश्वासन अब भी लंबे समय से अधूरे पड़े हुए हैं। दरअसल यह आश्वासन विधानसभा में सवाल-जवाब, ध्यानाकर्षण और बजट तथा अन्य विषयों पर चर्चा के दौरान अक्सर मंत्रियों द्वारा दिए जाते हैं। कुछ आश्वासन तो ऐसे होते हैं जिनमें अफसर यह कहकर रोक लगा देते हैं कि इनका पूरा करना मुश्किल है, तब उन्हें लंबित रख दिया जाता है। इसके अलावा कई आश्वासनों को पूरा करने में अफसर रुचि ही नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वे पूरा ही नहीं हो पाते हैं। अब लंबे समय बाद विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, ऐसे में सरकार के संसदीय कार्य विभाग को एक बार फिर अधूरे आश्वासनों को पूरा करने की याद आई है। यही वजह है कि अब मंत्रियों के आश्वासन और लोक लेखा समितियों की सिफारिशों को पूरा करने के लिए कहा गया है। इस मामले में सबसे खराब हालात पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का है। इस विभाग में सर्वाधिक 80 आश्वासन अधूरे पड़े हुए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर कृषि विभाग है, जिसमें 62 आश्वासनों को पूरा होने का इंतजार है। अन्य विभागों में नगरीय विकास तथा आवास विभाग में 44, गृह विभाग में मंत्रियों के 42 आश्वासनों पर अमल नहीं हुआ है।

इंतजार है। इसके अलावा गृह, नगरीय प्रशासन, वन, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति कल्याण, जलसंसाधन, महिला एवं बाल विकास, खनिज, नर्मदा घाटी विकास, उद्यानिकी, सामाजिक न्याय विभागों से जुड़ी सिफारिशों पर भी अमल नहीं किया गया है।

केंद्र सरकार की ही तरह इस बार मद्र सरकार का आम बजट भी पूरी तरह से पेपरलैस होगा। नए वित्त वर्ष के इस बजट की खासियत यह होगी कि उसमें पूरी तरह से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इस बजट में आत्मनिर्भर मद्र के रोडमैप की पूरी झलक दिखेगी। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने विभाग से जुड़े प्रस्तावों को आत्मनिर्भर मद्र के तहत ही तैयार करने के लिए कहा है।

विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों का कहना है कि बजट सत्र में शासकीय कार्य की अधिकता के कारण यह लंबा चलेगा। इसमें विभागवार अनुदान मांगें पारित होंगी। विधेयक भी प्रस्तुत होंगे और विभिन्न समितियों के चुनाव भी कराए जाएंगे। बजट सत्र के दौरान अध्यादेश के स्थान पर संशोधन विधेयक लाए जाएंगे, जिनमें सहकारी सोसायटी संशोधन, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी संशोधन, वैट संशोधन, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन, मद्र निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन, मद्र भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन, डॉ. बीआर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन, पंडित एसएन शुक्ला विश्वविद्यालय संशोधन, मद्र मोटर स्पिरिट उपकर संशोधन, मद्र हाई स्पीड डीजल उपकर संशोधन, मद्र विनियोग संशोधन और धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक। सदन में इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच रोचक जंग भी देखने को मिलेगी।

● रजनीकांत पारे

साकार होता स्वच्छ जल का सपना

सपनों को संजोना जितना आसान है, उतना ही कठिन है उन्हें साकार करना, लेकिन विगत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन सपनों को संजोया, उन्हें साकार होते भी हम सब देख रहे हैं। चाहे वह हर घर तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों का निर्माण करना हो या फिर उज्वला योजना के तहत माताओं-बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाना। समय रहते इन सभी योजनाओं को घर तक पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। आत्मनिर्भर मद्र के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हर घर नल जल योजना का कार्य तेजी से हो रहा है। हर घर नल जल योजना के तहत अब तक 5.71 लाख घरों को नल कनेक्शन दे चुके हैं, अब मद्र सरकार अगले 4 वर्षों में प्रदेश के हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाएगी। मद्र में कुल 1.21 करोड़ घर हैं। बताते चलें कि 12 नवंबर को शिवराज ने राजधानी में वर्ष 2023 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोडमैप का विमोचन किया था, इस रोडमैप-2023 में मद्र में रोजगार, अर्थव्यवस्था, सुशासन, अधोसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। इस पर 2023 तक अगले 3 साल में काम होगा। परियोजना पूरी होने पर गांव-गांव में प्रारंभ उत्सव मनाया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण अंचल में घर-घर नल से जल पहुंचाया जाना है।

प्रदेश की ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 2605 करोड़ की राशि अतिरिक्त रूप से दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। जल निगम के अंतर्गत राज्य मद से वित्त पोषित 39 समूह जल-प्रदाय योजनाओं के तहत कार्यों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित करने की स्वीकृति भी भारत सरकार से मिल गई है। इन योजनाओं से जुड़े कार्यों के लिए जल शक्ति मंत्रालय से 1326 करोड़ की राशि प्रदेश को प्राप्त होगी। इन 39 समूह जलप्रदाय योजनाओं की कुल लागत 2661 करोड़ है, जिससे 6091 ग्रामों की 64 लाख से अधिक आबादी को नल कनेक्शन के जरिए जलप्रदाय किया जा सकेगा।

मद्र सरकार अगले चार वर्षों में प्रदेश के हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना में 47,500 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च होगी। प्रदेश में कुल 1.21 करोड़ घर हैं। इनमें से अब तक महज 21 लाख घरों में सीधे नल कनेक्शन हैं। शेष आबादी अपने संसाधनों से पानी जुटा रही है। आत्मनिर्भर मद्र के तहत जल पर गठित सब कमेटी ने अपने एक्शन प्लान में यह बात कही है। अहम बात यह है कि इस एक्शन प्लान पर काम शुरू भी हो चुका है। इसके तहत जारी वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 1.81 लाख घरों को



सभी 52 जिलों में 100 प्रतिशत घरों को नल के जरिए पानी

सब कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मद्र में कुल 52 जिले हैं, लेकिन अब तक एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां 100 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन हों। राजधानी होने के बाद भी भोपाल जिले में केवल 17.45 प्रतिशत घरों तक ही सरकार पाइपलाइन बिछाकर पानी दे रही है। मलय श्रीवास्तव कहते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में हम दो जिले निवाड़ी और बुरहानपुर में हर घर को नल कनेक्शन देंगे। 2021-22 में 6 नए जिलों तक 100 प्रतिशत घरों को नल के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। 2022-23 में 24 और इसके बाद 2023-24 में शेष बचे 20 जिलों में हर घर को नल जल से जोड़ा जाएगा। अगले 4 सालों में हर घर नल जल जैसी अतिमहत्वाकांक्षी योजना के लिए 47,500 करोड़ रुपए कैसे जुटेंगे। यह सवाल सभी विशेषज्ञों के मन में उठ रहा है। मलय कहते हैं कि उन्होंने फंड के लिए योजना तैयार कर ली है। 50 प्रतिशत राशि नाबार्ड, एनडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) और जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से कर्ज के रूप में जुटाई जाएगी। शेष राशि लाभार्थियों से ली जाएगी। उनसे केवल लागत का खर्च ही लिया जाएगा। मलय कहते हैं कि इन योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं आ रही है। कोरोना संकट के बाद भी केंद्र से जून माह में पहली किश्त और दूसरी किश्त अक्टूबर में मिल चुकी है।

नल कनेक्शन से जोड़ा गया। दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर में 3.87 लाख घरों तक पाइप के जरिए पानी पहुंचाया गया।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव और जल सब कमेटी के प्रमुख मलय श्रीवास्तव कहते हैं, हमने दूसरी तिमाही के 30 सितंबर तक के लक्ष्य को 31 अगस्त तक ही पूरा कर लिया है। इसके बाद हम 47 हजार अतिरिक्त कनेक्शन दे चुके हैं। 1 अप्रैल से 13 सितंबर तक हम 5.71 लाख घरों को नल कनेक्शन दे चुके हैं। इस साल कुल 26 लाख घरों तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने बताया है कि कर्तव्य के प्रति इच्छाशक्ति से ही उद्देश्य की पूर्ति संभव हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की कुछ जल-प्रदाय योजनाओं को जल जीवन मिशन में शामिल कर अतिरिक्त राशि दिए जाने के निरंतर प्रयासों पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति प्रदान की है। श्रीवास्तव ने

बताया कि इसी तरह जायका के ऋण से मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले के ग्रामों में प्रस्तावित समूह योजनाओं को जल जीवन मिशन से वित्त पोषण के प्रयासों को भी सफलता मिली है। अब जल-प्रदाय की 2558 करोड़ लागत की समूह योजना के लिए भी भारत सरकार ने 1279 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति प्रदान की है। बता दें कि गत दिनों सिंगरौली में आमसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की थी कि 2024 तक हर घर में नल-जल योजना के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी। तब माताओं-बहनों को पेयजल के लिए इधर-उधर भटकना नहीं होगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत खराब गुणवत्ता वाले जल से प्रभावित बस्तियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ताकि फ्लूरोसिस और आर्सेनिकोसिस के दुष्प्रभावों में कमी लाई जा सके।

● सुनील सिंह

म प्र के तीन प्रमुख अंचलों के विकास के लिए पूर्व में भाजपा की शिवराज सरकार के समय गठित किए गए तीनों विकास प्राधिकरणों को बंद करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव की तैयारी बीते साल कर ली गई थी। हालांकि इस पर अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन अघोषित रूप से यह प्राधिकरण बंद ही पड़े हुए हैं। हालत यह है कि न तो इनमें कोई पदाधिकारी लंबे समय से है और न ही बजट में इनके लिए किसी तरह की कोई राशि का प्रावधान किया गया है। यही वजह है कि अब यह तीनों शोभा की सुपारी बन चुके हैं। जनता की जगह राजनीतिक फायदे के लिए गठित किए गए इन प्राधिकरणों को लेकर सरकार की अरुचि इससे ही समझी जा सकती है कि बीते डेढ़ दशक में इन्हें पर्याप्त बजट तक नहीं दिया गया। यही नहीं दो मौकों को छोड़ दिया जाए तो सरकार उनमें राजनीतिक स्तर की नियुक्तियां तक ही नहीं कर सकी है।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश में 10 विकास प्राधिकरण भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, कटनी, अमरकंटक और सिंगरौली नगरों में स्थित हैं, जबकि पांच विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी साडा) ग्वालियर काउंटर मेनेट, पचमढी, खजुराहो, महेश्वर-मंडलेश्वर तथा ओरछा में स्थित हैं। ये सभी प्राधिकरण अपने-अपने क्षेत्र के विकास में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इन प्राधिकरणों की तर्ज पर वर्ष 2007-08 में प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा महाकौशल, बुंदेलखंड और विंध्य विकास प्राधिकरण का अलग-अलग गठन किया गया था। यह समय प्रदेश में होने वाले आम विधानसभा चुनाव के ठीक पहले का था। यही वजह है कि लोगों का तो ठीक सरकार की उपेक्षा के चलते नेताओं में भी इनको लेकर कोई रूचि नहीं रह गई। सरकार ने इनका गठन किया और फिर उनसे पूरी तरह से मुंह फेर लिया जिसके चलते इनका अपना कोई भवन भी अब तक नहीं बन सका है, लिहाजा अंचलों के विकास का जिम्मा उठाने वाले यह प्राधिकरण खुद ही विकास की राह देखने को मजबूर बने हुए हैं। अब तो हालत यह है कि इनमें नाम के लिए ही कर्मचारी रह गए हैं। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का दफ्तर तो महज एक कमरे तक ही सीमित रह गया है। यही नहीं उसमें भी तीन निचले स्तर के ही कर्मचारी हैं।

खास बात यह है कि अब तो सरकार इनको बंद करने की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए दो माह पहले प्रस्ताव तक तैयार कर लिया गया है। यह प्रस्ताव योजना विभाग द्वारा तैयार किया गया है। दरअसल इनके गठन के बाद से ही यह प्राधिकरण सरकार की प्राथमिकता में कभी नहीं रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार



बंद होंगे तीन विकास प्राधिकरण

कई प्राधिकरण भ्रष्टाचार की गिरफ्त में

प्रदेश के ज्यादातर शहरों के प्राधिकरण अब सफेद हाथी की तरह हो गए हैं। घोटालों से दागदार और कंगाल हो चुके प्राधिकरणों के अस्तित्व पर सवाल उठना लाजिमी है। इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) में कई भ्रष्टाचार सामने आ चुके हैं। घोटालों के मामले में भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) भी पीछे नहीं है। बागमुगलिया इलाके में बीडीए के अधिकारियों ने 125 एकड़ जमीन को गलत तरीके से अनापत्ति प्रमाणपत्र देकर कब्जा छोड़ दिया। बाद में यहां बिल्डरों ने शॉपिंग मॉल और आवासीय क्षेत्र विकसित करके करोड़ों रुपए कमाए। इस मामले की जांच दबा दी गई। ग्वालियर विकास प्राधिकरण (जीडीए) तो अभूतपूर्व घोटालों को अंजाम दे रहा है। जीडीए ने आवासीय कॉलोनियां विकसित करने के लिए सरकारी जमीन का अधिग्रहण किया था। बाद में यह जमीन निजी कॉलोनियाइजर्स को दे दी गई। ऐसी दो दर्जन से ज्यादा गृह निर्माण समितियों का घोटाला जब सामने आया तो उनकी फाइलें जीडीए से गायब हो गईं। जीडीए ने अनुमान लगाए बिना ही कई इलाकों में मकान-दुकानों का निर्माण करवा दिया, लेकिन यहां इन्हें खरीदार ही नहीं मिल रहे। करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए शॉपिंग मॉल में कोई दुकान नहीं खरीद रहा है। जबलपुर, उज्जैन और देवास के प्राधिकरण भी ऐसे की कमी से जूझ रहे हैं और घोटालों के आरोपों से दो-चार हो रहे हैं।

के 15 और भाजपा की शिवराज सरकार के एक साल में अब तक इनमें से किसी में भी कोई राजनीतिक नियुक्ति तक नहीं की गई है। दरअसल

इन प्राधिकरणों का गठन उस समय विधानसभा के आम चुनाव के ठीक पहले राजनीतिक फायदे के लिए किया गया था। यह वह समय था, जब प्रदेश में पृथक बुंदेलखंड और विंध्य को नया प्रदेश बनाने की मांग जोर पकड़ रही थी।

इन तीनों में शामिल विंध्य और महाकौशल में आठ-आठ तो बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण में नव गठित निवाड़ी शामिल होने के बाद अब सात जिले आते हैं। इनमें से अधिकांश जिले बेहद पिछड़ेपन का शिकार हैं। यही नहीं महाकौशल और विंध्य के तहत आने वाले कई जिले आदिवासी बाहुल्य भी हैं। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के तहत सागर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दतिया, विंध्य विकास प्राधिकरण के तहत रीवा, शहडोल, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर और उमरिया आदि जिले जबकि महाकौशल विकास प्राधिकरण के तहत जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, कटनी और छिंदवाड़ा जैसे जिले आते हैं। इसके बाद भी सरकार की अरुचि बनी हुई है। फिलहाल इन प्राधिकरणों का जिम्मा लंबे समय से अफसरों के हाथों में बना हुआ है।

खास बात यह है कि अब तक एक बार ही सर्वाधिक 30 करोड़ की राशि इन तीनों प्राधिकरणों को दी गई है। उसके बाद तो राशि में जो कटौती का दौर शुरू हुआ तो थम ही नहीं रहा है। इन तीनों ही प्राधिकरणों के तहत 23 जिले आते हैं। इनकी संख्या लगभग प्रदेश के आधे जिलों के बराबर होती है। अगर औसत निकाला जाए तो एक जिले के खाते में महज सवा करोड़ रुपए ही आते हैं। इसके बाद तो यह राशि इतनी कम कर दी गई की उसका उल्लेख करने में भी शर्म आने लगती है। यही नहीं अब तो नए कामों के लिए बजट ही नहीं दिया जा रहा है।

● विकास दुबे

20 जिलों में लगाई कटाई पर रोक

मप्र में की जा रही अंधाधुंध कटाई के चलते लगातार तेजी से हरियाली समाप्त हो रही है। यही वजह है कि अब प्रदेश में वन कटाई के मामले में केंद्र सरकार द्वारा सख्त रुख दिखाना शुरू कर दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने मप्र के 20 जिलों में पूरी तरह से इस तरह की कटाई पर रोक लगा दी है। दरअसल प्रदेश में पेड़ कटाई करने के बाद भी उसके एवज में नए पेड़ लगाने में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। इस मामले में प्रदेश सरकार का रुख भी गंभीर नहीं है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने केंद्र से एक लाख 24 हजार हैक्टेयर के इलाके में वन कटाई की अनुमति केंद्र से मांगी थी। खास बात यह है कि प्रदेश का वन महकमा उन जिलों में कटाई की योजना बना चुका था, जिन जिलों के वन क्षेत्रों में पहले से ही ग्रीनरी बहुत कम बची है। इस प्रस्ताव पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पूरी तरह से पेड़ कटाई पर रोक लगा दी है। दरअसल प्रस्ताव में प्रदेश सरकार ने वन महकमे की ओर से 20 जिलों के 2400 कूपों में पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा था।

फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि मप्र में भोपाल सहित लगभग 28 जिले ऐसे हैं, जिनमें ग्रीनरी बेहद कम हो चुकी है। दरअसल इसकी बड़ी वजह है बीते कई सालों में वर्किंग प्लान से ज्यादा पेड़ों की कटाई की जाना। यही नहीं इसकी दूसरी जो वजह मानी जा रही है वह है इन क्षेत्रों में अत्याधिक मात्रा में अवैध कटाई का होना। प्रदेश के वन महकमे द्वारा बीते साल मई-जून 2020 में प्रदेश के 20 जिलों में लगभग एक लाख 24 हजार हैक्टेयर में वन कटाई की अनुमति केंद्र के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से मांगी गई थी। इस पर आपत्ति लगाते हुए कार्यालय ने सरकार के सामने तीन शर्तें रख दीं। इसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि फॉरेस्ट सर्वे इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जिन जिलों में ग्रीनरी कम हुई है वहां पेड़ नहीं काटे जाएं। इसके अलावा सूखे पेड़ों को काटने के बदले में हरे पौधों को उस जगह पर लगाया जाए। तीसरी शर्त में पेड़ों की कटाई के इलाकों की वर्तमान में ग्रीनरी की स्थिति की जानकारी देना शामिल है।

मप्र देश का शायद ऐसा पहला राज्य है, जहां पर सरकार द्वारा सैकड़ों करोड़ की राशि खर्च करने के बाद भी हरियाली बढ़ने की जगह तेजी से कम हो रही है। इनमें भी प्रदेश के डेढ़ दर्जन जिलों में तो हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इन जिलों में दो साल के अंदर ही करीब 60 वर्ग किमी के दायरे में हरियाली साफ हो चुकी है। यह खुलासा हुआ है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की सर्वे रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मप्र में पौधरोपण में होने वाली औपचारिकता



गायब हो चुके हैं करोड़ों पौधे

खास बात यह है कि सरकारी प्रयासों के तहत वन विभाग और अन्य संस्थानों द्वारा बीते पांच सालों में प्रदेश में 40 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का दावा किया गया है, लेकिन इनमें से आधे पौधे तो मर चुके हैं। यही नहीं वन विभाग के पास जीवित बचे पौधों का भी कोई ठीक-ठीक आंकड़ा तक नहीं है। प्रदेश में करीब द्वादस साल पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी तो पौधरोपण की जांच जरूर शुरू की गई थी, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री स्तर पर उस पर फैसला नहीं लिए जाने की वजह से कुछ भी नहीं हो सका और अब सरकार बदलने के बाद मामले को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वन विभाग और अन्य संस्थानों द्वारा पिछले पांच सालों में प्रदेश में 40 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं, लेकिन 20 करोड़ भी जिंदा नहीं बचे हैं। वन विभाग के पास जीवित बचे पौधों का ठीकठीक आंकड़ा तक नहीं है, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञ बताते हैं कि 50 फीसदी से कम पौधे ही जीवित रह पाते हैं। इस साल 10 करोड़ 25 लाख पौधे लगाने की योजना है। इनमें से सात करोड़ पौधे नर्मदा कैचमेंट के 16 जिलों में रोपे गए थे। इनमें से 20 फीसदी से ज्यादा पौधे नष्ट हो गए हैं। लिहाजा विभाग ने सभी मैदानी वन अफसरों को पौधों की सुरक्षा करने को कहा है।

और लापरवाही की वजह से प्रदेश में हरियाली का दायरा नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि इस पर हर साल सरकार द्वारा सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इस मामले में संस्थान ने प्रारंभिक रिपोर्ट वन विभाग को भेजकर आंकलन करने की नसीहत दी है। विभाग की आंकलन रिपोर्ट मिलने के बाद संस्थान द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाएगा। संस्थान द्वारा इस तरह का सर्वे हर दो साल में किया जाता है।

प्रदेश के जिन डेढ़ दर्जन जिलों में हरियाली कम हुई है उनमें से अधिकांश जिले आदिवासी बाहुल्य हैं। इन जिलों के वन क्षेत्र में जंगलों को अत्याधिक नुकसान पहुंचाया गया है। संस्थान की रिपोर्ट में कहा गया है कि वन अधिकार कानून लागू होने के बाद तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है। यही नहीं इन इलाकों में अतिक्रमण भी तेजी से हो रहा है। वन विभाग से जुड़े सूत्रों की मानें तो वर्ष 2017 और 2019 के बीच प्रदेश में 60 वर्ग किमी हरियाली कम हो चुकी है। इस मामले में प्रदेश की राजधानी होने के बाद भी भोपाल में

हालात बेहद खराब हैं। यहां पर भी तेजी से हरियाली कम हो रही है। अगर इसका आंकलन करें तो शहर में बीते बीस सालों के अंदर हरियाली में 44 प्रतिशत की कमी आई है। इसका सीधा असर पर्यावरण में असंतुलन, गिरते जलस्तर और बढ़ते तापमान के रूप में सामने आ रहा है। इसके बाद भी सबक न लेते हुए विकास के नाम पर अब भी आगे लगातार पेड़ों की कटाई जारी रहने का अनुमान है। हैरत की बात है कि प्रदेश में 60 वर्ग किमी हरियाली घटी है और ये वन क्षेत्र आदिवासी बहुल 18 जिलों में आता है। संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है। इस हिसाब से आदिवासी बहुल इलाकों में जंगलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वन अधिकार कानून आने के बाद पेड़ों की कटाई में तेजी आई है। वहीं अतिक्रमण भी बढ़ा है। वन विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2017 और 2019 के बीच प्रदेश में 60 वर्ग किमी हरियाली घटी है।

● जितेंद्र तिवारी

देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में महिलाओं के लिए स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया गया है। 400 क्वायर फीट में बन रहे सुविधाघर में अलग से फीडिंग रूम की भी व्यवस्था है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि महिलाओं की निजता, गरिमा, सम्मान, सुरक्षा, सशक्तिकरण और अधिकारों के मुद्दे पर केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारों तक बड़ी-बड़ी बातें और नारे तो खूब देती हैं, लेकिन यह वास्तव में महिला मुद्दों, उनकी बुनियादी जरूरतों को लेकर कितनी संजीदा हैं, इसकी हकीकत गत दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश ने सामने लाकर रख दी है।

दरअसल हाईकोर्ट ने उप्र की सरकार से यह सवाल पूछ लिया है कि वह यह बताए कि राज्य के कितने पुलिस थानों में महिला शौचालय हैं।

बता दें कि उप्र पुलिस थानों में महिलाओं के लिए शौचालय या खराब स्थिति के मामले में देश में चौथे स्थान पर है। उप्र ही क्यों मप्र और बिहार जैसे राज्यों के भी बुरे हाल हैं। मप्र में तो 60 फीसदी से ज्यादा पुलिस थानों में महिला शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। शौचालय की सुविधा न मिलने के कारण महिला पुलिसकर्मी कम पानी पीती हैं और शरीर में पानी की कमी के कारण कई बीमारियों का शिकार हो जाती हैं।

क्या यह सरकारों और सिस्टम का अमानवीय और संवेदनहीन चेहरा नहीं है, जो महिलाओं की गरिमा और सम्मान की बात तो करता है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ के नारे भी खूब लगाता है, लेकिन इंतजाम कुछ नहीं करता। क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की बेकद्री की पोल नहीं खोलता, जिसे लेकर वह बेहद गंभीर रहते हैं और हमेशा स्वच्छता के लिए मिशन मोड पर होने की बात करते हैं। शायद तमाम सवालियों की तरह यह सवाल भी दबा ही रह जाता, अगर कानून की पढ़ाई करने वाली उप्र की अंजिल पांडे और उनके कुछ साथी उप्र के पुलिस थानों में महिला शौचालय न होने या उनकी बदहाली को लेकर एक जनहित याचिका के माध्यम से ध्यान आकर्षित न करते।

इसी याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय यादव और जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने आदेश देते हुए उप्र की सरकार से जवाब मांगा है। इस याचिका में प्रयागराज शहर के थानों में महिलाओं के लिए शौचालय बनाने और जो बने हैं, उन्हें दुरुस्त कराने की मांग भी की गई है। याचियों का कहना है कि पुलिस थानों में महिला शौचालय न होना महिलाओं की गरिमा व निजता के अधिकार का उल्लंघन है। बता दें कि स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019 शीर्षक



60 फीसदी थानों में महिला शौचालय नहीं



महिला कर्मी हो रहीं बीमार

अलग शौचालय की व्यवस्था न होने से महिला पुलिस कम पानी पीती हैं, ताकि बिना किसी व्यवधान के ज्यादा समय तक ड्यूटी करने की हालत में रह सकें, इससे वह कई तरह की बीमारियों की शिकार हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि महिला पुलिसकर्मीयों की इन दिक्कतों से आला अधिकारी अनजान हों, लेकिन इन व्यवस्थाओं को करने की दिशा में किसी का ध्यान नहीं जाता। न ही यह पता किया जाता है कि कितने थानों में सुविधा है, कितनों में यह सुविधा करानी है। 2017 में प्रदेशभर के पुलिस कर्मियों की एक कार्यशाला में थानों में महिला शौचालयों का मुद्दा उठा था, अफसरों ने भी थानों में व्यवस्थाओं में कमी की बात मानी थी, लेकिन इस दिशा में सबसे आज तक हुआ कुछ नहीं।

वाली रिपोर्ट दिसंबर 2019 में जारी की गई थी। उसके अनुसार 20 फीसदी पुलिसकर्मीयों ने पुलिस स्टेशनों में महिला शौचालयों की कमी की शिकायत की थी। इस सर्वेक्षण में 21 राज्यों में 12000 पुलिसवालों को शामिल किया गया था। इस रिपोर्ट में उप्र को महिला शौचालयों की कमी या खराब स्थिति के मामले में चौथे स्थान पर बताया गया था।

बदहाली की ये स्थिति केवल उप्र की ही नहीं है, बल्कि मप्र के भी ऐसे ही हाल हैं। मप्र के भी 60 फीसदी से ज्यादा थानों में महिला पुलिसकर्मीयों के लिए अलग से शौचालय नहीं हैं। ड्यूटी पर आने के बाद उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती और मुश्किल यह होती है कि वह शौचालय कहाँ जाएं। ऐसी स्थिति में उन्हें बार-बार घर जाने के लिए अफसर से पूछना

पड़ता है, जिसके लिए उन्हें कई बार डांट भी पड़ जाती है और शर्मिंदगी भी झेलना पड़ती है।

बता दें कि मप्र में 2018 की आधिकारिक जानकारी के अनुसार 1095 पुलिस थाने हैं। अकेले राजधानी भोपाल में 40 से अधिक थाने हैं। हर थाने में औसतन 4 महिला पुलिसकर्मीयों की तैनाती है, लेकिन उनके लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कई थानों में महिला पुलिसकर्मीयों के सैल्यूट करते हुए पोस्टर्स दिख जाएंगे, जिन पर लिखा होगा कि 'हम उन्हें सलाम करते हैं, जो कानून का सम्मान करते हैं,' लेकिन पुलिस तंत्र खुद इन महिलाओं का कितना सम्मान करता है, ये महिला शौचालयों का न होना बताता है। अधिकांश थानों में कॉमन शौचालय हैं, जिनका उपयोग पुलिस वालों से लेकर उसकी अभिरक्षा में रखे गए आरोपी तक सभी करते हैं। ये शौचालय महिला पुलिसकर्मीयों, महिला फरियादियों या अभिरक्षा में रखी गई महिलाओं के लिए कितने सुरक्षित होते हैं, स्वतः ही अनुमान लगाया जा सकता है। महिला पुलिसकर्मीयों के लिए अलग से शौचालय न होना अकेले भोपाल की नहीं, पूरे प्रदेश की समस्या है, चाहे देश में स्वच्छता के मामले में देशभर में नंबर वन रहा इंदौर हो या फिर आगरा-मालवा, ग्वालियर, जबलपुर हो, सब जगह एक जैसे हाल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2015 में राज्य के थानों में महिलाओं के लिए रेस्ट रूम समेत शौचालय बनाने की घोषणा की थी, 40 करोड़ का बजट भी बना, लेकिन तब वित्त विभाग के रोड़े से काम अटक गया। विधानसभा या सड़क पर तमाम मुद्दे तो उठाता है, लेकिन महिलाओं, बच्चों से जुड़े मुद्दों पर आवाज बिरले ही सुनाई देती है।

● धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया

बाघों को मिलेगा नया क्षेत्र

मप्र में एक तरफ बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ उनकी मौत भी हो रही है। बाघों की मौत का एक बड़ा कारण है आपसी लड़ाई। दरअसल, बाघों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उनका निवास क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है।

ऐसे में बाघों के बीच टेर्रेटरी को लेकर जानलेवा लड़ाई होती है। जिससे बाघों की मौत के मामले बढ़े हैं। ऐसे में सरकार अब बाघों के निवास क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए कॉरिडोर प्रबंधन किया जा रहा है। मप्र में बाघों की सुरक्षा और उनकी वंशवृद्धि के लिए संरक्षित क्षेत्रों के बीच सुरक्षित कॉरिडोर की जरूरत महसूस होने लगी है। वन विभाग की ताजा रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश के 11 जिलों में बाघों की आवाजाही बढ़ गई है। इनमें कुछ ऐसे जिले भी हैं, जिनमें पहले कभी बाघ नहीं देखे गए। ऐसे हालात में संरक्षित क्षेत्रों में बाघों के बीच वर्चस्व की लड़ाई की आशंका बढ़ गई है। बाघों के प्रदेश की सीमा से बाहर जाने का एक कारण यह भी बताया जा रहा है।

टाइगर एस्टीमेशन 2018 के तहत प्रदेश में 526 बाघ हैं। यह आंकड़ा पिछले चार साल में बढ़ा है, क्योंकि वर्ष 2014 की गणना में प्रदेश में 308 बाघ पाए गए थे। इसके साथ ही प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र, कान्हा, बांधवगढ़ एवं पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या पार्कों की क्षमता से ज्यादा हो गई है तो सामान्य वनमंडलों में भी बाघ दिखाई देने लगे हैं। भोपाल की ही बात करें तो यहां चार नए बाघ देखे जा रहे हैं। इन्हें मिलाकर भोपाल के आसपास 18 बाघों का मूवमेंट बताया जा रहा है। ऐसे ही बालाघाट के जंगलों में 40 बाघ बताए जा रहे हैं। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर डैम के नजदीकी क्षेत्रों में भी बाघों का मूवमेंट देखा जा रहा है। इस क्षेत्र में दो साल पहले तक बाघ नहीं थे। क्षेत्र को बाघों से आबाद करने के लिए इन क्षेत्रों में तीन साल पहले चीतल शिफ्ट किए गए थे। वन्यजीव विशेषज्ञ एके खरे बताते हैं कि जंगलों में संख्या बढ़ने के कारण बाघ बाहर आ रहे हैं तो उनके रास्ते का माहौल भी जंगल जैसा ही हो। दो संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले रास्ते में जंगल खड़ा करना होगा। ताकि उनके मूवमेंट के दौरान बाघ-मानव का सामना न हो।

देश में सबसे ज्यादा 526 बाघ होने का तमगा हासिल कर टाइगर स्टेट बने मप्र में बाघों की मौत का आंकड़ा कम करने के जतन शुरू हो गए हैं। बाघों की मौत की मुख्य वजह उनका संरक्षित क्षेत्रों (टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, अभयारण्य) से बाहर निकलकर आना ही है। इस पर तभी रोक लग सकती है, जब संरक्षित क्षेत्रों के बीच सुरक्षित कॉरिडोर (जंगल में गलियारा) हो और राज्य सरकार इसी पर काम कर रही है। मंडला जिले के कान्हा नेशनल



कूनो में लाए जाएंगे दक्षिण अफ्रीका से चीते

उधर, वन्य प्राणियों में रुचि रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। इस साल के अंत तक मप्र के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से सात चीते आ जाएंगे, इनमें चार मादा और तीन नर चीते शामिल हैं। तब तक कूनो प्रबंधन साढ़े चार सौ वर्ग किलोमीटर वनक्षेत्र से कांटेदार बबूल के पेड़ हटाने के साथ फेंसिंग लगाने जैसे काम करेगा। इस संबंध में भोपाल से वन विभाग के अवर सचिव का एक पत्र दो फरवरी को डीएफओ पीके वर्मा के पास आया है। उन्हें तैयारियां करने और भोपाल आकर चर्चा करने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2020 में सेंट्रल इंपावर कमेटी की सब कमेटी में शामिल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. वाय वी झाला की टीम ने कूनो पार्क का निरीक्षण किया था। पार्क को चीतों लिए सबसे अधिक मुफीद पाया था। टीम ने भोपाल और दिल्ली में रिपोर्ट दी थी। भारत में कूनो-पालपुर नेशनल पार्क पहला पार्क होगा, जहां चीते आएंगे। इसकी मुख्य वजह यह है कि पार्क चीतों के रहवास और भोजन के लिए पूरी तरह अनुकूल है। चीतों का पसंदीदा भोजन चिंकारा और काला हिरण होता है, जो यहां बहुतायत में पाए जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार चीता को शिकार करने के लिए छोटे वन्यप्राणी और लंबे खुले मैदान वाला क्षेत्र चाहिए। उन्हें छिपने के लिए घास की जरूरत होती है, जो यहां मौजूद है। इन्हें और बढ़ाया जाएगा। फिलहाल दुनिया में मौजूदा समय में सात हजार से ज्यादा चीते हैं। इनकी बड़ी संख्या अफ्रीकी देशों में ही पाई जाती है।

पार्क, उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क और सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व को एक-दूसरे से जोड़ा जा रहा है।

बाघों की एक से दूसरे जंगल में सुरक्षित आवाजाही के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने प्रदेश में 11 संभावित कॉरिडोर तलाश किए हैं, जो घने जंगल और मैदानी क्षेत्रों के माध्यम से प्रदेश के अन्य कोनों पर स्थित दूसरे संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ते हैं। अब इन्हीं का प्रबंधन किया जाना है। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि ये कॉरिडोर सुरक्षित कर लिए गए, तो बाघों का जंगल से बाहर निकलना बहुत कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, बाघ-मानव द्वंद्व की स्थिति भी नहीं बनेगी। प्रदेश के सभी संरक्षित क्षेत्रों के वन्यजीव प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार राशि देती है, पर इन क्षेत्रों के बाहर प्रबंधन के लिए कोई राशि नहीं मिलती। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने अलग बजट का प्रावधान भी किया है।

एक से दूसरे नेशनल पार्क तक बने कॉरिडोर में घास, पानी की उपलब्धता और आगजनी की घटनाएं रोकने पर काम होगा। कॉरिडोर में जहां खुला क्षेत्र (खेत या मैदान) आ रहा है, वहां वनभूमि और राजस्व भूमि पर पौधे रोपने की रणनीति बनी है। इसके अलावा जिन कॉरिडोर में बाघों की ज्यादा आवाजाही है, वहां से गांव भी शिफ्ट किए जाने हैं। कान्हा एवं पेंच कॉरिडोर से एक गांव हटा भी दिया गया है। बाघों के रास्ते का गतिरोध अंडरपास और ओवरपास भी खत्म करेंगे। संरक्षित क्षेत्र या व्यस्ततम कॉरिडोर से सड़क, रेलवे लाइन, नहर आदि बाधाएं इन्हीं के माध्यम से दूर होंगी। जंगल में होने वाले ऐसे नए कार्यों में ये शर्तें जोड़ी जा रही हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व के बीच से गुजर रहे नेशनल हाईवे-सात और रातापानी टाइगर रिजर्व से गुजर रही रेलवे लाइन के लिए ये शर्तें लगाई गई हैं।

● श्याम सिंह सिकरवार

जल संचय से बदल दी तस्वीर



मडियों में जखनी के स्वाद्यान्न की बढ़ी मांग

सामुदायिक आधार पर चला यह सिलसिला यहीं नहीं रुका, गल्ला मडियों में जखनी के किसानों के धान को अधिक मूल्य और सम्मान मिला, तो सब्जी मंडी में भिंडी, बैंगन, प्याज, टमाटर की सर्वाधिक मांग होने लगी। इससे प्रभावित होकर आसपास के लगभग 50 गांवों के सैकड़ों किसानों ने भी जखनी की तरह खेती करने का संकल्प लिया और उन्होंने हजारों बीघा जमीन की अपने संसाधनों से मेड़बंदी कर दी और यहीं से जलग्राम जखनी की जलक्रान्ति सूखे बुंदेलखंड में फैलने लगी। गांव से पलायन कर गए नौजवान अपने खेतों में बिना मजदूरों के स्वयं काम करने लगे। तालाबों में मछली पालन, दुग्ध उत्पादन और कृषि आधारित रोजगारों से गांव खुशहाल होने के साथ-साथ स्वावलंबी बनने लगा। पिछले पांच वर्षों एक मीटर 34 सेंटीमीटर जिले का भू-जलस्तर बढ़ा है। ऐसी रिपोर्ट माइनर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उग्र ने दी है। आज सरकार सूखे बुंदेलखंड के चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालोन, झांसी, छतरपुर में सरकारी धान खरीद सेंटर बनाकर धान खरीद रही है। अब यहां पानी की वजह से लाखों क्विंटल धान पैदा होता है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 वर्षों में किसानों ने फसल बोने का रकबा बुंदेलखंड में मेड़बंदी करके तीन लाख हेक्टेयर से अधिक बढ़ाया है। आज बुंदेलखंड आत्मनिर्भर हो रहा है। यहां के किसानों की अपनी मेहनत की वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें उनके साथ खड़ी हैं।

सकता है, संरक्षण से पानी बचाया जा सकता है।

उमाशंकर ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पूरे गांव के खेतों की मेड़बंदी की और पानी की फसल बोने का पुरखों का मंत्र सिद्ध किया। मेड़बंदी के बाद अब बारी थी कि जल की निरंतर प्राप्ति के लिए पानी की फसल कैसे बोई जाए, कैसे पानी

की खेती की जाए। जिसके लिए उमाशंकर ने समुदाय के साथ गांव के पानी का मैनेजमेंट किया, गांव के तालाबों को पुनर्जीवित करवाया राज समाज सरकार को साथ लिया और खेतों की मेड़ से निकलने वाले अतिरिक्त पानी और गांव के बचे पानी का रुख तालाबों की ओर मोड़ दिया। यानी खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। गजब की सोच! पहली बारिश होते ही वर्षा की बूंदें जहां गिरीं, वही उन्हें रोककर संचित किया। ऊंची मेड़ों के कारण जमीन ने जी भरकर पानी पिया। खेतों का पेट भरने के बाद बाहर निकलते पानी ने तालाबों का रुख किया। तालाब पानी से भरने लगे। गांव के सभी 6 तालाब पानी से लबालब भर गए। यही नहीं, तालाबों के भरने से गांव के 30 कुएं भी अपना यौवन दिखाते लगे और कुओं का जलस्तर भी 15 से 20 फीट पर पहुंच गया।

गांव वालों का हौसला बढ़ा, तो काम यहीं नहीं रुका। उन्होंने मेड़-मेड़ पर पौधरोपड़ का काम शुरू कर दिया। लहलहाती फसलों के बीच धीरे-धीरे पेड़ झुमने लगे। मानों कह रहे हों कि अब बादलों से पानी लाने का काम हमारा और उसे रोकने का काम तुम्हारा। इस गांव को खुशहाल बनाने के लिए उमाशंकर पांडे को पूरे गांव के साथ लंबा संघर्ष करना पड़ा। और आखिरकार सूखे बुंदेलखंड में लगातार 21 वर्षों की मेहनत रंग लाई। इस जखनी गांव में कभी खेती नहीं हो पाती थी, लेकिन आज इस गांव में रिकॉर्ड फसल उत्पादन होता है। पिछले वर्ष ही जखनी के किसानों ने 21,000 क्विंटल बासमती धान और 13,000 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया। इस तरह गेहूं, धान, चना, तिलहन, दलहन के साथ-साथ सब्जी, दूध और मछली पालन से जखनी के किसान अब समृद्ध और साधन-संपन्न होने लगे हैं। यहां तक कि चार बीघे के छोटे-से-छोटे किसान के पास भी आज अपना ट्रैक्टर है, वह भी बिना किसी कर्ज के।

● सिद्धार्थ पांडे

वर्तमान में मध्य भारत का सूखाग्रस्त बुंदेलखंड ऐसा क्षेत्र है, जहां सूखे के दौरान सरकारों ने मालगाड़ी के जरिए पीने का पानी भिजवाया। यह एक ऐसा स्थान है जहां, जल संसाधनों की प्रचुरता है और कभी यहां पानी की मात्रा प्रचुर थी। करीब 35 छोटी-बड़ी नदियां यहां हैं, जिनमें पांच बड़ी और 30 प्रदेश स्तर की हैं। इतना ही नहीं, यहां करीब 125 छोटे-बड़े बांध हैं, 27,000 तालाब हैं, 52,000 कुएं, 300 नाले, 150 बावड़ियां और चंदेल, बुंदेल राजाओं द्वारा स्थापित लगभग 51 परम्परागत और प्राकृतिक जल संसाधन और अनुसंधान केंद्र हैं। एशिया की सबसे बड़ी ग्रामीण पेयजल योजना पाठा चित्रकूट बुंदेलखंड में ही है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जल की तमाम योजनाओं में अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी बुंदेलखंड आज प्यासा क्यों है? आखिर यहां मालगाड़ी से पानी भेजने की नौबत क्यों आई? क्या कारण रहा है कि सरकारों के अनेक प्रयासों के बावजूद भी समस्या ज्यों-की-त्यों बनी रही। सरकारों ने अपना काम किया, लेकिन जिनके लिए काम किया, उस समाज ने उन कामों के प्रति क्या जिम्मेदारी दिखाई? भू-जल संरक्षण करना सरकार का नहीं, समाज का काम है। लेकिन सरकार के कार्यों में उन्होंने क्या सहयोग किया? क्या केवल भोगी बनकर उपभोग किया और उपलब्ध कराए गए संसाधनों का दोहन करके सरकारों के भरोसे छोड़ दिया? सवाल यह है कि हम दिए गए संसाधनों से समस्या का स्थायी समाधान निकालकर गांव, शहर, प्रदेश और देश की उन्नति में सहायक बने अथवा नहीं? शायद नहीं। वहीं सरकारों ने भी इस बारे में बेहतर तरीके से नहीं सोचा। क्योंकि यदि ऐसा पुरानी सरकारें सोचतीं, तो सरकार को बुंदेलखंड में पीने का पानी मालगाड़ी से नहीं भेजना पड़ता। पानीदार बुंदेलखंड फिर से पानी के लिए आत्मनिर्भर होता, स्वावलंबी होता। इन तमाम घटनाओं के बावजूद इनका उपाय अंधेरा-अंधेरा कह देने की बजाय एक छोटा-सा दीपक लेकर उजाला करने में छुपा है।

दृढ़ संकल्पित उमाशंकर पांडे के नेतृत्व में बुंदेलखंड के बांदा जिले के जखनी गांव के लोगों ने अपना भरोसा जगाया। अपनी परम्परागत खेती-किसानी का सहारा लिया और बिना किसी सरकारी सहायता, संसाधन के गांव के बच्चे, बुजुर्ग, जवान स्त्री-पुरुष सभी ने गांव के जल देव को जगाया। इन लोगों ने अपने गांव के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सामुदायिक आधार पर फावड़े, कस्सी, डलिया, टोकरा लेकर परम्परागत तरीके से बिना किसी आधुनिक मशीनी-तकनीकी के पानी रोकने का बंदोबस्त किया। सब समझ चुके थे कि पानी बनाया नहीं जा सकता, न ही बादलों को लाकर अपनी इच्छा से बरसाया जा सकता है, लेकिन प्रकृति द्वारा दिए पानी को रोककर पानी की फसल को बोया जा

प्राकृतिक आपदाएं खलनायक कौन?



हिमालय में हुई ग्रासदी के लिए अकेले प्रकृति ही जिम्मेदार नहीं है। इसे प्राकृतिक आपदा कहना सच्चाई से मुंह मोड़ना है। वास्तव में निरंकुश और लापरवाह तरीके से किए गए विकास के चलते हमने हिमालय क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। इससे भी बड़ा खतरा यह उत्पन्न हो गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के चलते यह अधिक खतरे वाला क्षेत्र बन गया है। वैज्ञानिकों ने भी इस तरह की वर्षा की घटनाओं में बढ़ोतरी की आशंका जाहिर की है।

● राजेंद्र आगाल

7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद आई भयावह बाढ़ ने सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में सुला दिया, वहीं अरबों रुपए की परियोजनाओं को पानी में मिला दिया। इसके बाद भारत सहित विश्वभर में एक बार फिर से यह सवाल उठने लगा है कि

आखिरकार प्राकृतिक आपदाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन खलनायक है? हम सभी जानते हैं प्राकृतिक आपदाएं, मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हैं। कई आपदाएं मानव निर्मित गतिविधियों का परिणाम होती हैं लेकिन बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति के रूटीन का हिस्सा होती हैं। विश्वभर में जिस तरह प्रकृति का दोहन किया जा

रहा है, उससे धरती कमजोर पड़ रही है। इस कारण भूकंप और तूफान आ रहे हैं। वहीं ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसके कारण चमोली जैसी घटनाएं हो रही हैं। पिछले कुछ दशक में आई प्राकृतिक आपदाओं का आंकलन करें तो हम यह पाते हैं कि इसके पीछे मनुष्य की विकास लालसा सबसे बड़ी खलनायक है।



उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली में विगत दिनों आई भारी प्राकृतिक आपदा ने 7 साल पहले की केदारनाथ आपदा की भयावह यादें एक बार फिर से हरी कर दीं। नंदादेवी बायोस्फियर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले रैणी गांव के समीप ऋषि गंगा नदी में आए जलप्रलय से आसपास के इलाके में बहुत नुकसान पहुंचा। ऋषि गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण इलाके में हिमनद का एक बड़ा हिस्सा टूट कर नदी में गिर जाने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया था। आगे जाकर इसने बाढ़ का रूप लेकर नदी के आरपार के छोरों में भारी तबाही मचा दी। एकाएक आए इस जलप्रलय ने नदी के किनारे स्थित ऋषि गंगा जलविद्युत परियोजना को पूरी तरह नैस्ताबूद तो कर ही दिया, साथ ही आगे धौलीगंगा नदी पर तकरीबन 80 प्रतिशत बन चुकी तपोवन-विष्णुगाड़ जलविद्युत परियोजना को भी भारी नुकसान पहुंचा दिया। रैणी और तपोवन इलाके के 5 पुल व कुछ मकान भी इस बाढ़ में बह गए।

यह भी स्पष्ट है कि इस अस्थिर क्षेत्र में विकास कार्य बगैर सोचे-समझे और विनाशकारी ढंग से किया गया है। परिणामों की परवाह किए बगैर प्राकृतिक संसाधनों जल, वन और खनिज का जमकर दोहन किया जा रहा है। लिहाजा कई जगहों पर नदियां वास्तव में सूख गई हैं। हिमालय के पर्यावरण से इस तरह की गंभीर छेड़छाड़ कभी किसी के लिए चिंता का मुद्दा नहीं रहा। इसका नतीजा यह रहा कि प्रोजेक्टों का भारी-भरकम कचरा नदियों में डाला जाता रहा। पनबिजली परियोजनाओं और सड़कों के निर्माण ने पहाड़ों को अस्थिर और भूस्खलन को आम बना दिया है। इनके सामूहिक प्रभाव का ही परिणाम है कि पहाड़ ध्वस्त हो रहे हैं। भूस्खलन ने नदियों को अवरुद्ध कर दिया है और प्राकृतिक बांधों का निर्माण किया है। इसलिए जब पानी का दबाव इन प्राकृतिक शक्तियों के विरुद्ध बनता है तो विनाशकारी हो जाता है। इसका यह मतलब भी नहीं है कि इस क्षेत्र में विकास की जरूरत नहीं है

सदी के आखिर तक पिघल जाएंगे हिमालय के एक-तिहाई ग्लेशियर

ग्लोबल वार्मिंग कम करने से जुड़े पेरिस समझौते के अनुसार, वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक रोकने में सफलता मिलने के बावजूद हिमालय के हिंदू कुश क्षेत्र के तापमान में 2.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके चलते इस क्षेत्र में स्थित एक-तिहाई ग्लेशियर पिघल सकते हैं। जलवायु परिवर्तन रोकने के प्रयास विफल होते हैं तो स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है। ऐसे में तापमान 5 डिग्री तक बढ़ सकता है और हिंदू कुश क्षेत्र के दो-तिहाई ग्लेशियर पिघल सकते हैं। ये निष्कर्ष इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटन डेवलपमेंट (आईसीआईएमओडी) द्वारा किए गए अध्ययन में उभरकर आए हैं। भारत समेत 22 देशों के 350 से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया यह अध्ययन काठमांडू में जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 25 करोड़ लोगों के साथ-साथ निचले भागों में स्थित (भारत और इसके आसपास के देशों) की नदी घाटियों की करीब 1.65 अरब आबादी के लिए ये ग्लेशियर महत्वपूर्ण जल स्रोत माने जाते हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से इस क्षेत्र में जल संकट गंभीर हो सकता है। आईसीआईएमओडी से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता फिलिप वेस्टर के मुताबिक, यह क्षेत्र पहले ही दुनिया के सबसे कमजोर और आपदाओं के प्रति संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहां ग्लेशियरों के पिघलने से वायु प्रदूषण से लेकर चरम मौसमी की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। मानसून पूर्व नदियों के प्रवाह में कमी और मानसून में बदलाव के कारण शहरी जल प्रणाली, खाद्य एवं ऊर्जा उत्पादन भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकता है।

लेकिन अनगिनत जिंदगियों की कीमत पर किए गए विकास का कोई मतलब नहीं है। इस लिहाज से हमको ऐसे हिमालयी तरीके के आर्थिक वृद्धि की जरूरत है जो टिकाऊ हो। इसके बगैर क्षेत्र या यहां के लोगों का कोई भविष्य नहीं है।

विकास के रास्ते विनाश

निश्चित तौर पर इस तरह की आपदाएं जहां बार-बार हिमालय के अति संवेदनशील मिजाज के प्रति हमें सजग रहने की चेतावनी देती आ रही हैं, वहीं इन आपदाओं से जब-तब यहां के नाजुक पारिस्थितिकीय क्षेत्र में बनाई जा रही भारी-भरकम जलविद्युत परियोजनाओं व अन्य बड़ी विकास परियोजनाओं के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान उठ खड़े होते हैं। यह विडंबना ही है कि प्रकृति के बचाव से जुड़े इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझे-बुझे बगैर अक्सर विकास विरोधी मानसिकता से देखा जाता है। समाज में कुछ दिनों तक चर्चा में बने रहने के बाद अंततः ऐसे मुद्दे नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में देहरादून के पर्यावरणविद् डॉ. रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में बनी एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में उच्च हिमालयी इलाकों में बनाई जा रही इस तरह की कई बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को स्थानीय पर्यावरण के प्रतिकूल करार देने के बाद भी इन सिफारिशों को भुला दिया गया।

अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो यहां की कुछ बड़ी विकासपरक परियोजनाओं खासतौर पर भारी-भरकम जलविद्युत परियोजनाओं व गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ व बदरीनाथ को जोड़ने वाली चौड़ी ऑलवेदर रोड जैसी तमाम महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण में हिमालय की स्थानीय भौगोलिक संरचना और पर्यावरण से जुड़ी अनेक स्थानीय समस्याओं की पूरी तरह अनदेखी की गई है। देखा जाए तो इन परियोजनाओं के मूल में विकास की वह अवधारणा व्याप्त है जो त्वरित लाभ प्रदान करने वाली तो है, पर सतत अथवा दीर्घकाल तक नहीं। विशुद्ध लाभ की आकांक्षा वाली इस तरह की विकास परियोजना अक्सर पर्यावरण के प्रतिकूल रहती हैं और देर-सवेर प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा देने का काम करती हैं। आपदाएं चाहे प्राकृतिक हों अथवा मानवजनित, इनका दुखद परिणाम अंततः जन-धन व संपदा के नुकसान के रूप में सामने आता है।

अनियोजित विकास

उत्तराखंड हिमालय की उत्तरी पर्वत श्रृंखलाएं जहां तीव्र ढाल व बर्फ से ढकी हैं, वहीं इसका मध्य भाग अपेक्षाकृत सामान्य ढाल वाला है। इसके दक्षिण में विस्तृत मैदानी भू-भाग स्थित है जो पर्वतीय नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है। अपनी विशिष्ट भू-गर्भिक संरचनाओं, पर्यावरणीय

भारत की बड़ी आपदाएं

प्राकृतिक आपदाएं दुनियाभर में सार्वभौमिक घटनाएं हैं। भारत में अभी तक 7 ऐसी आपदाएं आ चुकी हैं, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। इनमें से 2014 में आई कश्मीर की बाढ़ भी एक है। इस बाढ़ में करीब 550 लोगों ने अपनी जान गंवाई और लगभग 5000 करोड़ से 6000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था। वहीं 2013 में उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स भारत के इतिहास में सबसे विनाशकारी बाढ़ में से एक है। जून 2013 में उत्तराखंड में भारी वर्षा, बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ था। इसमें 14 से 17 जून तक बाढ़ और भूस्खलन जारी रहा और इसमें लगभग 1 लाख तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर में फंस गए थे। जब 5700 लोगों की मौत हो गई। 2007 में बिहार की बाढ़ को सबसे खराब बाढ़ के रूप में वर्णित किया गया था। इसका असर बिहार के 19 जिलों पर पड़ा था। बिहार बाढ़ ने पूरे राज्य में अनुमानित 10 मिलियन लोगों को प्रभावित किया था। लगभग 29,000 घर नष्ट हो गए और 44,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए, लगभग 4822 गांव और 1 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि इस बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई थी। जबकि 1,287 लोगों की मौत हुई थी। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी ने दक्षिणी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदि को प्रभावित किया था। इस सुनामी में करीब 2.30 लाख लोग मरे थे। वहीं 2001 में गुजरात में आया भूकंप 20 हजार लोगों को मौत की नींद सुला गया। इसमें 1,67,000 लोग घायल और लगभग 4 लाख लोग बेघर हो गए। 1999 में ओडिशा में आया सुपर साइक्लोन लगभग 15,000 लोगों की जान ले गया। सन् 1999 का सुपर साइक्लोन, उत्तर हिंद महासागर में सबसे खतरनाक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। इसकी गति 260 किमी प्रतिघंटा थी। इसने न केवल भारत बल्कि बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड को भी प्रभावित किया था। अनुमान के अनुसार, लगभग 15 हजार लोग मारे गए, लगभग 1.67 मिलियन लोग बेघर हो गए और 2.75 लाख से अधिक घर नष्ट हो गए थे। 1770 में महान बंगाल अकाल अभी तक की सबसे बड़ी आपदा माना जाता है। इसमें करीब 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन इस अकाल को मानव निर्मित आपदा बताते हैं। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों और सूखा पड़ने के कारण हुआ था। यह अकाल 1769 में एक असफल मानसून से शुरू हुआ था जो 1773 तक लगातार दो सीजन तक जारी रहा था। इस अकाल की पूर्ण अवधि के दौरान लगभग 10 मिलियन लोग भूख के कारण मर गए थे।



हिमाचल में कभी भी कहर ता सकती हैं झीलों

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुसंधान के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण राज्य परिषद और जलवायु परिवर्तन केंद्र की ओर से पिछले साल तीन रिवर बेसिन सतलुज, चिनाब और व्यास को लेकर की गई स्टडी में चौंकाने और चेताने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। जलवायु परिवर्तन केंद्र के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के तीन रिवर बेसिन में 897 झीलें पाए गई हैं। इनके दायरे में वर्ष 2018 के मुकाबले में वृद्धि दर्ज की गई है। शोधकर्ताओं ने चिंता जाहिर की है कि यदि ग्लेशियरों के पिघलने का क्रम ऐसा ही जारी रहा तो इन झीलों के आकार में और वृद्धि होना तय है, जिससे भविष्य में भयानक बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जलवायु परिवर्तन राज्य केंद्र द्वारा 2019 में किए गए शोध के आधार पर वर्ष 2019 में सतलुज बेसिन में 562 झीलों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जिनमें से लगभग 81 प्रतिशत (458) झीलें 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की हैं, 9 प्रतिशत (53) झीलें 5 से 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल और 9 प्रतिशत (51) झीलें 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की हैं।

व जलवायुगत विविधताओं से युक्त इस क्षेत्र में अक्सर भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं होती हैं। भू-गर्भिक संरचना की दृष्टि से इस संवेदनशील इलाके में छोटे-बड़े भूकंपों की आशंका बराबर बनी रहती है। पिछले कई दशकों में यहां के अनियोजित विकास, प्राकृतिक संसाधनों के निर्मम दोहन, बढ़ते शहरीकरण और उच्च हिमालयी भू-भाग में बांधों व सुरंगों के निर्माण कार्यों ने स्थानीय पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ दिया है। इसके चलते प्राकृतिक आपदाओं में इजाफा हो रहा है।

नदी-घाटियों से सटी भूमि के साथ ही संवेदनशील जगहों पर आबादी के बसाव होने से प्राकृतिक आपदा आने पर जन-धन की हानि व्यापक स्तर पर हो जाती है। उत्तराखंड में वर्ष 1998 के मालपा भूस्खलन में 250 से अधिक तीर्थयात्रियों की अकाल मौत और जून 2013 में आई केदारनाथ आपदा में हजारों लोगों की मौत के पीछे भी यही कारण मुख्य रहे। पिछले कुछ सालों में आई प्राकृतिक आपदाओं के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि प्राकृतिक आपदाओं से उत्तराखंड के जन-जीवन पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ा है।

इंसानी महत्वाकांक्षा

हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट से पता चला है कि 1951 से 2014 के बीच हिंदू कुश हिमालय के तापमान में करीब

1.3 डिग्री की वृद्धि हुई है। इसके कारण उत्तराखंड में जलवायु और ग्लेशियल बदलाव आए हैं। जिसकी वजह से बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसका असर न केवल वहां रहने वाले लोगों बल्कि वहां चल रही 32 बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर भी पड़ सकता है। गौरतलब है कि ऐसी हर परियोजना की लागत 150 करोड़ से ज्यादा है। जलवायु परिवर्तन का यह असर केवल बाढ़ को ही नहीं बढ़ा रहा है इसके साथ-साथ सूखे की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। सीईईडब्ल्यू के अनुसार 1970 के बाद से वहां सूखे की घटनाओं में भी दोगुनी वृद्धि हुई है। यहां के 69 फीसदी जिले सूखे की मार झेल रहे हैं। पिछले एक दशक में अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में बाढ़ और सूखे की घटनाएं एक साथ बढ़ी हैं। इन आपदाओं की दोहरी मार इनसे निपटने की क्षमता और प्रयासों को और मुश्किल बना रही है। 2015 में सीईईडब्ल्यू द्वारा जलवायु जोखिम मूल्यांकन पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछली सदी के दौरान गंगा बेसिन में बाढ़ की आवृत्ति 6 गुना बढ़ गई है।

जलवायु परिवर्तन का खतरा

2020 में जारी एक अध्ययन से पता चला है कि देश के 75 फीसदी जिलों पर जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है। इन जिलों में देश के करीब 63.8 करोड़ लोग बसते हैं। वहीं देश का करीब 12 फीसदी हिस्सा बाढ़ और 68 फीसदी



हिस्सा सूखे की जद में है। इसी तरह देश की करीब 80 फीसदी तटरेखा पर चक्रवात और सुनामी का खतरा लगातार बना हुआ है। हाल ही में जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ने भी भारत को दुनिया का 7वां सबसे जलवायु प्रभावित देश माना था। देश के तापमान में हो रही वृद्धि लगातार जारी है जो एक बड़ा खतरा है। यदि देश में तापमान के बढ़ने को देखें तो अब तक के 12 सबसे गर्म वर्ष हाल के पंद्रह वर्षों (2006 से 2020) के दौरान रिकॉर्ड किए गए थे। वहीं आंकड़ों के अनुसार 2020 भारतीय इतिहास का 8वां सबसे गर्म वर्ष था। तापमान में हो रही यह बढ़ोतरी हालांकि अब आम बात बनती जा रही है। और शायद आम लोगों को इसका असर पता नहीं चल रहा या फिर वो उसे अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से और जिस रफ्तार से तापमान में यह बढ़ोतरी हो रही है, उसके चलते बाढ़, सूखा, तूफान, हीट वेव, शीत लहर जैसी घटनाएँ बहुत आम बात हो जाएंगी।

70 फीसदी नदियां प्रदूषित

कहने को तो भारत नदियों का देश है, लेकिन विडंबना यह है कि 70 प्रतिशत नदियां जानलेवा स्तर तक प्रदूषित हैं। भारत की कई नदियां जैविक लिहाज से मर चुकी हैं। इसका असर पर्यावरण के साथ लोगों पर भी पड़ रहा है। कई नदियों का अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। देशभर में प्रदूषण की चपेट में करीब 150 नदियों में गंगा और यमुना नदी दुनिया की 10 गंदी नदियों में भी शुमार हैं। देश के 27 राज्यों में 150 नदियां ऐसी हैं जो प्रदूषण की चपेट में हैं, इनमें सबसे ज्यादा 28 नदियां महाराष्ट्र राज्य में हैं, तो विकास की मिसाल कायम कर रहे गुजरात की

मानव ही प्रलय का सृजनकार

मानव ही है प्रलय का सृजनकार, क्योंकि उसने धरती पर जो जुलूम किया है, धरती उसका बदला लेने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। धरती के 75 प्रतिशत हिस्से पर जल है और सिर्फ 25 प्रतिशत हिस्से पर ही मानव की गतिविधियां जारी थी। आज से 200-300 साल पहले मानव की आकाश और समुद्र में पकड़ नहीं थी, लेकिन जबसे मानव ने आकाश और समुद्र में दखलअंदाजी की है, धरती को पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तेल के खेल और खनन ने धरती का तेल निकाल दिया है। वक्त के पहले धरती को मार दिए जाने की हरकतें धरती कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इससे पहले कि मानव अपनी हदें पार करे धरती उसके अस्तित्व को मिटाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। धरती का अपना एक परिस्थितिकी तंत्र होता था। उस तंत्र के गड़बड़ाने से जीवन और जलवायु असंतुलित हो गया है। मानव की प्रकृति में बढ़ती दखलअंदाजी के चलते वह तंत्र गड़बड़ा गया है। मानव ने अपनी सुख, सुविधा और अर्थ के विकास के लिए धरती का हृदय से ज्यादा दोहन कर दिया है। मांसाहार के अति प्रचलन के चलते मूक प्राणियों के मारे जाने की संख्या लाखों से करोड़ों में पहुंच गई। जो नहीं खाना चाहिए मानव वह भी खाने लगा है। शेर को बकरी नहीं मिलती, बकरी को चारा नहीं मिलता। कुत्ते को बिल्ली नहीं मिलती और बिल्ली को चूहा। बाज को सांप नहीं मिलता और सांप को इल्ली। सभी के हिस्से का भोजन मानव खाने लगा है। जो पशु जीभ से पानी पीता है वह मांसाहारी और जो होट लगाकर पानी पीता है वह शाकाहारी है।

19 नदियों का भी प्रदूषण के कारण हाल बुरा है। राज्यवार प्रदूषित नदियों की बात की जाए तो उग्र तीसरे पायदान पर है जहां 12 प्रदूषित नदियां समस्या बनी हुई हैं। इसी प्रकार कर्नाटक में 11 के अलावा मप्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 9-9 नदियां ऐसी हैं, जो प्रदूषण की चपेट में हैं। वहीं राजस्थान की पांच और झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भी तीन-तीन नदियां प्रदूषित नदियों की सूची में शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से गुजरने वाली एकमात्र यमुना नदी का प्रदूषण तो अरसे से सुर्खियों में बना हुआ है।

लगातार घट रहे वनक्षेत्र

भारत के वनक्षेत्र पर स्थिति रिपोर्ट 2015 के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना में जंगल तेजी से घटे हैं। पूरे भारत की बात करें तो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में देश में केवल 12 बार सूखा पड़ा, यानी 16 वर्ष में एक बार सूखा पड़ा। लेकिन 1968 के बाद से सूखे की तादाद में वृद्धि आई। जंगलों की अंधाधुंध कटाई जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। मानवीय लालच ने वनों की विनाश लीला का काला अध्याय लिखा है। एक रिपोर्ट के अनुसार विगत 3 वर्षों (2009-2011) में ही भारत में 5339 स्क्वायर किमी वन क्षेत्र विकास के नाम पर बलि चढ़ गए तथा राष्ट्र को 2000 करोड़ रुपए की आर्थिक हानि हुई। वनों के घटने के कारण हर वर्ष, वर्षा के दिनों में, भूस्खलन, बाढ़ आदि से करोड़ों रुपए का राष्ट्र को नुकसान उठाना पड़ता है। उदाहरण के लिए जून 2013 को उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा ने 5700 यात्रियों व पर्यटकों के जीवन को समाप्त कर दिया तथा बड़ी कठिनाई से सरकारी प्रयासों से 1,17,000 लोगों के जीवन को बचाया जा सका।

लगातार बढ़ रहा तापमान

धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है जिसके चलते प्रकृति में अनेक नुकसानदेह परिवर्तन हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो बढ़ती गर्मी के लिए कहीं न कहीं मानव जाति ही कसूरवार है। विकास की दौड़ में सरपट भागते इंसानों ने कार्बन उत्सर्जन, पेड़ों की कटाई, प्रकृति से खिलवाड़ करते वैश्विक तापमान में जो बढ़ोतरी की है उसका ही दुष्परिणाम अब प्रतिवर्ष बढ़ती हुई गर्मी एवं तापमान के रूप में सामने आ रहा है। आंकड़ों के आलोक में बात की जाए तो पिछले डेढ़ दशक में देश में हर वर्ष औसतन तापमान में बढ़ोतरी रिकार्ड की जा रही है। गौरतलब है कि पिछली एक शताब्दी के दौरान देश के अन्य 9 सबसे गर्म वर्षों में 1998, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009, 2010 और 2014, है। खास बात यह है कि पिछले 15 वर्षों 2000-

2015 के दौरान ही रहे। इससे आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिवर्ष तापमान बढ़ने की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पिछले वर्ष जानलेवा गर्मी ने 2500 लोगों को मौत की नौद सुला दिया था।

ऐसे हालात में यह जरूरी हो गया है कि विकास को इस प्रकार सीमित व व्यवस्थित बनाया जाए कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम रह सके। विकास की प्रक्रिया को इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि उससे प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव न हो। यदि विकास के साथ-साथ पर्यावरण की भी गंभीरता से चिंता की जाए तो बिगड़ती प्राकृतिक स्थिति पर कुछ रोक लगाना संभव है। मत भूलिए की प्राकृतिक संसाधन इंसान की जरूरतों की पूर्ति तो कर सकता है किंतु उसकी लालच की पूर्ति नहीं कर सकता।

ग्लोबल वॉर्मिंग चिंतनीय

ग्लोबल वॉर्मिंग के चलते लगातार दुनिया के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कहीं सुनामी तो कहीं भूकंप और कहीं तूफान का कहर जारी है। दूसरी और धरती के ऊपर ओजन पर्त का जो जाल बिछा हुआ है उसमें लगभग ऑस्ट्रेलिया बराबर का एक छेद हो चुका है। जिसके कारण धरती का तापमान 1 डिग्री बढ़ गया है। एक अन्य शोध के चलते वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप आदि आपदाओं के कारण धरती अपनी धुरी से 2.50 से 3 डिग्री घिसक गई है जिसके कारण भी जलवायु परिवर्तित हो गया है। धरती पर से प्राकृतिक आपदा के कारण कई बार कई जाति और प्रजातियों का विनाश हो चुका है। वैसे मानव को अस्तित्व में आए वैज्ञानिकों के अनुसार तो लगभग 2 करोड़ साल ही हुए हैं और एक दूसरी मान्यता के अनुसार 80 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव अस्तित्व में आया। धरती की अब तक की आयु का आंकलन 4.5 अरब वर्ष किया गया है। हालांकि वैज्ञानिकों में इस बारे में मतभेद हैं।

वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती के सारे द्वीप (अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि) एक-दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन धरती की घूर्णन गति (अपनी धुरी पर घूमना) के कारण ये सभी एक दूसरे से धीरे-धीरे अलग होते गए और इस प्रक्रिया में हजारों, लाखों साल लगे। इस घूर्णन गति के कारण ही समुद्र और धरती के अंदर स्थित बड़ी-बड़ी चट्टानें घिसकर एक-दूसरे से दूर होती रहती हैं जिसके कारण भूकंप और ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आज भी जारी है और आगे भी निरंतर जारी रहेगी। लेकिन जब मानव इस स्वाभाविक प्रक्रिया में दखल देता है तो स्थिति और भयानक बन जाती है।



बाढ़ के लिए हॉटस्पॉट बन चुके हैं उत्तराखंड के 85 फीसदी जिले

उत्तराखंड के 85 फीसदी जिले बाढ़ की गंभीर घटनाओं के लिए हॉटस्पॉट बन चुके हैं। यह जानकारी काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) द्वारा जारी विश्लेषण में सामने आई है। इन जिलों में 90 लाख लोग रहते हैं। विश्लेषण के अनुसार 1970 के बाद से उत्तराखंड में बाढ़ की चरम घटनाओं की संख्या और तीव्रता में चार गुना वृद्धि हुई है जिसके कारण बाढ़ से जुड़ी अन्य घटनाओं जैसे भूस्खलन, बादल फटना आदि में भी इतनी ही वृद्धि हुई है। जिसके कारण बड़ी मात्रा में जान-माल की हानि हुई है। इसमें राज्य के चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा असर पड़ा है। सीईईडब्ल्यू में प्रोग्राम लीड अविनाश मोहंती के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड में आई बाढ़ इस बात का प्रमाण है कि जलवायु परिवर्तन के खतरे को अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता। पिछले 20 वर्षों में उत्तराखंड के करीब 50,000 हेक्टेयर वन खत्म हो चुके हैं, जिसके कारण वहां की जलवायु में बदलाव आ रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप मौसम की चरम घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में इन जंगलों को फिर से तैयार करना जरूरी है। इसकी मदद से जलवायु में आ रहे असंतुलन में सुधार लाया जा सकता है।

प्रकृति की सत्ता सर्वोपरि

कुदरत की लाठी में बड़ी जान है। जब मारती है तो बचने की जरा भी गुंजाइश नहीं रहती। करें तो क्या? सोचने की बात यह है कि प्रकृति इतनी बेरहमी से लाठी भांजने को मजबूर क्यों होती है? पहले उसे गुस्सा कभी-कभार आता था अब लगता है उसकी भौंहें बारहों मास-आठों पहर तनी रहती हैं। हमारी समझ में खुद मनुष्य की मुद्रा 'आ बैल मुझे मार' वाली रही है। जो लाठी बचपन में नौनिहाल को चलने में मददगार, बुढ़ापे का सहारा, जवानी में सांप-कुत्ते जैसे जोखिमों को दूर करती है वह बेचारों का सिर फोड़ने वाला हथियार अगर बन रही है तो अकारण नहीं। एक और मुहावरा याद आता है जो लाठी के रूपक के साथ जुड़ी विडंबना को उजागर करता है- 'मारें घुन्ना, फूटे आंख!' अनाड़ी लठैत की तरह प्रकृति का लठ भी अंधाधुंध घूमता है। जो मुनाफाखोर खुदगर्ज हिमालय के बेहद नाजुक पारिस्थितिकी को संकटग्रस्त बनाने के लिए जिम्मेदार हैं वे निरापद जगहों में बचे हुए हैं। और जो निरपराध-वंचित पेट पालने की मजबूरी में

सड़क किनारे काम करते थे वही अपने मेहमानों के साथ 'शिकार' बने हैं। छोटे से पहाड़ी राज्य की कुल आबादी का करीबन 8-9 प्रतिशत हिस्सा दो-तीन दुर्गम जिलों में 'अतिरिक्त भार' के रूप में जिस तरह से अनिर्यात्रित पहुंचा है उस स्थिति में धरती कैसे और कितनी देर तक अपना नाम सार्थक करती इन्हें धारण कर सकती है? तीर्थयात्रा पर्यटन के नाम पर जो व्यवसाय प्रायोजित ढंग से पनपाया जाता रहा है या विकास के नाम पर भवन, पुल, सड़क निर्माण हर सरकार ने प्रोत्साहित किया है, उसी का नतीजा है कि बहुमंजिला सीमेंट कांक्रीट के मकान ताश के महलों की तरह भरभराकर ढह रहे हैं। यह बात कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा कि पर्यावरण के संरक्षण तथा जनहितकारी विकास में संतुलन की जरूरत है। दुर्भाग्य यह है कि इस घड़ी भी उत्तराखंड की नाकाम मौजूदा सरकार 'आपदा प्रबंधन की अर्थव्यवस्था' के सहारे अपना अस्तित्व बचाने एवं भविष्य संवारने में व्यस्त नजर आ रही है। जब तक आलाकमान की बैसाखी का सहारा है कुदरत की लाठी की किसे परवाह है?

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उप्र के कुछ किसानों द्वारा दिल्ली को घेरकर कृषि कानूनों को हटाने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है, वह अब एक जिद में तब्दील हो गया दिखता है। किसान नेताओं ने सरकार के उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया, जिसमें इन कानूनों को डेढ़ साल तक रोकने को कहा गया था। इससे यही लगता है कि किसान नेताओं

का मकसद सरकार को नीचा दिखाना है। किसान नेता उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने भी अपनी बात कहने

को तैयार नहीं। वे कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी को कानूनी रूप देने पर अड़े हैं। किसान नेताओं के इसी रवैए को देखते हुए सरकार को यह कहना पड़ा कि अब उसके पास उनके लिए कोई प्रस्ताव नहीं। वास्तव में इसका कोई औचित्य नहीं कि सरकार तो लगातार नरमी दिखाए, लेकिन किसान नेता उस से मस न हों।

निसंदेह भारत का किसान गरीब है, लेकिन सारे किसान गरीब नहीं हैं और जो किसान करीब दो महीने से दिल्ली में डेरा डाले हैं, वे तो खास तौर पर अपनी समृद्धि के लिए जाने जाते हैं। इसकी पुष्टि पंजाब, हरियाणा से लाखों ट्रैक्टर दिल्ली लाने की तैयारी से भी होती है। किसान ये ट्रैक्टर अपने खर्च से लाएंगे और ले जाएंगे। संपन्नता के चलते ही यहां के किसान आमतौर पर दिहाड़ी मजदूरों से खेती कराते हैं। इसी कारण वे अपना काम-धाम छोड़कर इतने दिन से दिल्ली में डटे हैं। चूंकि किसान संगठनों को समर्थन दे रहे कांग्रेस एवं वाम दलों की दिलचस्पी किसानों को उकसाने में अधिक है इसलिए शायद वह यह कहना भूल गए थे कि किसान गणतंत्र दिवस की गरिमा का ध्यान रखें। अपेक्षाकृत समृद्ध किसान तो दिल्ली में डेरा डाले हैं, लेकिन आम किसान उनके आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं। वे इस आंदोलन में अपना हित नहीं देख रहे हैं।

कई किसान संगठन तो कृषि कानूनों को अपने लिए जरूरी मान रहे हैं। इसका कारण यह भी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का अधिकतर लाभ पंजाब और हरियाणा के किसान उठाते हैं। एक तरह से एमएसपी पर उनका एकाधिकार है। एमएसपी का लाभ उठाने वाले किसान उसे कानूनी रूप देने की मांग करने के साथ यह भी चाह रहे हैं कि उन्हें पराली जलाने से रोका न जाए और न ही बिजली की सब्सिडी में कटौती की जाए। पंजाब और हरियाणा के किसान यह समझने को तैयार नहीं कि धान की जरूरत से ज्यादा खेती के चलते भूजल का स्तर नीचे जा रहा है। इसके कारण उपजी समस्याएं गंभीर रूप लेती जा रही हैं। एक आंकलन के

देश की राजनीति का मोहरा बने किसान



मोदी सरकार को नीचा दिखाने की रणनीति

किसान नेताओं की तरह कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल भी किसान आंदोलन की आड़ में मोदी सरकार को नीचा दिखाने की रणनीति पर चल रहे हैं। विपक्षी दल यह जानते हैं कि किसानों की हालत में सुधार लाने की जरूरत है और यह सुधार खेती को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ने से होगा। इसी कारण कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में वैसे कानूनों की वकालत की थी, जैसे कानून मोदी सरकार ने बनाए हैं, लेकिन आज राहुल गांधी किसानों को बरगलाने के साथ मोदी को किसानों का दुश्मन बता रहे हैं। कांग्रेस सरीखे दलों को तो किसानों की परवाह नहीं, लेकिन किसान नेताओं को यह समझना चाहिए कि पुरानी व्यवस्था और खेती के तौर-तरीकों से चिपकें रहने से किसानों को कुछ हासिल नहीं होने वाला। किसान नेताओं के कहने पर दिल्ली आए किसानों को भी यह समझना चाहिए कि वे संकीर्ण राजनीति का मोहरा बनाए जा रहे हैं। अभी भी समय है, किसान हित की वास्तव में चिंता कर रहे किसान नेताओं को कृषि कानूनों को डेढ़ साल तक रोकने के सरकार के प्रस्ताव पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। किसी समस्या का समाधान सकारात्मक रवैये के साथ बातचीत करने से ही निकलेगा। नकारात्मक रवैये से कभी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता।

अनुसार अगर दक्षिणी पंजाब में भूजल दोहन बंद नहीं हुआ तो वह रेगिस्तान में बदल सकता है। इस खतरे से पंजाब सरकार के साथ किसान भी अवगत हैं, लेकिन वे धान की खेती कम करने को तैयार नहीं। दरअसल एमएसपी के लालच में धान की खेती की जा रही है।

देश में सबसे पहले 1966-67 में गेहूँ के लिए एमएसपी की घोषणा की गई थी। तब अनाज की तंगी से जूझ रहे देश में कृषि उत्पादन बढ़ाना और

गरीबों के लिए अन्न का प्रबंध करना प्रमुख लक्ष्य था। एमएसपी जिस मकसद के लिए शुरू की गई थी, वह पूरा हो गया है। अब एमएसपी के दायरे वाली कई फसलों और खासकर गेहूँ और धान का उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो रहा है, लेकिन राजनीतिक कारणों से उनकी भी सरकारी खरीद करनी पड़ती है। एमएसपी अधिक उपज वाली फसलों के लिए नहीं थी और न ही होनी चाहिए। एमएसपी तो उन्हीं फसलों के लिए होनी चाहिए, जिनकी पैदावार कम है और जिनका आयात करना पड़ता है। एमएसपी पर अनाज की खरीद सरकारी मंडियों से होती है और यह एक हकीकत है कि उनमें भ्रष्टाचार पनप गया है। यह भ्रष्टाचार अफसरों और बिचौलियों की मिलीभगत से होता है। हैरानी की बात है कि किसान नेता इस भ्रष्टाचार पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। वे यह देखने को भी नहीं तैयार कि गैर जरूरी फसलें उगाना न तो उनके हित में है और न ही देश के।

भारतीय किसानों के पिछड़ेपन के लिए सरकारी नीतियां भी उत्तरदायी रहीं और परंपरागत खेती का प्रचलन भी। आजादी के बाद भारत में अन्न की कमी थी और उसके चलते उसका आयात करना पड़ता था। अब स्थितियां बदल चुकी हैं। बदली हुई स्थितियों में यह आवश्यक है कि किसान मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाएं यानी बाजार के साथ तालमेल करें। 1990 के दशक में जैसे उद्योग-व्यापार जगत को मुक्त अर्थव्यवस्था के दायरे में लाया गया, वैसे ही कृषि को भी लाने की जरूरत है। किसान नेता इस जरूरत को समझने से इंकार कर रहे हैं। ऐसा करके वे आम किसानों का अहित ही कर रहे हैं। उन्हें यह देखना चाहिए कि आज देश के तमाम किसान अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में आकर ठीक-ठीक कमाई कर रहे हैं। किसानों के लिए यह जरूरी है कि वे परंपरागत फसलें उगाने के बजाय आय के अन्य स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करें।

● राजेश बोरकर

6

नरेंद्र मोदी जबसे प्रधानमंत्री बने हैं, उनका हर एक कदम चर्चा में रहा है। दरअसल, उन्हें जनता पर अगाध भरोसा है। अपने समर्थकों और देश के आमजन की सहज बुद्धि पर शायद ही किसी प्रधानमंत्री को ऐसा भरोसा रहा हो जैसा मोदी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक नए-नए आर्थिक सुधार के ऐसे कदम उठाते जा रहे हैं जो उनके लिए घाटे का सौदा बन सकता है। लेकिन मोदी बिना किसी विंता के क्रांतिकारी कदम उठाने से कतरा नहीं रहे हैं।

जनता के भरोसे जोखिम



कि सी भी नेता की राजनीतिक पूंजी उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। नेता इसका इस्तेमाल बड़ी किफायत से करते हैं और इसके प्रति सजग रहते हैं कि इसमें कमी न होने जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास राजनीतिक पूंजी बहुत ज्यादा है, पर वह इसका इस्तेमाल बड़ी दरियादिली से करते हैं। लगता है उन्हें इसका अक्षय पात्र मिल गया हो। किसान आंदोलन

के नाम पर चल रहा आंदोलन पहले अहिंसक से हिंसक हुआ और फिर गैर-राजनीतिक से राजनीतिक। विरोध के इस वातावरण में किसी भी सरकार के हाथ-पांव फूल सकते हैं। विरोध का आलम यह है कि तिरंगे के अपमान के साथ गणतंत्र दिवस एवं लाल किले की मर्यादा तार-तार करने और पुलिस वालों पर जानलेवा हमला करने वालों का भी समर्थन किया जा रहा है।

के माहौल में कोई भी प्रधानमंत्री लोकलुभावन घोषणाओं का सहारा लेता, इसके विपरीत मोदी सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की। बजट के जरिए मोदी विकास की राजनीति की एक नई इबारत लिख रहे हैं। मोदी बड़ा राजनीतिक जोखिम मोल ले रहे हैं। वह एक के बाद एक नए-नए आर्थिक सुधार के ऐसे कदम उठा रहे हैं, जो राजनीतिक घाटे का सौदा बन सकते हैं। इन कदमों का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि ये विपरीत परिस्थितियों में उठाए जा रहे हैं। खराब परिस्थितियां केवल राजनीतिक नहीं हैं, बल्कि कोरोना के कारण भी हैं।

मोदी के राजनीतिक विरोधियों के दो वर्ग हैं। एक दाएं-बाएं देखकर विरोध करता है। दूसरा, लगातार विरोध में लगा रहता है। मोदी का विरोध बाहर ही नहीं घर में भी है। संघ परिवार के विभिन्न अनुष्ठांगिक संगठनों में से कोई एक समय-समय पर विरोध की आवाज बुलंद करता ही रहता है।

मैदान से गायब

सब इस बात पर सहमत हैं कि भाजपा एक जोरदार चुनावी मशीन और सामने आए प्रतिस्पर्धी को कुचल कर रख देना वाला प्रभावशाली बल है। विपक्षी दल भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं, पन्ना प्रमुखों और मंडल प्रमुखों के बारे में पढ़कर भौचक रह जाते हैं। लेकिन ये कार्यकर्ता पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उप्र से अचानक कहां गायब हो गए हैं? भाजपा ने इन राज्यों में अपने सदस्यता अभियान के विस्तृत परिणामों की घोषणा कभी भी नहीं की है। इसलिए केवल भाजपा नेताओं को पता होगा कि पार्टी के अंबाला, जींद, मुजफ्फरनगर, शामली या गाजियाबाद में कितने सदस्य हैं। बाकियों को इस बात की जानकारी नहीं है कि हरियाणा में कितने लोग भाजपा के सदस्य हैं। लेकिन मोदी, शाह और नड्डा को जरूर ये जानकारी होगी, और वे उन पार्टी सदस्यों को ढूँढ रहे होंगे। मोदी के कागजी शेर टीवी और टिवटर पर विपक्ष के खिलाफ खूब दहाड़ते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी लुटियंस की दिल्ली से निकलकर सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर तक नहीं जाता।

आपने इससे पहले देश में कोई ऐसा आंदोलन देखा है, जिसमें चार सौ पुलिस वाले घायल हो जाएं, उन पर लाठी, डंडे, लोहे के रॉड से ही नहीं तलवार से भी हमला हो और ऐसा करने वाले सीना तानकर घूम रहे हों। जैसे पीड़ित ही दोषी हों। ट्रैक्टरों को अभी तक हमने खेतों में चलते देखा था। 26 जनवरी को उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल होते हुए भी देखा। विरोधियों के हिसाब से यह सब जायज है, क्योंकि वह मोदी के विरोध में है। मोदी इन सबसे कतई विचलित नहीं लगते। अपने समर्थकों और देश के आमजन की सहज बुद्धि पर शायद ही किसी प्रधानमंत्री को ऐसा भरोसा रहा हो। उनके मन में यह बात बहुत गहरे बैठी हुई है कि लोग ईमानदार आदमी का साथ देते हैं।

भारतीय समाज के मानस में एक बात गहरे पैठी हुई है कि ईमानदार आदमी अच्छा होता है और वह व्यक्तिगत स्वार्थ पर समाज के हित को वरीयता देता है। इसीलिए विपक्ष

के इतने बड़े नेताओं के होते हुए भी उन्हें 1975 में एक जयप्रकाश नारायण, 1986-87 में एक वीपी सिंह और 2011 में एक अन्ना हजारे की जरूरत पड़ी। इन तीनों अवसरों पर सत्तारूढ़ दल और उसके नेतृत्व पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। जनमानस में उनकी विश्वसनीयता नहीं रह गई थी और लोकप्रियता निचले पायदान पर थी। जेपी, वीपी और अन्ना के सफल होने का यह एक बहुत बड़ा कारण था। विपक्ष के दुर्भाग्य से उसके सामने ऐसा कोई नेता नहीं है। देश के सौभाग्य से वर्तमान सरकार का नेतृत्व ईमानदारी की मिसाल है। उसकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता कम होने के बजाय बढ़ी ही है। मोदी से पहले केवल नेहरू ही ऐसे प्रधानमंत्री थे, जो सत्ता में आने के बाद भी विश्वसनीय और लोकप्रिय बने रहे।

कहावत है कि अच्छी अर्थनीति खराब राजनीति होती है और अच्छी राजनीति खराब अर्थनीति। मतलब यह कि दोनों को एक साथ नहीं साध सकते, पर ऐसा लगता है कि मोदी 'एकै साधे सब सधें, सब साधे सब जाए' की नीति में विश्वास करते हैं। पिछले करीब पौने सात सालों ने यह दिखाया है कि अर्थनीति हो या राजनीति, फैसले अच्छी नीयत से किए जाएं तो नतीजा अच्छा ही निकलता है। जब-जब संकट की घड़ी आई, मोदी ने देश के लोगों पर भरोसा किया और देशवासियों ने मोदी पर। नेता और जनता के इस परस्पर भरोसे की तुलना कुछ हद तक जवाहरलाल नेहरू के समय से की जा सकती है। तब कांग्रेस के लोग मानकर चलते थे कि नेहरू जो कहेंगे, देश उसी को सच मानेगा। लोग मानकर बैठे हैं कि दर्द कितना भी बड़ा हो, उसकी दवा मोदी के पास है।

कई दशकों से जनता भारतीय राजनीति को करीब से देख रही हैं। याद नहीं कि विपक्ष कभी इतना निस्तेज और साख विहीन रहा हो। यह स्थिति जनतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वास्तविकता को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। किसी भी सरकार के खिलाफ मुद्दा हो तो विपक्ष की ताकत बढ़ती है, पर यह भी सही है कि मुद्दे केवल अवसर देते हैं। अवसर का लाभ उठाने के लिए विश्वसनीयता जरूरी होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कविता का उद्धरण दिया। इस कविता का अर्थ था कि चिड़ियों को पौ फटने से पहले ही रोशनी का आभास हो जाता है और वे चहचहाने लगती हैं। कोरोना महामारी से देश जिस तरह निपटा, चीन को सीमा पर जिस तरह का जवाब दिया गया, वैक्सिन के विकास और टीकाकरण में जिस तरह की शुरुआत हुई और अब बजट के जरिए आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह की पहल हुई, वह नए भारत के अभ्युदय का संकेत है। मोदी ने न केवल इस संकेत को पहचान लिया है, बल्कि इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। आने वाला



क्या हैं भाजपा की प्राथमिकताएं

ऐसा नहीं है कि केवल मंत्री और सांसद ही सतर्कता बरतते हुए इस राजनीतिक संकट से निपटने का जिम्मा मोदी सरकार के शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस संकट से खुद को लगभग पूरी तरह अलग-थलग किए दिखती है, और ये प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर छोड़ दिया गया है कि वे अपने मामले खुद ही संभालें। पिछले महीने, पार्टी ने कृषि कानूनों के खिलाफ कथित 'दुष्प्रचार' अभियान के खिलाफ एक जनसंवाद कार्यक्रम की योजना बनाई थी। इसके तहत देश के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनसंपर्क कार्यक्रम और 'चौपाल' आयोजित किए जाने थे। स्पष्ट है कि इसका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उग्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पार्टी की हरियाणा इकाई अब खाप पंचायतों और जाट नेताओं तक पहुंचने का कार्यक्रम बना रही है, लेकिन अभी ये योजना निर्माण के चरण में ही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के टिवटर हैंडल को देखकर आप प्राथमिकताओं को समझ सकते हैं। वह पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल और केरल में पार्टी के प्रचार में लगे रहे। और किस गर्मजोशी से उनका स्वागत हो रहा है! दमकता चेहरा, मालाएं और हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन। ये सब देखकर यही लगता है कि हमेशा उनको ये सब पसंद रहा है, भले ही आलोचकों को लगता था कि वे अमित शाह के साथे में रहेंगे। गौरव के ऐसे क्षणों में, दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद उदास चेहरों को कौन याद करेगा? यदि कागजी शेरों से घिरे प्रधानमंत्री आज शीर्ष पर अकेले दिख रहे हैं तो इसमें उनका भी दोष है। उन्होंने अपनी पार्टी से कभी नहीं कहा कि उन्हें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष डीके बरुआ की नकल के अलावा भी कुछ करना है, जिनका कुख्यात नारा 'इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा' आज भी कई राजनेताओं के लिए एक प्रेरणास्रोत है। वैसे, इंदिरा के सत्ता खोने के बाद बरुआ ने उनका साथ छोड़ दिया था।

समय भारत का है और उसके स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यह बात तमाम दुनिया को नजर आ रही है। कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उनकी निंदा हीनभावना से उत्पन्न हुई है। जब आप कर्म के मामले में कमजोर होने लगते हैं तो निंदा आपके स्वभाव का स्थायी भाव बन जाती है। हरिशंकर परसाई ने लिखा है कि ईर्ष्या-द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के मारे सो नहीं पाता। निरंतर अच्छा काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। हम और आप ऐसा होते हुए देख रहे हैं।

एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोखिम पर जोखिम उठाते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके आसपास के नेता कागजी शेर बनकर बैठे हैं।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गत दिनों राज्यसभा में पूरे फॉर्म में थे। सरकार की किसान समर्थक नीतियों के बारे में आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, 'मैं तथ्य पेश कर रहा हूँ, कोई मन की बात नहीं कह रहा।' उन्होंने विपक्षी दलों के शासन के रिकॉर्ड का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। कई अन्य मंत्रियों ने भी ऐसा ही किया। लेकिन तथ्य कभी कोई मुद्दा था ही नहीं। विशेषज्ञों के बीच आमराय है कि कृषि क्षेत्र में सुधारों की बहुत जरूरत है। लेकिन ये बात दिल्ली की सीमाओं पर इकट्ठा किसानों को तो बताएं! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री वही कर रहे हैं जिनमें वो अच्छे हैं- प्रधानमंत्री की तारीफ करना और विपक्षी दलों पर तीन कृषि कानूनों के बारे में किसानों को गुमराह करने की तोहमत लगाना।

● इन्द्र कुमार

देश की सबसे बड़ी और सबसे अधिक क्षेत्रों में सत्तारूढ़ भाजपा को आगामी दिनों में क्षेत्रीय दलों से जंग लड़नी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल सहित अन्य जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां भाजपा का मुकाबला कांग्रेस के साथ ही क्षेत्रीय दलों से भी होना है। ऐसे में भाजपा क्षेत्रीय दलों को साधने की कोशिश में अभी से जुट गई है। क्योंकि कई दल उसके लिए चुनौती बने हुए हैं।

क्षेत्रीय दलों से जंग का साल?



देश में भाजपा और कांग्रेस की जंग का दौर कुछ राज्यों में ही बचा है। भाजपा का मुकाबला अब क्षेत्रीय पार्टियों से है, जिनकी जड़ें अपने गृह राज्यों में मजबूत हैं। इस साल ऐसे 5 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें भाजपा को कहीं सत्ता बचानी है तो कहीं सत्ता के लिए उसका क्षेत्रीय पार्टियों से सीधा मुकाबला होगा। यानी 2021 में देश की सियासत में कई दलों का ग्राफ परिवर्तन होना तय है। इनमें भाजपा, टीएमसी, कांग्रेस और एआईएडीएमके सहित कई अन्य पार्टियां भी हैं। पश्चिम बंगाल में ममता का किला ढहाने के लिए भाजपा पहले से ही तैयारी कर रही है, तो तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमके की पुरानी जंग के बीच भाजपा के लिए जगह बना पाना आसान नहीं दिख रहा। केरल से भी भाजपा को सकारात्मक संकेत मिलते नहीं दिखाई दे रहे, वहीं असम में सत्ता बचाना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल होगा।

भाजपा असम में सत्ता में है, वाम मोर्चा केरल, एआईएडीएमके तमिलनाडु में है, और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता है। इनमें से प्रत्येक राज्य के चुनाव में अजीबोगरीब विशेषताएं और जटिलताएं भी हैं। असम सीएए, एनआरसी की राजनीति का केंद्र रहा है। खबरों के अनुसार अंतिम एनआरसी सूची में करीब 12 लाख हिंदू और बंगाली लोगों को बाहर रखा गया था? क्या भाजपा के लिए यह मुश्किलें खड़ी कर सकता है? पश्चिम बंगाल ऐसा धुवीकरण देख रहा है, जो पहले कभी नहीं देखा गया। 2019

लोकसभा के दौरान टीएमसी की अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के मुकाबले हिंदू जागृति अब जातिगत स्तर पर है। केरल सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच करीबी मुकाबला देख रहा है। एलडीएफ, स्थानीय निकाय चुनावों में शीर्ष पर उभरकर हर पांच साल में सरकार बदलने की मजबूत प्रवृत्ति को कड़ी चुनौती दे रहा है। तमिलनाडु में वर्षों बाद चुनाव होगा, जिसमें जयललिता और के करुणानिधि नहीं होंगे। एनडीए सहयोगियों के बीच तनाव और कई छोटे दलों की मौजूदगी से चुनाव रोमांचक होगा।

एनडीए असम में मंथन देख रहा है। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, जिसके साथ असम गण परिषद के

साथ भाजपा ने राज्य चुनाव जीता, ने गठबंधन छोड़ दिया है। यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) को एनडीए में बीपीएफ को बदलने की उम्मीद है। कांग्रेस अभी भी मुस्लिम कट्टरपंथी पार्टी एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन को लेकर अनिच्छुक है। एजेपी और रायजोर दल जैसे कुछ क्षेत्रीय दल चुनावों को बहुकोणीय और अधिक दिलचस्प बना सकते हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के निधन से कांग्रेस राज्य में नेतृत्व की कमी से जूझ रही है। फिर भी यह भाजपा के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अंतिम एनआरसी सूची से बाहर होने के कारण इसके मूल हिंदू और बंगाली मतदाताओं में कुछ असंतोष है।

राज्य की असमिया भाषी आबादी को डर है

जेएमएम बंगाल में 30-35 सीटों पर लड़ेगी

झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने ऐलान किया है कि वह बंगाल में पूरे दमखम के साथ इस साल होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद शीबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक दौर की जनसभा भी बंगाल के झारग्राम में कर ली है। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 'हम 30-35 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं।' भट्टाचार्य ने यह भी कहा, 'बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जेएमएम की घोषणा से पूरी तरह तिलमिला गई हैं। ममता ने साफ कहा है कि हेमंत पहले झारखंड संभालें, फिर बंगाल की तरफ देखें।' बता दें कि हेमंत के बंगाल चुनाव में कूदने के बाद ममता बनर्जी काफी दुखी हैं, उन्होंने इस बात का मंच से इजहार भी किया है। ममता ने कहा, 'ये क्या तरीका है। हेमंत सोरेन चले आए, उनको पार्टी का उम्मीदवार चाहिए। नहीं होगा' कैसे होगा। खाना, रहना, ढोल, मांदर हम देंगे, और वो आकर वोट मांगेंगे। जाओ न, पहले झारखंड को संभालो। मैं तो ये बात नहीं कहती, लेकिन मुझे दुख हुआ। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने एक और राजनीतिक प्रतिद्वंदी को जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी हैं। ममता ने कहा, 'आज मुझे दुख पहुंचा। मैंने देखा हेमंत सोरेन हमारे राज्य में पॉलिटिक्स करने आए। उनके शपथग्रहण में मैं गई थी। कितना सपोर्ट किया था।'



कि इस कानून का फायदा मुख्य रूप से बांग्लादेश के अवैध बंगाली हिंदू प्रवासियों को मिलेगा और यह राज्य की भाषाई जनसंख्या को बांग्लाभाषियों के हक में बदल देगा। सीए को लेकर नाराजगी के चलते पिछले साल एक नई राजनीतिक पार्टी असम जातीय परिषद (एजेपी) का जन्म हुआ। एजेपी ने आंचलिक दल के साथ गठबंधन किया है, जो जेल में बंद आरटीआई एक्टिविस्ट अखिल गोगोई ने हाल ही में बनाया है। एजेपी को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) और असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद (एजेवाइसीपी) का समर्थन हासिल है, जो दोनों ही असरदार छात्र संगठन हैं और जिन्होंने अवैध बाशिंदों के खिलाफ छह साल लंबे असम आंदोलन की अगुवाई की थी। यह आंदोलन 1985 में केंद्र और छात्र संगठनों के बीच असम समझौते के साथ खत्म हुआ था।

भाजपा विरोधी वोटों को बंटने से रोकने की गरज से कांग्रेस, एजेपी और आंचलिक दल से महागठबंधन में शामिल होने की अब तक नाकाम अपील करती रही है। विधानसभा की जिन 36 सीटों पर असमिया भाषी लोग नतीजा तय करते हैं, उनमें से चार पर 2016 में कांग्रेस जीती थी। बाकी 32 में 9 सीटें भाजपा-अगप ने 10 फीसदी से भी कम वोटों के अंतर से जीती थीं। अब कांग्रेस इन सीटों पर असमिया लोगों में सीए विरोधी भावनाओं के बूते मौका ताड़ रही है। केरल में हर पांच साल में सरकारों को उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति रही है। चलन के अनुसार अब कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की वापसी की बारी है। हालांकि, सोने की तस्करी मामले, कोविड-19 पर गलतफहमी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद हाल ही में संपन्न स्थानीय निकाय चुनावों में एलडीएफ अग्रणी था। ध्यान देने वाली बात है कि जो पार्टी स्थानीय चुनाव जीतती है, वह सामान्य रूप से विस चुनाव भी जीत जाती है। ओमन चांडी की अनुपस्थिति

असम में अबकी बार त्रिकोणीय मुकाबला

असम में इस साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार राज्य में भाजपा-कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला न होकर त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि राज्य की क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन बना रही हैं। उनका मकसद छोटी पार्टियों के बीच होने वाले वोटों के बंटवारे को रोकना है। सत्ताधारी भाजपा असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तीन वामपंथी दलों के साथ-साथ ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया है। वहीं दो प्रमुख क्षेत्रीय दलों असम जातीय परिषद और रायजोर दल ने ऐलान किया कि वे आगामी चुनाव एक साथ लड़ेंगे। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व नेता लुरिनज्योति गोगोई एजेपी में शामिल हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक और लेखक राजकुमार कल्याणजीत सिंह कहते हैं कि भाजपा भले ही किसी भी गठबंधन के सीधे खतरे को नकार रही है, लेकिन दो क्षेत्रीय दलों के गठबंधन से सावधान भी है।

और केरल कांग्रेस से बाहर निकलने से कांग्रेस कमजोर हुई है। केसी एलडीएफ में शामिल हो गया है। हालांकि स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर घटा है, जबकि यूडीएफ और एलडीएफ लगभग समान रहे। परिवर्तन के लिए राज्य के लोगों का मजबूत दृष्टिकोण अभी भी यूडीएफ के पक्ष में पैमाने को झुका सकता है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व केरल के बजाय पश्चिम बंगाल पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। भाजपा अभी तक सीपीएम के हिंदू वोट बैंक में पैठ नहीं बना पाई है। पार्टी 2026 को लेकर तैयारी कर सकती है। अगर केरल में वामपंथी हार गए, तो 1977 के बाद यह पहली बार होगा, जब देश के किसी राज्य में सत्ता में नहीं होंगे।

पश्चिम बंगाल में मुकाबला भाजपा और टीएमसी के बीच है। पार्टी उसी रणनीति पर दिख रही है, जिस पर चलकर उसने केंद्र में कांग्रेस को लगभग समेट दिया है। इसने टीएमसी के खिलाफ भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण और 'वंशवाद की राजनीति' के गंभीर आरोप लगाए हैं। यह पार्टी को कमजोर करने के लिए विद्रोहियों को अवसर दे रहा है। सुवेंदु अधिकारी के भाजपा में शामिल होने से सियासी फिजा बदलने लगी है। पार्टी ने राज्य चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि उसे सत्ता परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। दूसरी ओर, टीएमसी 10 साल के लंबे शासन के बाद सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है, लेकिन यहां ममता के करिश्मे और विपक्षी मतों में विभाजन से समीकरण दिलचस्प है। राज्य में प्रोजेक्ट करने के लिए भाजपा के पास मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। ऐसे में भाजपा इसे मोदी बनाम ममता का मुकाबला बना सकती है, लेकिन उसे टीएमसी के स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे से जूझना पड़ेगा। वाम मोर्चा और कांग्रेस अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को वाम वोटों का महत्वपूर्ण हिस्सा मिला था। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह खोए हुए समर्थन को हासिल करता है या नहीं। यदि यह अच्छा करता है, तो यह राज्य में भाजपा की संभावनाओं और बंगाल के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में टीएमसी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है।

तमिलनाडु में एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन को डीएमके के नेतृत्व वाले मोर्चे से कड़ी चुनौती मिल रही है। सियासत के कई जानकार डीएमके की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहस सिर्फ अंतर पर है। केरल की तरह तमिलनाडु भी वैकल्पिक पार्टी शासन का गवाह है। 2016 में जयललिता के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके ने लोकलुभावन योजनाएं रखी थीं। जयललिता की मृत्यु, पार्टी के भीतर गुटबाजी और सहयोगी भाजपा के साथ असहज संबंधों के कारण एआईएडीएमके के नेतृत्व में उलझन दिखती है। हालांकि रजनीकांत के चुनाव नहीं लड़ने या चुनावी राजनीति में प्रवेश न करने के फैसले ने दोनों को राहत दी है।

वाम और कांग्रेस सीट वितरण से नाखुश हैं। एमके स्टालिन को भाई एमके अलागिरी से विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। पहले से ही परिवार के सदस्यों के बीच शीत युद्ध चल रहा है, जो पार्टी के सिंहासन का असली उत्तराधिकारी है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि विधानसभा कि इन चुनावों से भाजपा, कांग्रेस सहित कई क्षेत्रीय दलों की सियासत की दशा, दिशा तय होने वाली है। यह मुकाबले रोचक होंगे और सियासत की नई इबारत भी लिखेंगे।

● दिल्ली से रेणु आगाल

अ योध्या में मंदिर पर काम आगे बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ में राम पर राजनीति। राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने राम नाम को लेकर ऐसा आक्रामक रुख अपनाया हुआ है कि भाजपा की ओर से संघ को कमान संभालनी पड़ी। दोनों



दंडकारण्य में राम पर राजनीति

ओर से सधा हुआ सियासी खेल चल रहा है, जबकि विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं। यह सब शुरू हुआ था बीते साल अगस्त में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या में मंदिर का भूमिपूजन कर रहे

थे, ठीक उस समय बघेल सरकार ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के राम सर्किट का एनिमेटेड रूप सार्वजनिक किया। इनमें श्रीडी तस्वीरें जारी करके राम सर्किट का मॉडल दिखाया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट आया था, 'प्रभु श्रीराम के ननिहाल चंद्रखुरी का सौंदर्य अब पौराणिक कथा और नगर जैसा आकर्षक होगा... जय सियाराम!'

दरअसल, रामायण के मुताबिक राम की मां कौशल्या का जन्म आज के छत्तीसगढ़ में हुआ था। भगवान ने 14 वर्ष के वनवास का एक लंबा समय भी छत्तीसगढ़ में ही बिताया। तब दंडकारण्य का हिस्सा था यह इलाका। कांग्रेस ने भाजपा के राम का तोड़ यहीं से निकाला है। बघेल सरकार ने करीब 138 करोड़ रुपए की लागत से राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट तैयार किया है। कोरिया से सुकमा जिले तक कुल 2260 किलोमीटर लंबाई की इस परियोजना में कई दुर्गम भूखंडों को रोड से जोड़ा जाएगा। राम वन गमन पथ के लिए शुरू में 9 जगहें डेवलप की जाएंगी।

सवाल है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस को राम पर नीति और रणनीति क्यों बनानी पड़ रही है? वजह है संघ का राम मंदिर के जरिए घर-घर से जुड़ने का खाका तैयार करना। संघ मंदिर निर्माण के लिए चंदा अभियान के बहाने भाजपा से रूठ गए मतदाताओं तक दोबारा अपनी पहुंच बना रहा है। इसी कड़ी में धार्मिक आयोजनों के माध्यम से गांवों तक राम की झांकियां और भजन-कीर्तन के कार्यक्रम जोरों पर हैं। राम मंदिर चंदा अभियान में पिछड़ी जातियों के नेतृत्व को आगे करके सामाजिक समीकरण भी साधे जा रहे हैं। संघ को पता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को साहू और कुर्मी बहुल क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह बौद्ध बस्तियों में भी दस्तक दे रहा है संघ। वहां नए सिरे से संवाद स्थापित करने की कोशिश चल रही है।

भाजपा की ओर संघ के सामने आने के पीछे

लोकरंग में बसे राम

छत्तीसगढ़ के लोकरंग में बसे राम अब राजनीति की प्रमुख धुरी हैं? इस सवाल पर दोनों पार्टियों के नेता घुमा-फिराकर जवाब देते हुए गेंद दूसरे के पाले में डाल देते हैं। भाजपा की ओर से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहते हैं, भाजपा के लिए राम आस्था का प्रश्न है, न कि राजनीति का। राम मंदिर और राम सेतु पर कांग्रेस की चाल पूरे देश को पता है। आज भले ही वह राम के नाम पर छाती पीट रही हो। अब इसी सवाल पर कांग्रेस की ओर से उसके मीडिया प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी जवाब देते हैं कि भाजपा राम को अपने दल और विचारों में बांधना चाहती है, लेकिन राम तो पूरे देश खासकर छत्तीसगढ़ के आमजीवन में हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने भाजपा की राजनीति को मुंहतोड़ जवाब दिया है।

भी वजह है। छत्तीसगढ़ में पार्टी साल 1992 में पहुंच गई थी। फिलहाल उसके पास न तो नए चेहरे हैं और न ही नया नेतृत्व। संघ को एहसास है कि यहां भाजपा की मौजूदा लीडरशिप को लेकर लोगों में खास उत्साह नहीं। पार्टी नेताओं की कई गतिविधियों पर जनता से ठंडी प्रतिक्रिया मिली। संघ के मोर्चा संभालने का कारण उसकी अपनी रणनीति भी है, जो धीरे-धीरे लेकिन स्थायी बदलाव लेकर आती है।

दूसरी तरफ, प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा के 'राम' से अलग एक नई रणनीति बनाई है। भूपेश बघेल और उनकी टीम राम को 'छत्तीसगढ़ के भांजे' के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। उनकी कोशिश राम की सॉफ्ट इमेज को राज्य की पहचान और अस्मिता से जोड़ना है। इस तरह पार्टी छत्तीसगढ़ की लोक-संस्कृति में रची-बसी राम की मूरत को खुद से जोड़ रही है। कुछ दिनों पहले राज्य के मंत्री शिव डहरिया ने राम की व्याख्या कुछ इस अंदाज में की, 'भगवान राम तो हम कांग्रेसियों के दिलों में बसे हैं। अगर कांग्रेसियों का सीना चीरकर देखेंगे तो भगवान राम दिखेंगे।'

दिसंबर में बघेल सरकार के दो साल पूरे होने पर कांग्रेस ने एक रामयात्रा निकाली। इसमें राम के साथ सीता और लक्ष्मण की भी भव्य प्रतिमाएं रखी गईं। इस दौरान बाइक रैली निकली, रास्तों

पर फूल बरसाए गए, आतिशबाजी हुई। रायपुर के नजदीक चंद्रखुरी गांव में कौशल्या माता के प्राचीन मंदिर पर जब इस यात्रा का समापन हुआ तो मुख्यमंत्री बघेल सहित पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था। इस जगह को कौशल्या की जन्मस्थली मानते हैं। यहां सरकारी कार्यक्रम के दौरान बघेल ने भाजपा पर राम के ननिहाल की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से पूरी जगह को संवारने का संकल्प भी लिया। यह सिलसिला आगे शिवरीनारायण तक पहुंचा। शिवरीनारायण जांजगीर जिले में महानदी, शिवनाथ और जोक नदी के त्रिधारा संगम तट पर बसा एक शहर है। कहा जाता है कि इसी जगह राम ने शबरी के जूटे बेर खाए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद बघेल दर्जनों बार शिवरीनारायण मंदिर जा चुके हैं। राज्य सरकार यहां भगवान राम और शबरी की 32 फुट ऊंची मूर्त बनाने की तैयारी कर रही है। भाजपा का राम प्रेम जगजाहिर है, लेकिन कांग्रेस के इस कदम ने यह संदेश दिया कि पार्टी राम के साथ ही शबरी को भी ऊंचा स्थान देती है। वरिष्ठ पत्रकार बरुण सखा कहते हैं, 'यह एक तीर से दो निशाने लगाने जैसी बात है। इस रणनीति से राम तो सधते ही हैं, प्रदेश में शबरी को मानने वाला समुदाय भी खुश हो जाएगा।'

● रायपुर से टीपी सिंह

राजस्थान में करीब तीन साल बाद यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन, इसके सियासी बुलबुले निकलने शुरू हो गए हैं। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के समर्थकों ने हाल में नया मंच बना डाला जिससे संकेत मिलता है कि पार्टी में 'सबकुछ ठीक नहीं' है। मंच ऐसे समय वजूद में आया, जब जनवरी में 20 जिलों के 90 निकायों के चुनाव और मार्च-अप्रैल में चार विधानसभा सीटों-राजसमंद, सहाड़ा, वल्लभनगर और सुजानगढ़ में उपचुनाव होने थे। इसको पिछले माह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौर सरीखे अन्य नेताओं के साथ लंबी बैठक की। लेकिन, बैठक में वसुंधरा नहीं पहुंचीं। यह इसलिए भी अहम है कि पिछले साल सचिन पायलट के नेतृत्व में गहलोत से बगावत के दौरान भी वसुंधरा राजे ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। फिर, पार्टी नेतृत्व से उनकी अलग राय भी कोई छुपी हुई नहीं है।

नए हालात गौरतलब हैं, क्योंकि हाल में नड्डा की बैठक के अगले दिन ही राजे समर्थकों ने 'वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच' के गठन का ऐलान कर दिया। मंच ने 25 जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो, क्या वसुंधरा बगावत के सुर अख्तियार कर सकती हैं? या फिर यह पार्टी में अपनी दावेदारी मजबूत करने की कवायद है? उनके समर्थक अभी से मांग कर रहे हैं कि वसुंधरा को आगामी चुनाव के लिए बतौर मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। हालांकि राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कहते हैं, 'राज्य में जिस तरह वोटों का जनरेशन बदलता है, उसी तरह नेतृत्व भी बदलना चाहिए। वसुंधरा राजे पार्टी की कददावर नेता हैं और उन्होंने दो बार राज्य की सत्ता संभाली है। हमारे पास बतौर मुख्यमंत्री कई अन्य वरिष्ठ नेता हैं। यह पार्टी की मजबूती है।' **वसुंधरा समर्थक मंच पर पूनिया** कहते हैं, 'जिन लोगों ने यह बनाया है, वे पार्टी के लोग नहीं हैं। उनका कोई जनाधार नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया पर तीर-कमान चल रहे हैं।' हालांकि मंच को लेकर राजे की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल बीते साल दिसंबर में राजे के विरोधी माने जाने वाले पूर्व मंत्री घनश्याम तिवाड़ी की भाजपा में वापसी हुई है। घनश्याम तिवाड़ी ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले राजे से बगावत करके अपनी अलग पार्टी 'भारत वाहिनी' बनाई थी और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

घनश्याम तिवाड़ी कहते हैं, 'अभी जो भी गतिविधियां वसुंधरा और उनके समर्थकों कर रहे हैं, उसे बस में चुपचाप देख रहा हूँ। पार्टी ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। पार्टी के



वसुंधरा की बाजीगरी

प्रधानमंत्री के मन में खटास

वसुंधरा की वापसी को लेकर पार्टी नेतृत्व भी विश्वास की लकीर खींचने को तैयार नहीं है। वसुंधरा का रोचक राजनीतिक रोजानामचा बांच चुके रणनीतिकार अनेक दृष्टांत गिनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से तो राजे के रिश्तों में तब खटास आ गई थी, जब वसुंधरा प्रतिगामी राजनीति की पटरी पर चल पड़ी थी। विश्लेषकों ने तो यहां तक कह दिया था कि वसुंधरा को राज्य की नई गवर्नर का सूत्रधार होना चाहिए था, वह अचानक मोदी मॉडल की सबसे कमजोर कड़ी बन गई हैं। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर रहे ललित मोदी को लेकर पासपोर्ट विवाद ने भाजपा नेतृत्व को कितनी मुश्किलों से दो-चार होना पड़ा था। कहने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे को लेकर पार्टी में सुलग रही आग भी नहीं बुझी है। राजमहल होटल विवाद में भाजपा नेतृत्व को क्या कुछ नहीं भुगतना पड़ा था? कहने की जरूरत नहीं है। अमित शाह तो यहां तक कह चुके थे कि जिस प्रदेश में भाजपा की सरकार हो, वहां मुख्यमंत्री का खास समझा जाने वाला व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, इससे संगठन चौपट हो जाता है। इस सियासी खींचतान में जिस तरह पूनिया की भद्द उड़ी, उसे न तो पूनिया भूलने को तैयार हैं और न ही संघ। वसुंधरा को लेकर संघ के थिंक टैंक की अनेक आशंकाएं हैं। संघ के पदाधिकारियों का मानना है कि वसुंधरा शक्तिपुंज बनकर फिर अधिनायकवाद को बढ़ावा दे सकती हैं। तब भाजपा की रीति-नीति के विरुद्ध एक अटपटा परिदृश्य उभर आएगा। एक आशंका यह भी है कि कालांतर में पार्टी में धृतराष्ट्र, भीष्म और गांधारियों का बोलबाला हो जाएगा, जिसकी परिणति इस परिदृश्य में होगी कि वसुंधरा का आचरण अहसान करने जैसा हो जाएगा कि उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा बहुमत लेकर आई, अन्त्या किसमें इतनी सामर्थ्य थी?

आलाकमान का जो आदेश होगा, वह स्वीकार्य होगा।' हालांकि सतीश पूनिया का मानना है कि अभी यह कहना जल्दीबाजी होगी कि वसुंधरा ने पार्टी से अलग राह पकड़ ली है। आसन्न उपचुनाव सत्तारूढ़ दल कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए आगामी विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। उपचुनाव में भाजपा यह भी दिखाने की कोशिश करेगी कि पार्टी राज्य में वसुंधरा के बिना भी जीत दर्ज कर सकती है। उधर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपनी सियासी पकड़ बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें राजसमंद भाजपा के जबकि सहाड़ा, वल्लभनगर और सुजानगढ़ कांग्रेस के खाते में गई थीं।

फिलहाल 200 सदस्य वाली विधानसभा में भाजपा के 72 विधायकों में 45 से अधिक राजे समर्थक माने जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी प्रसाद पंत मानते हैं कि मौजूदा समय में वसुंधरा के बिना भाजपा राजस्थान में मजबूत स्थिति में नहीं है। उधर, वसुंधरा का पार्टी से अलग रुख जुलाई-अगस्त 2020 में कांग्रेस में सचिन पायलट संकट के दौरान भी दिखा था। उस वक्त वसुंधरा ने बस एक ट्वीट किया था, 'राजस्थान के लोगों को कांग्रेस के संकट की कीमत चुकानी पड़ रही है। पार्टी और भाजपा नेताओं के नाम पर कीचड़ उछालने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है।' इस मसले पर गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा कहते हैं, 'हमारी नजर अभी निकाय चुनाव और उपचुनाव पर है। भाजपा अगले मुख्यमंत्री का सपना देखा छोड़ दे।' देखा होगा कि वसुंधरा का अगला कदम क्या होता है? क्या वे 'अजेय राजस्थान, अजेय भाजपा' के नारों में साथ रहती हैं या अलग राह चुनती हैं?

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

रामजी संवारेंगे काज

कभी राम मंदिर निर्माण के भूमिपूजन तक का विरोध करने वाले और कभी मराठा कार्ड खेलकर अपनी राजनीति चमकाने वाले मनसे प्रमुख राज ठाकरे को अब प्रभु श्रीराम की अयोध्या नगरी याद आई है। बता दें कि अगले महीने मार्च के पहले सप्ताह में राज ठाकरे 'रामलला की शरण' में आ रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बुरी तरह पिछड़ चुके मनसे प्रमुख अब अयोध्या में अपनी राजनीति की नई दिशा तय करने के लिए तैयार हैं। बड़ा सवाल यह है कि 'आखिर रामजी की अयोध्या कितने राजनीतिक दलों और नेताओं की किस्मत चमकाएगी?' भाजपा का उदय अयोध्या में राम मंदिर निर्माण बनाने को लेकर ही हुआ था। पार्टी के नेताओं ने भाजपा को स्थापित करने में 'जय श्रीराम के नारे' का भी खूब सहारा लिया।

यहां हम आपको याद दिला दें, बीती 5 अगस्त को जब उप्र के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन किया जा रहा था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। राम मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमिपूजन पर भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद समेत **तमाम हिंदू संगठनों** और देश की करोड़ों जनता ने हर्षोल्लास व्यक्त किया था और इसे वर्षों बाद आई 'शुभ घड़ी' भी बताया था। लेकिन अयोध्या से 1,512 किलोमीटर दूर मुंबई में बैठे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने ऐतराज जताते हुए कहा था कि, भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को कोराना संकटकाल में मंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन करने की क्या जरूरत थी?

अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी की। भाजपा के बाद शिवसेना भी हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी है। शिवसेना के नेता बद्ध-चढ़कर बयान देते रहे हैं कि अयोध्या में मस्जिद विध्वंस में भाजपा के बराबर ही हमारे शिवसैनिकों की अहम भूमिका रही है। पिछले कुछ वर्षों से शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अयोध्या रामलला की शरण में आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे मौजूदा समय में महाराष्ट्र की सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या पहुंचकर उद्धव ठाकरे ने रामलला से आशीर्वाद लिया था। भाजपा-शिवसेना के नेता दबी जुबान से मानते रहे हैं कि उनकी राजनीति चमकाने में अयोध्या का बड़ा हाथ रहा है।

शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की उंगली पकड़कर सियासत सीखने वाले राज ठाकरे महाराष्ट्र में अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भाजपा और शिवसेना की तर्ज पर अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी अपने कदम आगे बढ़ाना



मराठा कार्ड के साथ खेला 'भगवा कार्ड'

आपको बता दें, पिछले साल जनवरी में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का चौरंगी झंडा बदलकर 'भगवा रंग' दिया और शिवाजी की मुहर को अपनाया था। राज ठाकरे ने मंच पर सावरकर की फोटो सजाकर हिंदुत्व की दिशा में कदम बढ़ाने के मंसूबे जाहिर करते हुए कहा था कि ये वो झंडा था, जो पार्टी की स्थापना करते वक्त उनके मन में था और हिंदुत्व उनके डीएनए में है। पार्टी के झंडे के बदलाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि राज ठाकरे अब हिंदुत्व विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होने लगे हैं। गौरतलब है कि शिवसेना हिंदुत्व की राजनीति पर चलने वाली भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सियासत में लंबे समय तक कदमताल करती रही। 25 सालों तक दोनों पार्टियों का साथ वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद टूट गया। राज ठाकरे अब इस कोशिश में हैं कि शिवसेना के कांग्रेसी खेमे में जाने के बाद खाली हुई हिंदुत्व की भरपाई को वो भर सकें। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी वैचारिक विरोधी मानी जाने वाली कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर सत्ता की कमान अपने हाथों में ले ली है। जिसके बाद से भाजपा लगातार शिवसेना पर हिंदुत्व के मुद्दे से किनारा कर लेने का आरोप लगाती आ रही है। ऐसे में मौके की नजाकत को भांपते हुए हिंदुत्व के नारे के साथ राज ठाकरे भाजपा से कुछ समझौता करने में लगे हुए हैं, कुछ दिन पहले ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से गुप्त मुलाकात भी की थी।

चाहती है यानी राज ठाकरे अब 'हिंदुत्व विचारधारा' को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। राज ठाकरे पहली बार अयोध्या अपनी राजनीति के लिए नई दिशा तलाशने जा रहे हैं। मनसे प्रमुख ठाकरे भले ही रामलला के दर्शन करने अयोध्या आ रहे हों, लेकिन पार्टी उनके इस दौरे की जिस तरह से सार्वजनिक घोषणा कर रही है। इससे जाहिर होता कि ये उनका महज धार्मिक दौरा नहीं होगा बल्कि पार्टी एक सियासी संदेश देने की कोशिश भी कर रही है, ऐसा संदेश जो पार्टी की हिंदुत्व की छवि को मजबूत करे, क्योंकि राज ठाकरे को 'मराठी मानुष' की छवि के दम पर सियासत की बुलंदी को छूने में अभी तक सफलता नहीं मिली।

बता दें कि 9 मार्च 2006 को राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी, अगले महीने मनसे को 15 साल पूरे होने जा रहे हैं। जब राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बनाई थी तब वे शिवसेना से अलग दिखना चाहते थे। उन्होंने हिंदुत्ववादी विचारधारा को प्राथमिकता न देते हुए महाराष्ट्र के क्षेत्रीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस रखा। उस समय राज ठाकरे कहते फिरते थे कि 'मुझे मराठी मानुष से ही मतलब है।' हालांकि शुरुआती दिनों में राज ठाकरे राजनीति में सफल भी हुए थे। अपने पहले ही विधानसभा चुनाव यानी साल 2009 में राज ठाकरे ने 13 सीटें जीतकर दिखा दिया था कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में पार्टी सत्ता पर काबिज हो सकती है? लेकिन कुछ फैसले गलत क्या हुए कि उनकी पार्टी की नींव हिलने लगी। इसके बाद साल 2014 के विधानसभा चुनाव में मनसे ने 220 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उसे सिर्फ एक सीट मिली।

● बिन्दु माथुर

उप्र के पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपना अस्तित्व खो चुकी राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) को किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आंसू संजीवनी बन गए हैं। उन्हें उम्मीद जगी है कि वे फिर से अपनी साख जमा लेंगे। राजनीति के पुराने खिलाड़ी माने जाने वाले अजित सिंह चौधरी को तुरंत आभास हो गया कि यह केवल राकेश टिकैत के आंसू नहीं बल्कि हमारी खोई हुई सियासत को चमकाने के लिए एक मौका आया है।

फिर क्या था जयंत चौधरी ने तत्काल राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) मुखिया का राकेश टिकैत के साथ मंत्रणा करते हुए और दिल्ली में किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए ट्वीट कर दिया। यही नहीं अजित सिंह के निर्देश पर जयंत चौधरी तो तत्काल प्रभाव से गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर टिकैत के साथ फोटो भी खिंचा आए। उसके बाद वहां से सीधे मुजफ्फरनगर किसानों की महापंचायत में भी पहुंच गए। इस दौरान जयंत चौधरी को भी लगने लगा कि उप्र में सियासत चमकाने के लिए इससे अच्छा मौका और कोई हाथ नहीं लगेगा क्योंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल भी शुरू हो चुकी है। गत दिनों मुजफ्फरनगर में पांच घंटे चली महापंचायत में हजारों किसानों के बीच रालोद के उपाध्यक्ष जयंत ने किसानों के बीच घड़ियाली आंसू बहाकर अपनी सियासत को सक्रिय बनाने के लिए ऐलान भी कर डाला। बता दें कि यह पंचायत राकेश टिकैत के बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बुलाई थी लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चेहरा जयंत चौधरी ने अपना चमकाया।

आपको बता दें, आज से 4 साल पहले 2017 के उप्र विधानसभा चुनाव के दौरान अजित सिंह और जयंत चौधरी की सियासत काफी पीछे रह गई थी और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) से जनता का भी मोहभंग हो गया था। इस चुनाव में उप्र की 403 विधानसभा सीटों में से रालोद केवल एक सीट ही जीत पाई थी, साथ ही अजित सिंह के ग्रह जनपद बागपत और उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत आसपास जाट बेल्ट में राष्ट्रीय लोक दल का जनाधार भी बुरी तरह घट गया। उसके बाद वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इनकी करारी हार हुई और रालोद का एक भी प्रत्याशी जीतने में सफल नहीं हो सका, यही नहीं अजित के साथ जयंत भी अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हो सके।

इस तरह पिछले उप्र विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बाद 'रालोद का सियासी मार्केट ठंडा' पड़ा हुआ था। अगले वर्ष होने वाले उप्र विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा

आंसू बने संजीवनी



महापंचायत से बदलेगी तस्वीर

एक प्रसिद्ध कहावत है, 'ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजाई गई ताली की गूंज भी दूर तक सुनाई देती है।' ऐसा ही गत दिनों मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में हुआ। जब रालोद और चौधरी अजित सिंह ने किसानों का खुलकर समर्थन किया तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने भी अजित और रालोद के समर्थन में आकर भाजपा के लिए वोट न देने की सौगंध भी खाली। नरेश टिकैत ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है। हम इसी में रहकर अपना काम करेंगे। टिकैत ने किसानों को भाजपा से संभलकर रहने की सलाह दी। भाकियू अध्यक्ष ने कहा कि अजित सिंह को लोकसभा चुनाव में हराकर बड़ी भूल की है, हम भी दोषी हैं। उन्होंने मौजूद हजारों किसानों से कहा कि आगे से इस प्रकार की गलती मत करना, इस परिवार ने हमेशा किसान के मान-सम्मान की लड़ाई लड़ी है। इस बीच 'नरेश टिकैत ने महेंद्र सिंह टिकैत के साथ अजित सिंह के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी याद किया, उन्होंने कहा कि आगे से साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। नरेश टिकैत ने किसानों से वादा करते हुए कहा कि उनकी एक और गलती भाजपा पर भरोसा करना है। आने वाले दिनों में वह अपनी यह गलती सुधारेंगे। नरेश टिकैत ने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा को सबक सिखाया जाएगा।'

के साथ सपा, बसपा और कांग्रेस ने भी अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी ओर उप्र में अपना खोया हुआ जनाधार बढ़ाने के लिए अजित और जयंत मौके की तलाश में थे। रालोद प्रदेश की सियासत में सक्रियता बढ़ाने के लिए करवटें तो ले रहा था लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। इधर कृषि कानूनों के विरोध में जाटलैंड यानी पश्चिम उप्र के किसान राकेश टिकैत के नेतृत्व दिल्ली बॉर्डर पर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन को दो महीने बीत जाने के बाद भी दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के बीच रालोद के ये नेता अपनी पैठ नहीं बना पा रहे थे। इसी बीच जब कुछ संगठन और कई किसान नेता आंदोलन को छोड़कर जाने लगे और दुखी राकेश टिकैत की रुलाई फूट पड़ी तो इस मौके को भुनाने में चौधरी बंधुओं ने तनिक भी देर नहीं लगाई।

दिल्ली में किसानों के आंदोलन को धार देने

के लिए नरेश टिकैत के द्वारा मुजफ्फरनगर में बुलाई गई महापंचायत में सबसे अधिक रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ही सक्रिय दिखाई दे रहे थे। जयंत ने हजारों किसानों के बीच मोदी और योगी सरकार को ललकारने में ज्यादा फोकस रखा। इस दौरान जयंत चौधरी ने गंगाजल और नमक गिराकर स्टेज से बयान देते हुए कहा कि, 'मेरा प्रस्ताव ये है कि भाजपा के नेताओं का हुक्का-पानी बंद करना पड़ेगा।' उसके बाद जयंत ने अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए अपना भावनात्मक सियासी दांव भी चल दिया। रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा, 'पुरानी बातों को भूल जाओ। पहले चूक गए थे, आगे से मत चूकना। युवाओं की ओर इशारा करते हुए जयंत ने कहा अपनी गलती मान लो। किसान भगवान का रूप है और वह सड़क पर है। केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी है।'

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

भाजपा ने पहले मग्न के बाद अब बिहार के जरिए यह साफ संकेत दिया है कि उसकी मंशा राज्यों में पुराने चेहरों की जगह नए नेतृत्व को आगे लाने की है। मग्न में कई दिग्गज राजनेता शिवराज सरकार में जगह पाने में नाकाम रहे थे। वहीं, बिहार में भाजपा ने सबसे पहले सुशील कुमार मोदी को प्रदेश की सियासत से हटाकर केंद्र की राजनीति में लाने का काम किया है। साथ ही अब भाजपा ने डॉ. प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव जैसे नेताओं को कैबिनेट में शामिल नहीं किया है।

बिहार में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद प्रदेश में जो स्थिति सामने आई है, उससे यह बात तो साफ हो गई है कि भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा ने यह संकेत दे दिया है कि बिहार में पार्टी नया नेतृत्व खड़ा करने में जुटी हुई है। यानी पार्टी में युवाओं को अधिक महत्व दिया जाएगा, जिसकी तस्वीर मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिली है।

भाजपा ने पहले मग्न के बाद अब बिहार के जरिए यह साफ संकेत दिया है कि उसकी मंशा राज्यों में पुराने चेहरों की जगह नए नेतृत्व को आगे लाने की है। मग्न में कई दिग्गज राजनेता शिवराज सरकार में जगह पाने में नाकाम रहे थे। वहीं, बिहार में भाजपा ने सबसे पहले सुशील कुमार मोदी को प्रदेश की सियासत से हटाकर केंद्र की राजनीति में लाने का काम किया है। साथ ही अब भाजपा ने डॉ. प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव जैसे नेताओं को कैबिनेट में शामिल नहीं किया है।

बिहार में करीब महीनेभर चली रस्साकसी के बाद गत दिनों नीतीश कैबिनेट में 17 चेहरों को शामिल कर लिया गया, जिनमें भाजपा कोटे से 9 और जेडीयू कोटे से 8 मंत्री बने हैं। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में अब कुल 31 सदस्य हो गए हैं जबकि 5 मंत्रियों के पद अभी भी खाली हैं। बिहार में भाजपा की जगह पहली बार जेडीयू के बड़े भाई की भूमिका में मंत्रिमंडल में भी हो गई है। भाजपा कोटे से कुल 16 मंत्री हो गए हैं जबकि जेडीयू से मुख्यमंत्री सहित कुल 13 मंत्री हैं। इसके अलावा वीआईपी और हम से एक-एक मंत्री हैं।

बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में युवाओं को खास तवज्जो मिली है। भाजपा ने ज्यादातर युवाओं को मंत्री बनाकर ये साफ कर दिया है कि पार्टी नई पीढ़ी के नेताओं को आगे करना चाहती है। लंबे समय तक प्रदेश में भाजपा युवा मोर्चा की कमान संभाल चुके नितिन नवीन को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, तो सहरसा से युवा विधायक आलोक

बिहार में नया नेतृत्व खड़ा करने में जुटी भाजपा



मग्न में आजमाया गया फॉर्मूला

भाजपा ने राज्यों में पुराने चेहरों के बदलाव के फॉर्मूले को सबसे पहले मग्न से शुरू किया था। पिछले साल जुलाई महीने में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान भाजपा ने अपने पुराने और दिग्गज नेताओं को मंत्री बनाने की बजाय नए चेहरों को तवज्जो दी थी। हालांकि, राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाना पार्टी की मजबूरी थी, जिसके चलते उनके करीब एक दर्जन नेताओं को मंत्री बनाया गया। इसके बावजूद भाजपा ने प्रदेश में नया नेतृत्व तैयार करने की दिशा में मजबूती से कदम आगे बढ़ाया था और पार्टी ने 9 नए चेहरों को जगह दी थी। वहीं, गौरशंकर बिसेन, पारस जैन, राजेंद्र शुक्ला, संजय पाठक, जालम सिंह पटेल जैसे कई दिग्गज मंत्री बनने में नाकाम रहे थे। भाजपा के इस कदम से प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में असंतोष दिख रहा है। उधर, प्रदेश के युवा नेता इस बात से खुश हैं कि पार्टी में देर से ही सही युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है। भाजपा के इस कदम का प्रदेश की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, यह आगामी दिनों में साफ हो जाएगा।

रंजन झा को कैबिनेट में शामिल किया गया है। एमएलसी सम्राट चौधरी को भी मंत्री बनाया गया है, तो वहीं गोपालगंज से जनक राम मंत्रिमंडल में नया चेहरा होंगे। जनक राम पार्टी का दलित

चेहरा हैं। इसके अलावा भाजपा ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज कुमार सिंह बबलू और शाहनवाज हुसैन को भी मंत्रिमंडल में जगह दी है। इससे पहले भाजपा ने जिन सात मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया था, उनमें से चार पहली बार मंत्री बने हैं, तारकिशोर प्रसाद तो सीधे उपमुख्यमंत्री बने।

बिहार में पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी, डॉ. प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव भाजपा की पहली पंक्ति के नेता ही नहीं हैं बल्कि भाजपा का राज्य में चेहरा भी माने जाते थे। भाजपा ने चुनाव के बाद सरकार गठन के दौरान सबसे पहले सुशील मोदी को बिहार की राजनीति से हटाकर राज्यसभा सदस्य बनाया और केंद्र की

राजनीति में ले आई। इसके बाद भाजपा ने अपने कई दिग्गज नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी है, जिनमें डॉ. प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव, विनोद नारायण झा, रामनारायण मंडल और राणा रणधीर जैसे नाम शामिल हैं।

गया नगर सीट से लगातार सातवीं बार जीते डॉ. प्रेम कुमार 2005 से ही नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे। इस बार उन्हें भाजपा ने मंत्री नहीं बनाया है जबकि पिछली बार कृषि मंत्री थे। इसी तरह पटना साहिब से छठी बार जीते विधायक नंदकिशोर यादव को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। पिछली सरकार में इन्होंने पथ निर्माण व स्वास्थ्य महकमे की कमान संभाल रखी थी। वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा पिछली सरकार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री थे, लेकिन इस बार भाजपा ने उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी है। साल 2000 में पहली बार विधायक बने थे और नीतीश की पिछली सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं। पिछली सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रहे बांका सीट से चार बार विधायक राम नारायण मंडल को भी इस बार मंत्री पद नहीं मिल सका है। मधुबन से विधायक राणा रणधीर भी मंत्री नहीं बनाए गए हैं जबकि पिछली बार एनडीए सरकार में सहकारिता मंत्री थे।

● विनोद बक्सरी

भारत और नेपाल के रिश्तों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार रहा है। दोनों देशों के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है और वो रिश्ता आज भी कायम है।

लेकिन इधर कुछ समय से दोनों देशों के बीच रिश्ते अपने निचले स्तर पर रहे हैं, हालांकि अब उसमें सुधार दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल का रुख भारत को लेकर कड़ा हुआ और एक तरह से यह नजर आया कि नेपाल की मौजूदा ओली सरकार का झुकाव चीन की तरफ है।

रोटी-बेटी का रिश्ता



भारत-नेपाल संबंधों का रहा है ऐतिहासिक आधार

भारत के साथ नेपाल के संबंधों में खटास से पहले दोनों देश एक धागे से बंधे हुए थे। जब नेपाल में राजतंत्र था तो उस समय भी रिश्ते बहुत अच्छे थे। नेपाल में जब लोकतंत्र को लाने की लड़ाई चल रही थी तो वाम दलों की तरफ से यह नारा बुलंद किया गया कि भारत को राजतंत्र का समर्थक है, यह बात अलग है भारत ने साफ कर दिया था कि नेपाल के आंतरिक मामले में दखल देने का सवाल ही नहीं। इस तरह से भारतीय शासन सत्ता ने अपनी नीयत साफ कर दी। लेकिन भौगोलिक तौर बफर स्टेट होने की वजह से चीन की तरफ से यह चाल चली गई। भारत और नेपाल के बीच तात्कालिक विवाद कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को नेपाली नदशे में दिखाने पर बढ़ गया। भारतीय पक्ष ने साफ कर दिया कि ओली सरकार जिस तरह से तनाव को बढ़ा रही है वो सही नहीं है, हालांकि इसके साथ ही भारत की तरफ से संतुलित बयान दिया गया। दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के नाम पर ओली सरकार ने अपने कदम को जायज करार दिया और नेपाल के ज्यादातर दलों के बीच और कोई विकल्प था। यह बात अलग है कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में विवाद बढ़ गया।

दरअसल भारत-नेपाल संबंधों का एक दौर वसंत के खिलते फूलों की तरह रहा है, जो पिछले कुछ दशकों में मुरझा से गए हैं। मजबूत दोस्ती के दौर वाले वर्ष 1950 में भारत और नेपाल के बीच मैत्री संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और नेपाल की ओर से शासक वीरेंद्र विक्रम शाह ने दस्तखत किए गए। इसने हिमालय की गोद में बसे छोटे देश को चीन की साम्राज्यवादी नीति से सुरक्षा प्रदान की। लैंडलॉकड यानी चारों तरफ भूमि से घिरे देश को आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए राह प्रदान की गई। साथ ही भारत की वरीयता में पड़ोसी राष्ट्र की सुरक्षा और चीन का खतरा अहम था, इसलिए वह इस पर ही नजर रखे रहा कि नेपाल भारतीय हित के विपरीत कोई कार्य न करे। इसके बावजूद संधि का एक बिंदु नेपाल को खटकने लगा कि वह बिना भारतीय अनुमति के विदेशों से हथियार की खरीद नहीं करेगा।

पिछली सदी के नौवें दशक में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान नेपाल ने संधि की परवाह न कर दूसरे देशों से हथियार खरीदने शुरू कर दिए। ऐसे में राजीव सरकार ने नेपाल के जरूरी सामान मंगाने वाले रास्तों को रोक पेट्रोलियम आपूर्ति को बंद कर दिया। वहां जरूरी सामान की किल्लत हो गई। ऐसे में विदेशी इशारे पर चलने वाले नेपाली राजनेताओं के एक वर्ग ने जनता को भारत विरोध के लिए उकसाना शुरू कर दिया। चीन को यहां से पूरा मौका मिल गया। हालांकि इस दौर में नेपाली राजशाही के भारत से नजदीकी संबंधों के चलते रिश्ते की इमारत ऊपर से तो सलामत बची रही, लेकिन आंतरिक रूप से दरारें पड़ गईं। नेपाल नरेश वीरेंद्र की मौत के बाद राजशाही की जड़ें कमजोर हो गईं। चीन ने वहां माओवादियों की मदद बढ़ाकर राजशाही के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। जनता की ओर से भी लोकतंत्र की मांग तेजी से उठने लगी। भारतीय रणनीतिकार एक लोकतांत्रिक देश से ज्यादा मजबूत रिश्तों की सोचकर लोकतंत्र के समर्थन में आगे बढ़ गए। परंतु इससे भारतीय हितों की रक्षा नहीं हो सकी। लोकतांत्रिक चुनावों

के बाद सत्ता कम्युनिस्टों के हाथ में पहुंच गई। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल यानी प्रचंड के पहले ही कदम से उनका रुख भी जाहिर हो गया। पूर्व में जहां कोई भी नेपाली प्रधानमंत्री पहले भारत की यात्रा करता था, वहीं प्रचंड पहले चीन गए। यह भारत के लिए एक झटका था। चीन के दबाव में प्रचंड भारतीय हितों की परवाह न कर उसके बड़े निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देते रहे। परंतु चीन मदद के दांव चलता है तो उसमें भी घात होता है। उसने श्रीलंका की तरह ही नेपाल को भी कर्ज के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। उस दौर में भारत बहुत कुछ कर पाने में समर्थ नहीं था और यह स्थिति अब तक कायम है। ऐसे में भारत के लिए अब उम्मीद की किरण दिख रही है।

कम्युनिस्ट पार्टी में केपी ओली और प्रचंड के अलग होने के बाद एक बार फिर राजशाही की मांग उठ रही है, तो नेपाल की जनता का एक धड़ा इस बात से भी नाराज है कि चीन राजनीतिक हस्तक्षेप कर हदों को पार कर गया है। ऐसे में भारत को नेपाली कांग्रेस की मजबूती पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं कम्युनिस्टों में प्रचंड को भी अपने पाले में लाने की जरूरत है। भारत में पढ़ाई के चलते उनकी भावनाएं यहां से जुड़ाव रखती हैं। साथ ही केपी ओली के प्रति चीन के झुकाव के चलते उनका इस ओर बढ़ना थोड़ा आसान भी होगा। भारत को नेपाल में निचले स्तर

पर भी संबंध मजबूती का काम करना चाहिए। चीन नेपालियों को मंदारिन भाषा पढ़ाने के लिए बड़ा बजट प्रदान करता है। भारत की ओर से हिंदी के लिए भी ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। नेपालियों और भारतीयों के बीच रोटी-बेटी के रिश्तों पर भी तेजी से काम करने की जरूरत है। भारत में सेना और नौकरियों में स्थान पाने वाले नेपाली जब वापस नेपाल पहुंचें तो हमारे राजदूत की तरह काम करें, इसके लिए उन्हें तैयार करने को भी कदम बढ़ाने चाहिए।

नेपाल में बड़ी संख्या में बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। भारत वहां के प्रतिभाशाली बच्चों की सहायता कर एक रास्ता खोल सकता है। दरअसल ये बच्चे नेपाल में आगे चलकर अहम पदों पर काबिज होंगे, तो भारत के प्रति उनके मन में स्वाभाविक झुकाव होगा। भारत को इस मौके को भुनाना चाहिए। कूटनीति के अन्य प्रयासों के बीच सॉफ्ट कूटनीति को तेज करना चाहिए। भारत-नेपाल के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आदान-प्रदान हों। नेपाल में यह संदेश भी पहुंचना चाहिए कि चीन नेपाल को श्रीलंका की तरह ऋण जाल में फंसाकर उसकी जमीन पर अधिकार कायम करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इससे वहां भारत के प्रति सकारात्मक भाव बना रहेगा।

● ऋतेन्द्र माथुर

अमेरिका में जो बाइडेन युग का आगाज हो गया है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश में इस सत्ता परिवर्तन के बाद भारत में भी दोनों देशों के संभावित रिश्तों को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं। कमला हैरिस के रूप में भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति बनना भारत के लिए एक सकारात्मक संदेश है। लेकिन अमेरिकी कैबिनेट में भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा से जुड़े लोगों को न लेना बाइडेन की भारत के प्रति आगे की नीतियों को काफी हद तक स्पष्ट करता है। लेकिन क्या बाइडेन चीन के साथ ट्रंप प्रशासन जैसा ही रुख रखेंगे या फिर कोई बदलाव करेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। संभावना यही है कि चीन को रोकने के लिए बाइडेन भारत के साथ साझेदारी रखेंगे। चीन के साथ भारत का सीमा तनाव अभी बना हुआ है, ऐसे में अमेरिका की भूमिका भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा अमेरिका भारतीयों, खासकर युवाओं को लेकर क्या नीति रखता है? यह भी बहुत अहम मुद्दा है।

सन् 1998 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और भारत के पोखरण में परमाणु परीक्षण से अमेरिका में नाराजगी थी। जो बाइडेन तब प्रमुख डेमोक्रेट नेताओं में शामिल थे। उस समय उन्होंने भारत का पक्ष लिया था। यही नहीं सन् 2006 में जब भारत का अमेरिका से ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ, तब भी भारत को विशेष अहमियत देने वाला ड्राफ्ट, उस समय उपराष्ट्रपति बाइडेन ने ही तैयार किया था। लेकिन भारत के सबसे बड़े गैर-राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दुनिया की सबसे बड़ी और भारत की केंद्रीय सत्ता में विराजमान भाजपा से जुड़े लोगों को बाइडेन का अपनी कैबिनेट में शामिल न करना भी एक बड़ी बात है। इससे कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि बाइडेन भारत के प्रति तो झुकाव रखते हैं, लेकिन वह भारत की वर्तमान राजनीति और मुख्य राजनीतिक पार्टी से खुश नहीं हैं। अब जबकि बाइडेन राष्ट्रपति बन गए हैं, तब उनका यह रुख बहुत मायने रखता है। क्योंकि बाइडेन का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका से बेहतर निजी रिश्तों के दावों को भी पलीता है। यह भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि चीन के साथ उनके प्रशासनिक रिश्ते कैसे होंगे? बाइडेन अभी तक भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा का समर्थन करते रहे हैं। संभावना है कि भारत-अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों में भविष्य में और मजबूती आएगी।

भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका से रक्षा संबंध हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, ट्रंप के जाने और बाइडेन के सत्ता संभालने के बावजूद दोनों देशों के रक्षा संबंधों पर असर की संभावना



बाइडेन-हैरिस का अमेरिका

कई फैसले पलटें

अमेरिका की सत्ता हाथ में आते ही बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पेरिस जलवायु समझौते और अमेरिका में मुस्लिम ट्रेवल बैन को खत्म करने जैसे फैसले पलट दिए। नए राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में अमेरिका की फिर से वापसी के लिए उस पर हस्ताक्षर कर दिए। बाइडेन ने पेरिस जलवायु समझौते में दोबारा शामिल होने का ऐलान करते हुए कहा कि देश की जनता से चुनाव के दौरान उन्होंने इसका वादा किया था। इसके अलावा बाइडेन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग तेज करने के इरादे से महामारी कोरोना वायरस को रोकने के एक फैसले पर दस्तखत किए। इस आदेश के मुताबिक, उन्होंने मास्क को और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य कर दिया है। बाइडेन ने अमेरिका में ट्रंप द्वारा कुछ मुस्लिम देशों और अफ्रीकी देशों के आवागमन पर रोक लगाने जैसे फैसलों को पलटते हुए इस प्रतिबंध को खत्म कर दिया है। बाइडेन ने मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने के ट्रंप के फैसले को भी पलट दिया और इसके लिए फंडिंग भी रोक दी। इस फैसले के बाद मैक्सिको ने बाइडेन की प्रशंसा की। इतना ही नहीं, जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद कीस्टोन एक्सप्लोडेशन के विस्तार पर भी रोक लगाने के आदेश पर दस्तखत किए हैं।

लगभग न के बराबर है। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच दोनों देशों में ड्रोन से लेकर एंटी एयर मिसाइल जैसे हथियारों की खरीद को लेकर बातचीत की जमीन तैयार हो रही है। दोनों देश पहले ही रक्षा और रणनीति क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जता चुके हैं। चुनाव के समय

अमेरिका की घरेलू राजनीति ऐसी थी कि भारत, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप के बहुत करीब माना जाता था। हालांकि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद भी घरेलू राजनीति का दोनों देशों के संबंधों पर खास असर पड़ने की संभावना नहीं है।

हाल के महीनों में 2+2 स्तर बातचीत ने दोनों देशों के बीच सहयोग की नई कड़ी शुरू की है। बाइडेन की टीम के सदस्य कर्ट कैम्पबेल, एंथनी ब्लिंकेन, मिशेल फ्लोरनी आदि को भारत के प्रति काफी सकारात्मक रुख रखने वाला माना जाता है। चीन से सीमा तनाव के दौरान ट्रंप के भारत के समर्थन में दिखने से चीन भी काफी खफा रहा था। देखना होगा कि बाइडेन का इसे लेकर क्या रुख रहता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि बाइडेन प्रशासन की चीन को लेकर तलखी ट्रंप के समय जैसी न रहे। ट्रंप की तरह बाइडेन के सार्वजनिक मंचों से चीन को कोसने की संभावना बहुत कम दिखती है।

बाइडेन प्रशासन में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, जो दोनों देशों के बीच रिश्ते निभाने में बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। इसके अलावा बाइडेन की टीम में भारतीय मूल के 20 अमेरिकियों को जगह मिली है। इसे बहुत महत्वपूर्ण कहा जाएगा। वैसे बाइडेन के पद ग्रहण से पहले अमेरिका के भावी रक्षामंत्री जनरल (अवकाश प्राप्त) लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि चीन पहले ही क्षेत्रीय प्रभुत्वकारी शक्ति बन चुका है और अब उसका लक्ष्य नियंत्रणकारी विश्वशक्ति बनने का है। उन्होंने क्षेत्र और दुनियाभर में चीन के डराने-धमकाने वाले व्यवहार का उल्लेख करते हुए अमेरिकी सांसदों से ये बातें कहीं।

● कुमार विनोद

वै श्विक स्तर पर लोगों को जोड़ने वाली इंटरनेट की दुनिया में भारतीय महिलाएं काफी पीछे हैं। डिजिटल इंडिया के दौर में हर मुट्ठी में स्मार्टफोन और सस्ते डेटा की उपलब्धता के बावजूद आधी आबादी की पहुंच इंटरनेट तक नहीं है। यह विचारणीय पहलू है कि जागरूकता, जुड़ाव, विचार-विमर्श और पल-पल की सूचनाओं से जोड़ने वाले साइबर संसार में भारत की महिलाएं आखिर क्यों पूरी तरह से मौजूदगी दर्ज नहीं करवा पाई हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2019-20 में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या काफी कम है। देश के सत्रह राज्यों और पांच केंद्रशासित प्रदेशों में इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर हुआ सर्वेक्षण बताता है कि दस राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों में औसतन हर दस में से छह महिलाओं ने अपने जीवन में इंटरनेट का इस्तेमाल कभी नहीं किया।

इंटरनेट की दुनिया में मौजूदगी से जुड़ी ऐसी विसंगति भरी स्थिति बिहार से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात जैसे प्रांतों तक में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में औसतन हर दस में से लगभग चार महिलाओं और गुजरात में औसतन हर दस में से तीन महिलाओं ने इंटरनेट का इस्तेमाल कभी नहीं किया। बिहार में तो हालात हैरान करने वाले हैं, जहां दस में से आठ महिलाएं डिजिटल दुनिया से दूर हैं। खासतौर से ग्रामीण महिलाएं इंटरनेट इस्तेमाल करने में काफी पीछे हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएमएआई) की बीते साल की रिपोर्ट 'इंडिया इंटरनेट 2019' बताती है कि भारत में इंटरनेट उपयोग की बढ़ती रफ्तार के बावजूद इंटरनेट उपयोग के मामले में लैंगिक स्तर पर काफी असमानता है। इस रिपोर्ट में सामने आया था कि देश में जहां 25.8 करोड़ पुरुष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, वहीं महिलाओं की संख्या इसके मुकाबले आधी है।

भारत में 67 फीसदी पुरुषों के मुकाबले केवल 43 फीसदी महिलाएं ही इंटरनेट उपयोग करती हैं। शहरी क्षेत्रों में 62 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 38 प्रतिशत महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में 72 फीसदी पुरुषों की तुलना में महज 28



डिजिटल युग की महिलाएं

प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 की रिपोर्ट के ताजा आंकड़े भी इंटरनेट प्रयोग में महिलाओं की कम भागीदारी की पुष्टि करते हैं। सर्वेक्षण में शामिल प्रदेशों और केंद्रशासित प्रदेशों की फेहरिस्त में आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे राज्य हैं जिनमें 40 प्रतिशत से कम महिलाओं ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया है।

भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनमें इंटरनेट उपयोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इंटरनेट उपयोग करने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहला स्थान चीन का है। बावजूद इसके भारत के इंटरनेट उपयोक्ताओं में महिलाओं का आंकड़ा काफी कम है। देश के बारह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 60 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने इंटरनेट का कभी इस्तेमाल नहीं किया। डिजिटल दुनिया में भारतीय महिलाओं की इतनी कम

मौजूदगी कई तरह के विचारणीय प्रश्नों को जन्म देती है। हाल के वर्षों में महिलाओं में साक्षरता ही नहीं, उच्च शिक्षा का आंकड़ा भी बढ़ा है। देश में महिलाओं की औसत साक्षरता दर 87 फीसदी है। ऐसे में इंटरनेट के प्रयोग से जुड़ी यह संख्या महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को भी सामने रखती है। सर्वेक्षण के अनुसार जिन राज्यों में महिलाएं इंटरनेट का प्रयोग कम करती हैं, वहां पर महिला साक्षरता दर भी कम है। इसका सीधा-सा अर्थ यह है कि शिक्षा और इंटरनेट के इस्तेमाल के बीच भी सीधा संबंध है। बिहार में महिलाओं की औसत साक्षरता दर केवल 57 फीसदी है और इंटरनेट इस्तेमाल करने में यहां की महिलाएं अन्य राज्यों की तुलना में काफी पीछे हैं। सर्वेक्षण में बताया गया है कि जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 40 फीसदी से कम महिलाओं ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, उनमें बिहार 20.6 फीसदी के साथ आखिरी पायदान पर है, जबकि 48 फीसदी उपयोग के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर है।

महिलाओं और पुरुषों के बीच मौजूद इस अंतर के पीछे कई सामाजिक-पारिवारिक कारण भी हैं, जिनके चलते इंटरनेट की दुनिया तक महिलाओं की पहुंच कम है। भारत में घर-बाहर दोनों मोर्चों पर जद्दोजहद में जुटी महिलाओं की प्राथमिकताएं पुरुषों से काफी अलग हैं। ग्रामीण महिलाओं में डिजिटल साक्षरता की कमी और शहरी महिलाओं का साइबर उत्पीड़न, उन्हें इस दुनिया से दूर करता है।

● ज्योत्सना अनूप यादव

महिलाओं और बेटियों को शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी योजनाओं और

डिजिटल दुनिया में महिलाओं का पीछे रहना चिंतनीय

संस्थानों की जानकारीयां डिजिटल माध्यमों के जरिए हासिल करने में आसानी होती है। यह संपर्क और सूचनाओं का सहज और त्वरित माध्यम है। यही वजह है कि इस डिजिटल दुनिया में महिलाओं का पीछे रहना चिंतनीय है। कहना गलत नहीं होगा कि सूचनाओं और सजगता के इस दौर में इंटरनेट एक साथी की तरह है, जो लोगों को दुनिया से जोड़े रखता है। खबरों की पहुंच और ख़ैरियत लेने-देने का सक्रिय जरिया बनता है। सूचनाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाता है। 'इंडिया इंटरनेट 2019' के मुताबिक पिछले साल देश में

उपयोक्ताओं की संख्या पर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था कि पुरुषों के मुकाबले इंटरनेट इस्तेमाल में महिलाएं काफी पीछे हैं। यही वजह है कि ग्रामीण भारत में डिजिटल दुनिया में लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए इंटरनेट साथी प्रोग्राम के तहत इंटरनेट इस्तेमाल के लिए महिलाओं को शिक्षित करने की शुरुआत की गई थी। डिजिटल रूप से साक्षर महिलाएं अपने समुदाय और आसपास के गांवों की अन्य महिलाओं को प्रशिक्षित करती हैं।

श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत के हित के लिए गोकुल, वृंदावन को ही नहीं छोड़ा बल्कि उन्होंने अपनी सबसे प्रिय बांसुरी और उससे भी प्रिय राधा को भी छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अधर्म के साम्राज्य को ध्वस्त करना था। श्रीकृष्ण का संपूर्ण जीवन अधर्म के विरुद्ध एक युद्ध था और उनके उस जीवन का अंतिम युद्ध महाभारत था। आओ जानते हैं क्या कहती है कृष्ण नीति। महाभारत काल से आज तक युद्ध के मैदान और खेल बदलते रहे लेकिन युद्ध में जिस तरह से छल-कपट का खेल चलता आया है, उसी तरह का खेल आज भी जारी है। ऐसे में सत्य को हर मोर्चों पर कई बार हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर बार सत्य के साथ कोई कृष्ण साथ देने के लिए नहीं होते हैं। ऐसे में श्रीकृष्ण की नीति को समझना जरूरी है।

श्रीकृष्ण ने कहा था कि कुल या कुटुम्ब से बढ़कर देश है और देश से बढ़कर धर्म, धर्म का नाश होने से देश और कुल का भी नाश हो जाता है। जब कुरुक्षेत्र में धर्मयुद्ध का प्रारंभ हुआ तो युधिष्ठिर दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर कहते हैं कि मैं जहां खड़ा हूँ उसके नीचे एक ऐसी रेखा है जो धर्म और अधर्म को बांटती है। निश्चित ही एक ओर धर्म और दूसरी ओर अधर्म है। दोनों ओर धर्म या अधर्म नहीं हो सकता। अतः जो भी यह समझता है कि हमारी ओर धर्म है वह हमारी ओर आ जाए और जो यह समझता है कि हमारे शत्रु पक्ष की ओर धर्म है तो वह उधर चला जाए क्योंकि यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन किधर है। युद्ध प्रारंभ होने से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन किसकी ओर है? कौन शत्रु और कौन मित्र है? इससे युद्ध में किसी भी प्रकार की गफलत नहीं होती है। लेकिन फिर भी यह देखा गया था कि ऐसे कई योद्धा थे, जो विरोधी खेमे में होकर भीतरघात का काम करते थे। ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी होता है।

भीष्म ने युद्ध के कुछ नियम बनाए थे। श्रीकृष्ण ने युद्ध के नियमों का तब तक पालन किया, जब तक कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर उसे युद्ध के नियमों के विरुद्ध निर्ममता से मार नहीं दिया गया। अभिमन्यु श्रीकृष्ण का भांजा था। श्रीकृष्ण ने तब ही तय कर लिया था कि अब युद्ध में किसी भी प्रकार के नियमों को नहीं मानना है। इससे यह सिद्ध हुआ कि कोई भी वचन, संधि या समझौता अटल नहीं होता। यदि

श्रीकृष्ण की नीतियां राजनीति में कारगर



उससे राष्ट्र का, धर्म का, सत्य का अहित हो रहा हो तो उसे तोड़ देना ही चाहिए। भगवान श्रीकृष्ण ने अस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़कर धर्म की ही रक्षा की थी।

जब दुश्मन शक्तिशाली हो तो उससे सीधे लड़ाई लड़ने की बजाय कूटनीति से लड़ना चाहिए। भगवान श्रीकृष्ण ने कालयवन और जरासंध के साथ यही किया था। उन्होंने कालयवन को मुचुकुंद के हाथों मरवा दिया था, तो जरासंध को भीम के हाथों। ये दोनों ही योद्धा सबसे शक्तिशाली थे लेकिन कृष्ण ने इन्हें युद्ध के पूर्व ही निपटा दिया था। दरअसल, सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता। खासतौर पर तब जब आपके विरोधियों का पलड़ा भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाएं।

युद्ध में संख्या बल महत्व नहीं रखता, बल्कि साहस, नीति और सही समय पर सही अस्त्र एवं व्यक्ति का उपयोग करना ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। पांडवों की संख्या कम थी लेकिन कृष्ण की नीति के चलते वे जीत गए। उन्होंने घटोत्कच को युद्ध में तभी उतारा, जब उसकी जरूरत थी।

उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके कारण ही कर्ण को अपना अचूक अस्त्र अमोघास्त्र चलाना पड़ा जिसे वह अर्जुन पर चलाना चाहता था। जो राजा या सेनापति अपने एक-एक सैनिक को भी राजा समझकर उसकी जान की रक्षा करता है, जीत उसकी सुनिश्चित होती है। एक-एक सैनिक की जिंदगी अमूल्य है। अर्जुन सहित पांचों पांडवों ने अपने साथ लड़ रहे सभी योद्धाओं को समय-समय पर बचाया है। जब वे देखते थे कि हमारे किसी योद्धा या सैनिक पर विरोधी पक्ष का कोई योद्धा या सैनिक भारी पड़ रहा है तो वे उसके पास उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते थे।

जब आपको दुश्मन को मारने का मौका मिल रहा है, तो उसे तुरंत ही मार दो। यदि वह बच गया तो निश्चित ही आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा या हो सकता है कि वह आपकी हार का कारण भी बन जाए। अतः कोई भी दुश्मन किसी भी हालत में बचकर न जाने पाए। श्रीकृष्ण ने द्रोण और कर्ण के साथ यही किया था। जो निष्पक्ष हैं, तटस्थ या दोनों ओर हैं इतिहास उनका भी अपराध लिखेगा। दरअसल वह व्यक्ति ही सही है, जो धर्म, सत्य और न्याय के साथ है। निष्पक्ष, तटस्थ या जो दोनों ओर है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस भयंकर युद्ध के बीच भी श्रीकृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। यह सबसे

अद्भुत था। कहने का तात्पर्य यह कि भले ही जीवन के किसी भी मोर्चे पर व्यक्ति युद्ध लड़ रहा हो लेकिन उसे ज्ञान, सत्संग और प्रवचन को सुनते रहना चाहिए। यह मोटिवेशन के लिए जरूरी है। इससे व्यक्ति को अपने मूल लक्ष्य का ध्यान रहता है। भगवान श्रीकृष्ण ने जिस तरह युद्ध को अच्छे से मैनेज किया था, उसी तरह उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को भी मैनेज किया था। उन्होंने हर एक प्लान मैनेज किया था। यह संभव हुआ अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने, योजना बनाने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से। मतलब यह कि यदि आपके पास 5, 10 या 15 साल का कोई प्लान नहीं है, तो आपकी सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। श्रीकृष्ण सिखाते हैं कि संकट के समय या सफलता न मिलने पर साहस नहीं खोना चाहिए। इसकी बजाय असफलता या हार के कारणों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना करें। एक बार भय को जीत लिया तो फिर जीत आपके कदमों में होगी।

● ओम

मौन



रू पवती, गुणवती, सुशील और चंचल अदाओं से परिपूर्ण स्नेहा को देखते ही मयंक ने शादी के लिए हां कर दी। सारी बातें हो जाने के बाद बात दहेज पर आकर अटक गई। मयंक के घर वालों ने शादी में मोटी रकम के साथ ही गाड़ी की भी मांग स्नेहा के पिताजी से कर दी। स्नेहा के पिता ने उनकी मांग के अनुसार व्यवस्था कर दी पर फिर भी मयंक के घर वालों का मन खुश नहीं था। शादी के बाद स्नेहा अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा पर

अचानक से उसके ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। उसके ससुराल वाले बात-बात पर उसके साथ अत्याचार करने लगे। पहले तो स्नेहा ने इसका विरोध किया पर जब विरोध ना कर पाई तो धीरे-धीरे उसे अपनी किस्मत मानकर मौन सी हो गई। अब कोई उसके साथ कुछ भी करे वह कोई प्रतिउत्तर नहीं देती। वह अलहड़, चंचल अदाओं से परिपूर्ण स्नेहा जैसे मर गई हो और उसका पुनर्जन्म हो गया।

- रीता तिवारी रीत

देहदान



सु भाष बाबू ने अपने देहदान की घोषणा कर दी। उन्होंने घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर कर देहदान की सारी कार्यवाही पूरी कर ली थी। उनके घर वाले हैरान परेशान थे कि पता नहीं बाबूजी को क्या हो गया। अभी तो वे भले चंगे एकदम स्वस्थ हैं फिर उमर भी अभी नहीं हुई है। अभी तो पचास ही पार हुई है।

पत्नी ने पूछा, क्यों जी, बैठे-ठाले तुम्हें क्या सूझी कि देहदान का फार्म भर आए? क्या हुआ तुम्हें? कोई बीमारी वगैरह तो तुम्हें नहीं है। फिर अचानक से यह क्यों? मुझे तो सच में बड़ी घबराहट हो रही है।

पत्नी की बातें सुनकर सुभाष बाबू ने बड़े धैर्य के साथ शांत स्वर से कहा, अरे भागवान! घबराने वाली कोई बात नहीं है। हजारों लोग अपना देहदान कर रहे हैं। बस मेरा भी मन किया।

पत्नी ने कहा, नहीं जी, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। बताइए न?

सुभाष बाबू ने रंधे गले से कहा, आजकल के बेटे-बहु का बर्ताव बुजुर्गों के प्रति कैसा है। यह किसी से छुपा नहीं है। हमारा बेटा तो अभी बड़ा

आज्ञाकारी है। अभी तक का जीवन ईश्वर की कृपा से सुखद रहा पर आगे बुढ़ापा कैसे रहेगा क्या पता? तुम्हें पता है? फ्लैट नंबर छपन में रहने वाले वर्मा जी के बेटे विदेश में बस गए। पत्नी तो काफी साल पहले ही दुनिया छोड़कर चली गई है। बेचारे अकेले रहते थे। उन्होंने अपने देहदान की घोषणा इसलिए की थी ताकि क्रियाकर्म, अंतिम संस्कार वगैरह का कोई झंझट ही न हो। वे बेटों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे।

तभी उनकी बात सुन रहे बेटे ने रुआंसे स्वर से कहा, पापा, आपकी सोच अपने स्थान पर सही है पर सभी अंगुलियां एक जैसी नहीं होतीं। आपने भी दादा जी की बड़ी सेवा की है। मैं यह बचपन से देखता आया हूँ। पहले आप दादा जी को भोजन करवाते थे और बाद में आप भोजन करते थे। पितृ भक्ति तो मैंने आप ही से सीखी है। आपने अपना कर्तव्य निभाया। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों की सेवा-शुश्रूषा करूँ। आप निश्चित रहिए।

बेटे की बात सुनकर सुभाष बाबू को लगा कि अभी भी 'श्रवण कुमार' जिंदा है।

- डॉ. शैल चन्द्रा

आओ हे सुकुमार



बीत रहा ये जीवन प्रतिपल,
सूर्य उदित होता ए प्रतिदिन।
मेरी रातें बीते दिन गिन,
अब तक दिखी न किरण कोई।
नहीं सुनी कोई कंठ कोकिला,
हुआ नहीं आभास गति का,
जो जीवन देगा तार।

आओ हे सुकुमार...

घर का मेरे आंगन सूना,
जीवन मांगे चंद्र खिलौना।
खेले ओ पर हम खेलाएं,
कठपुतली सा नाच नचाएं।

जिसकी मृदुल मुकुंद हंसी संग,
पाऊं मैं तिमिर से पार।

आओ हे सुकुमार...

हृदय प्रेम अब कहीं गुप्त है,
संबंधों में स्नेह लुप्त है।
तेरे आने के विलम्ब से,
जीवन राग वसंत सुप्त है।
काल चक्र की द्रुत गति से,
यह जीवन ना जाए हार।

आओ हे सुकुमार...

प्रतिक्षण कल्पित दिवास्वप्न की,
बूंद-बूंद जुड़ लहर बने जब।
करूँ प्रतीक्षा नव प्रभात की,
होगा उदित नवल-नीरज कब।
कब बोले वह कंठ कोकिला,
हो परिपूर्ण नीड़ मेरा तब।
तभी तीव्र पीड़ा के लहू से,
हुआ स्वप्न यह तार-तार।

आओ हे सुकुमार...

- महिमा तिवारी

भारत में सांप्रदायिकता एक ऐसी चीज है, जिसके लपेटे में कोई न कोई गाहे-बगाहे आते ही रहता है। उत्तराखंड टीम के पूर्व कोच और इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाज वसीम जाफर इन दिनों सांप्रदायिकता के आरोप झेल रहे हैं। कहा जा रहा है कि वसीम जाफर ने उत्तराखंड की टीम का 'राम भक्त हनुमान की जय' का नारा बदलवा दिया। जाफर पर बायो-बल के नियम तोड़ने और खिलाड़ियों का चयन धर्म के आधार पर करने के भी आरोप लगे। ये सब कुछ तब हो रहा है, जब वसीम जाफर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जाफर का इस्तीफा इन आरोपों के लगाए जाने की सबसे बड़ी वजह है।

वसीम जाफर ने अपने इस्तीफे में टीम चयन में चयनकर्ताओं और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अधिकारियों के दखल की बात कही और इसी के बाद आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया। जाफर को एक 'अघोषित मजबूरी' की वजह से इन आरोपों का खंडन करने के लिए सामने भी आना पड़ा। सीएयू ने कोच वसीम जाफर और कप्तान इकबाल अब्दुल्ला सहित कुछ खिलाड़ियों को नमाज अदा कराने की वजह से बायो बल टूटने की रिपोर्ट तलब की है। मामले पर सबकी अपनी डफली और अपना राग है। लेकिन, इस मामले पर सवाल उठ रहा है कि किसी पर भी सांप्रदायिक होने के आरोप लगा देना कितना जायज है?

हमारे देश में दूसरों पर आरोप लगाना बहुत ही सरल और सहज है। आरोप इतने प्यार से लगाए जाते हैं कि लोग मना भी नहीं कर पाते हैं। विश्वास न हो रहा हो, तो महाराष्ट्र की ओर रुख कर लीजिए। कांग्रेस ने भारत रत्नों पर भाजपा के दबाव में ट्वीट करने के आरोप लगाए थे। साथ ही इन लोगों को उद्धव सरकार की ओर से सुरक्षा मुहैया कराने की बात भी कह दी थी। सोचिए कितनी विचित्र स्थिति में होंगे हमारे भारत रत्न? खैर, देश की एकता को लेकर बात करना जब जांच के दायरे में आ सकता है। वसीम जाफर ने तो सीधे-सीधे सिस्टम पर ही सवाल उठा दिए हैं। ये तो अच्छा हुआ कि उन पर केवल सांप्रदायिक होने के आरोप लग रहे हैं। देश के माहौल पर गौर करेंगे, तो कई और चीजें हो सकने की आशंका से आपका मन घिर जाएगा।

वसीम जाफर इस्तीफे को लेकर दिए गए अपने कारणों पर कायम हैं। हालांकि, जाफर ने ये स्वीकार किया कि टीम स्लोगन को लेकर उन्होंने अपनी एक राय रखी थी। लेकिन, उन्होंने इसे किसी पर जबरदस्ती थोपा नहीं था। जाफर का मानना था कि उत्तराखंड के लिए खेल रहे खिलाड़ी किसी एक संप्रदाय का नहीं प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। खिलाड़ियों को उनकी बात

क्रिकेट का कोई धर्म नहीं!



सही लगी और इसे मान लिया गया। इस बात के लिए वसीम जाफर पर आरोप लगाना निहायत ही बचकाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ऐसे ही नहीं कहा था कि ना खेलब ना खेले देब, खेलवे बिगाड़ब। दरअसल, भारत में कुछ ऐसे लोग हैं, जो प्रगति नहीं करना ही नहीं चाहते हैं। आप लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन घूम-फिरकर वो सांप्रदायिकता को बीच में ले ही आते हैं।

वसीम जाफर ने अपने इस्तीफे में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों पर टीम चयन में दखल देने की बात कही थी। इसके बाद वो अचानक से मजहबी तौर-तरीके अपनाने वाले घोषित कर दिए गए। उन पर चौतरफा आरोपों की बौछार होने लगी। आरोप लगाने वाले वही थे, जिनके बारे में वसीम जाफर ने इस्तीफे में जिक्र किया था। ऐसे में इन आरोपों के क्या मायने रह जाते हैं। अपनी छवि को बचाने के लिए सीएयू के ये अधिकारी अपनी हदों को तोड़ते हुए एक अच्छे खिलाड़ी रहे जाफर पर बहुत ही घटिया आरोप लगा रहे हैं। सीएयू के वर्तमान आदेश के हिसाब से कोच और खिलाड़ियों द्वारा बायो बल तोड़ने की जांच होगी। अन्य आरोपों पर सीएयू ने कुछ नहीं कहा है। ऐसे में इसे सीधे तौर पर किसी की छवि को खराब करने के लिए कुछ भी आरोप लगा देने की मानसिकता क्यों न माना जाए?

बायो बल तोड़कर नमाज पढ़ने के आरोप भी वसीम पर लगे हैं। सीएयू इसी मामले पर जांच भी करेगा। बायो बल तोड़ने पर वसीम

जाफर ने कहा कि कप्तान इकबाल अब्दुल्ला ने इसके लिए मुझसे पूछा था। मैंने उन्हें टीम मैनेजर से बात करने को कहा था। इस पर अब्दुल्ला ने परमीशन मिलने की बात कहकर मौलवियों को बुलाया था। मैंने इसे लेकर कोई परमीशन नहीं दी थी और न किसी को बुलाया था। इस पर जांच होगी, तो हो सकता है कि शायद कप्तान इकबाल अब्दुल्ला ही बायो बल तोड़ने के जिम्मेदार निकलें। ऐसे में वसीम जाफर पर मजहबी होने का आरोप लगाना सीधे तौर पर दबाव बनाने की कोशिश करना ही नजर आता है।

वसीम जाफर ने खुद पर लगाए गए आरोपों को कम्युनल एंगल देने के आरोपों को बहुत ही दुखद बताया है। उन्होंने इसे सांप्रदायिक रंग देने की वजह से ही आरोपों पर सफाई देने की बात कही। वसीम जाफर को जानने वाले लोगों ने भी इसे लेकर उनका बचाव किया है। खैर, अब लोगों को विश्वास है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले वसीम जाफर इस दबाव को अच्छे से हैंडल कर ले जाएंगे। इस पिच पर भी जाफर कलाईयों का बेहतरीन उपयोग करते हुए कवर ड्राइव पर एक शानदार चौका लगाते हुए दिखेंगे। लेकिन, सवाल जस का तस है कि केवल मुस्लिम होने पर आप कैसे किसी भी व्यक्ति पर सांप्रदायिक होने का आरोप थोप सकते हैं। फिर चाहे वो देश के लिए क्रिकेट खेला हो, बॉलीवुड में अभिनय करता हो या देश की सीमाओं की चौकसी में लगा हो।

● आशीष नेमा



राजीव कपूर नहीं रहे... शादी के 2 साल बाद ही हो गया था तलाक, अकेले ही कटा जीवन

ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का 9 फरवरी को निधन हो गया। वे 58 साल के थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजीव को हार्ट अटैक आया था, जिसके तुरंत बाद उनके बड़े भाई रणधीर कपूर उन्हें चेम्बूर के इनलाक्स हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजीव का अंतिम संस्कार कर दिया गया जिसमें ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर ने उन्हें मुखाम्बिनी दी। राजीव की कोई संतान नहीं थी। वह अकेले ही जीवन गुजार रहे थे। दरअसल, राजीव की पर्सनल लाइफ काफी उतार-चढ़ाव भरी रही।

2 साल टिकी शादी... राजीव ने 2001 में आर्किटेक्ट आरती सभरवाल से शादी की थी। शादी के बाद आरती और राजीव सामंजस्य नहीं बिटा पाए और दो साल में ही 2003 में उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद आरती ने अपना बेस कनाडा शिफ्ट कर लिया। वहीं, राजीव ने तलाक के बाद दूसरी शादी नहीं की और अकेले ही रहे। राजीव कपूर ने यूं तो 1983 में आई फिल्म एक जान है हम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। लेकिन उनके कैरियर ने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। राजीव ने लवर बॉय, हम तो चले परदेस, अंगारे, शुकिया जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन वे बॉलीवुड में अपनी पहचान नहीं बना पाए।



टीना मुनीम से अफेयर के शक में ऋषि कपूर को पीटने पहुंच गए थे संजय दत्त

बॉ लीवुड एक्ट्रेस टीना मुनीम 64 साल की हो चुकी हैं। 11 फरवरी, 1957 को मुंबई की एक गुजराती फैमिली में जन्मीं टीना 9 बहनों में सबसे छोटी हैं। टीना बचपन से ही ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा बनना चाहती थीं। उन्हें शुरू से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था। महज 21 साल की उम्र में फिल्म देस परदेस से बॉलीवुड कैरियर की शुरुआत करने वाली टीना ने कई हिट फिल्मों में काम किया। हालांकि टीना फिल्मों से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहीं। खासकर संजय दत्त से उनका अफेयर काफी चर्चा में रहा था।



पजेसिव संजू ने गुलशन ग़ोवर के साथ मिलकर ऋषि को पीटने का प्लान बनाया। संजय दत्त जब नशे में ऋषि कपूर के घर की ओर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में नीतू सिंह मिलीं। नीतू के कहने पर संजय ने अपने शक को जाहिर किया। नीतू ने बताया कि टीना और ऋषि सिर्फ दोस्त हैं, उनके बीच और कोई रिश्ता नहीं है। नीतू सिंह के कई बार समझाने के बाद संजय दत्त ने ऋषि कपूर को पीटने की जिद छोड़ी थी।

दरअसल 1981 में रॉकी की रिलीज से पहले 1980 में ऋषि कपूर की कर्ज रिलीज हुई थी। दोनों फिल्मों में टीना मुनीम ही एक्ट्रेस थीं। संजय दत्त को शक हो गया था कि ऋषि और टीना का अफेयर चल रहा है, जिसके चलते टीना के लिए

खलनायक के किरदार की वजह से असल में प्राण से नफरत करने लगे थे लोग

इ स इलाके में नए आए हो बरखुरदार, वर्ना यहां शेर खान को कौन नहीं जानता! अपनी फिल्मों में न जाने कितने ही ऐसे दमदार और उम्दा डायलॉग बोलने वाले प्राण की 12 फरवरी को बर्थ-एनिवर्सरी है। अगर आज वह जिंदा होते तो अपना 101वां जन्मदिन मना रहे होते। कहते हैं कि एक खलनायक की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगता है कि लोग उससे कितनी नफरत करते हैं।



प्राण अभिनय में तो उम्दा थे ही, इस पैमाने पर भी खरे उतरते हैं। प्राण के द्वारा निभाए गए खलनायकों के किरदार के चलते लोग उन्हें सड़कों पर गालियां देते थे। एक समय में लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना तक बंद कर दिया था। प्राण ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था- उपकार से पहले सड़क पर मुझे देखकर लोग अरे बदमाश, ओ लफंगे, ओ गुंडे कहा करते थे। मुझ पर फब्तियां कसते। उन दिनों

जब मैं परदे पर आता था तो बच्चे अपनी मां की गोद में दुबक जाया करते थे और मां की साड़ी में मुंह छुपा लेते। रुंआसे होकर पूछते- मम्मी गया वो, क्या अब हम अपनी आंखें खोल लें। 12 फरवरी, 1920 को एक सरकारी ठेकेदार लाला केवल कृष्ण सिंघद के घर दिल्ली में पैदा हुए प्राण 12 जुलाई, 2013 को हिंदी सिनेमा को 400 से भी ज्यादा फिल्मों का तोहफा देकर इस दुनिया से चले गए।

6

हमने कहा- ठीक है, इस शब्द का पुराने कवियों ने चमत्कार पैदा करने के लिए बहुत प्रयोग किया है। सारंग के 70 अर्थ होते हैं लेकिन यह कोई अच्छी बात नहीं है। इससे कनफ्यूजन होता है। सारंग मतलब कबूतर भी और बाज भी, सूरज भी चांद भी, विष्णु भी और शिव भी, अब कोई कहे सारंग ने सारंग को मार दिया तो क्या अर्थ लगाओगे?



सावन के अंधे को...

रात को कुछ देर तक जागना हो गया सो सुबह आलस के मारे अलसाए से रजाई में पड़े थे कि दरवाजे पर इस अंदाज में दस्तक हुई जैसे कि किसी सरकार की नीतियों से असहमत बुद्धिजीवी के दरवाजे पर पुलिस देती है। इस अधिकार से किसी ने हांक लगाई जैसे मंदिर के लिए चंदा मांगने वाले लगाते हैं।

कमलं भाभी, क्या मास्टर कमलं घर पर है? पत्नी से बैठे-बैठे की प्रतिप्रश्न किया- कौन है?

आवाज ने उत्तर दिया- कमलं।

हमने भी लेटे-लेटे ही उत्तर दिया- यह तो सूफी बोध कथा हो गई- बाहर कौन है? वही जो अंदर बोल रहा है। अंदर भी कमलं और बाहर भी कमलं।

बोला- पहले दरवाजा तो खोल। यह क्या सरकार और किसानों के संवाद वाला नाटक कर रहा है। जैसे मोदी जी दिल्ली में हैं लेकिन बात के लिए भेज रहे हैं तोमर को।

जैसे ही तोताराम अंदर आया हमने कहा- यह क्या तुलसीदास की तरह 'कंज लोचन, कंज पद, कर कंजारुण' लगा रखी है। सामान्य भाषा में बात क्यों नहीं करता?

बोला- ये सब ज्ञान की बातें हैं तुझ जैसे माया-मोह में लिपटे प्राणी को समझ नहीं आएंगी। तू जो बता रहा है वह कंज कमल है। और कर, पद तथा लोचन के उपमान के रूप में आ रहा है जबकि मैं जो 'कमलं' बोल रहा हूँ उसमें कमलं बार-बार आ रहा है लेकिन हर बार

उसके अर्थ अलग-अलग हैं। जैसे वह प्रसिद्ध दोहा सुना कि नहीं-

सारंग ले सारंग चल्थो, कर सारंग की ओट।
इसी तरह आगे भी है।

हमने कहा- ठीक है, इस शब्द का पुराने कवियों ने चमत्कार पैदा करने के लिए बहुत प्रयोग किया है। सारंग के 70 अर्थ होते हैं लेकिन यह कोई अच्छी बात नहीं है। इससे कनफ्यूजन होता है। सारंग मतलब कबूतर भी और बाज भी, सूरज भी चांद भी, विष्णु भी और शिव भी, अब कोई कहे सारंग ने सारंग को मार दिया तो क्या अर्थ लगाओगे? शिव ने विष्णु को मार दिया या कबूतर ने बाज को मार दिया। जो शब्द जिसके लिए चला आ रहा है उसे उसी के लिए रहने देने में क्या परेशानी है?

बोला- मैं क्या करूँ? यह तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि अब से 'ड्रेगन फ्रूट' को 'कमलं' कहा जाएगा।

हमने कहा- लगता है, ये चीन से डरे हुए हैं। चीन के मंजे को तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, अब ड्रेगन नाम से भी डर लगने लगा। मोदी जी ने अपने बचपन में क्या बिना 'चीनी' की चाय बेची थी?

बोला- यह सब भाजपा नेतृत्व को मक्खन लगाने के घटिया और बचकाने तरीके हैं। कल

को इस प्रकार की भाषा हो जाएगी- कमलं ने रात को सोते समय कमलं के साथ दो चम्मच कमलं खाया जिससे सुबह उसका कमलं अच्छी तरह से साफ हो गया।

हमने कहा- इसी को कहते हैं भाजपा के अंधे को कमलं ही कमलं।

बोला- यदि इस सारे मामले की व्यंजना समझ लेगा तो तुझे भी लगेगा कि रूपाणी जी ने बहुत ऊंची बात कही है। ड्रेगन फ्रूट एक बार फल देना शुरू कर देता है तो पच्चीस साल तक कुछ करने की जरूरत नहीं। मजे से फल खाते रहो। इसी तरह जब यह फल एक बार कमलं हो गया तो 25 साल के लिए गद्दी पक्की।

हमने कहा- जैसे मोदी जी ने जब मोरिंगा (सहजन) के परांठे खाने की बात कही तब लाखों लोगों ने मोरिंगा सर्च किया वैसे ही अब दो-चार दिन लोग ड्रेगन फ्रूट को सर्च करेंगे। उसके बाद सब नार्मल। ड्रेगन फ्रूट से चमत्कृत होने की जरूरत नहीं है। यह अपने राजस्थान में खेतों की बाड़ पर वैसे ही उग आने वाला एक प्रकार का केकटस है जिन्हें अपनी बोली में 'थोर' कहते हैं। दिखने में फूल बहुत सुंदर दिखते हैं लेकिन पौधा होता बड़ा सूगला (लीचड़) है। इसे कोई जानवर भी नहीं खाता। लोग इसे जहरीला मानते हैं।

रूपाणी के कहने से कोई भाजपा की कृपा प्राप्त करने के लिए खा जाए तो बात और है।

बोला- समस्त देश 'कमलं' बनाने के लिए जनता का नाम 'कीचड़मं' कर देना चाहिए।

● विनय कुमार तिवारी

PRISM[®]
CEMENT

प्रिज़्म चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.



दूर की सोच[®]

Toll free: 1800-3000-1444

Email: cement.customerservice@prismjohnson.in



**For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us**

Science House Medicals Pvt.Ltd.

**17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak
Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023**

GST. No. : 23AAPCS9224G1Z5 ☎ PH. : +91-0755-4241102, 4257687

✉ Email : shbpl@rediffmail.com Fax : +91-0755-4257687

